चौथी दुनिया

हिंदी का पहला साप्ताहिक अख़बार

www.chauthiduniya.com

दागी, दबंग और पिटे मोहरों पर दांव

पेज-4

मुसलमान दलितों से भी पिछड़े हैं

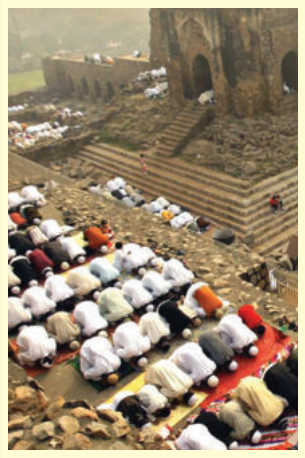

पेज-5

जीने का हक़ मत छीनो

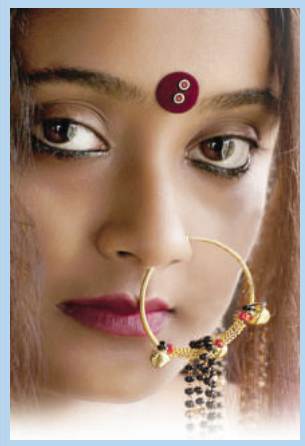

पेज-7

साईं की महिमा

पेज-12

1986 से प्रकाशित | दिल्ली, 12 सितंबर-18 सितंबर 2011 | मूल्य 5 रुपये

राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के बिना

यह प्रजातंत्र अधूरा है

सभी फोटो-*प्रभात पाण्डेय*

ऐसा क्यों होता है कि सरकार जितनी भी योजनाएं बनाती है, उनका फ़ायदा सिर्फ़ 5 फ़ीसदी लोगों को मिलता है. यह कैसा प्रजातंत्र है, जिसमें ग़रीब किसानों की ज़मीनें छीनकर बड़े-बड़े भूमाफ़ियाओं और बिल्डरों को करोड़ों रुपये कमाने दिया जाता है. यह कौन सी लोकतांत्रिक मर्यादा है, जिसमें सरकार उद्योगपतियों को करों में छूट दे देती है और ग़रीब किसानों को मिलने वाली सब्सिडी में कटौती कर देती है. यह कैसा जनतंत्र है, जहां का आम नागरिक ज़िंदगी जीने के लिए ज़द्दोजहद कर रहा है और शहरों में रहने वाले चंद लोग विकास की रोशनी में जगमगा रहे हैं. यह कैसा लोकतंत्र है, जहां सांसद और विधायक जनता के प्रति ज़िम्मेदार न होकर पार्टी के प्रति वफ़ादारी को ही अपना राजनीतिक कर्तव्य मानते हैं. लोकतंत्र के रहनुमाओं को यह कैसा घमंड है कि जनता सड़कों पर है, लेकिन वे बातें किसी तानाशाह की तरह करते हैं. देश में एक नई स्थिति पैदा हुई है. एक आशा जगी है. अगर प्रजातंत्र में लोगों का विश्वास बनाए रखना है तो राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट क़ानून बनाना होगा. साथ ही विधायिका में व्हिप और चुनावों में निजी धन के इस्तेमाल को पूरी तरह ख़त्म करना होगा.

मनीष कुमार

अन्ना हजारे मूल बातें कहते हैं, इसलिए बड़े-बड़े विद्वान उनसे बहस नहीं कर सकते. सांसद सेवक हैं और देश की जनता मालिक है. अगर सेवक मालिक की बात न माने तो मालिक को यह हक़ है कि वह उसे बाहर कर दे. यही दलील अन्ना हजारे की है. देश को भ्रष्ट सांसदों से छुटकारा दिलाने के लिए राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट की मांग लेकर अन्ना हजारे और उनकी टीम आंदोलन करने वाली है. सांसदों को समय से पहले बर्ख़ास्त और चुनाव में उम्मीदवारों को ख़ारिज करने के अधिकार के लिए अन्ना हजारे आंदोलन करने वाले हैं. सरकार भी इन मांगों को लेकर चिंतित है. आने वाले समय में यह विषय सबसे बड़ा बहस का मुद्दा बनकर उभरेगा. सारे मंत्री, नेता और चुनाव आयोग के पुराने और वर्तमान अधिकारी इन दोनों मांगों को सिरे से नकार रहे हैं. आश्चर्य तो तब होता है, जब जेपी आंदोलन से निकले नेता आज जेपी की मांगों को ही नकारते हैं. चुनाव आयोग के पूर्व आयुक्त राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट को लागू करने में कई परेशानियों का वास्ता देते हैं. राहुल गांधी ने सरकारी ख़र्च पर चुनाव कराने की बात कही. सुझाव ग़लत नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि पूरा ख़र्च सरकार वहन करे. आज देश में चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपये ख़र्च करने पड़ते हैं. चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार संविधान ने दिया है, लेकिन राजनीतिक दलों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि ग़रीब और ईमानदार व्यक्ति चुनाव लड़ ही नहीं सकता. ऐसा करके राजनीतिक दलों ने देश के करोड़ों लोगों के प्रजातांत्रिक और मौलिक अधिकारों का हनन किया है.

चुनाव आयोग के एक दस्तावेज में एक अनोखी बात लिखी है. नागरिकों को क्यों वोट देना चाहिए, इस सवाल के जवाब में चुनाव आयोग कहता है कि प्रजातंत्र में वोट देने का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है. इसके इस्तेमाल से नागरिक देश की तक़दीर लिखते हैं. वे अपने नुमाइंदे चुनते हैं, जो सरकार चलाते हैं और सभी देशवासियों के विकास के लिए और उनके हित में फ़ैसले लेते हैं. चुनाव आयोग की बातें तो सही हैं, लेकिन यह पूरा सच नहीं है. सही इसलिए हैं, क्योंकि संविधान लिखने वालों ने तो यही सोचकर लिखा था. स्वतंत्रता के लिए लड़ने वाले महापुरुषों ने भी यही सपना देखा था, लेकिन एक तीखा सत्य भी है, जिसे आज की पीढ़ी को समझना जरूरी है. अगर हम नहीं समझ सके तो संभलने का मौक़ा नहीं मिलेगा. देश में तबाही और तानाशाही का राज लौट आएगा. देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सच्चाई यह है कि हमारा लोकतंत्र कुछ परिवारों और चंद नेताओं के क्लब की जागीर बन गया है. ऐसे में जब अन्ना यह ऐलान करते हैं कि उनका अगला आंदोलन राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के लिए होगा, तो राजनीतिक भूकंप आना निश्चित है. समझने वाली बात यह है कि प्रजातंत्र पर राजनीतिक दलों का ऐसा शिकंजा है, उनका ऐसा मैनेजमेंट है कि नागरिकों को ये दोनों अधिकार मिलने के बावजूद प्रजातंत्र उनके चंगुल से बाहर नहीं निकल पाएगा.

सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर चुना हुआ जनप्रतिनिधि अक्षम, निकम्मा, भ्रष्ट और बेईमान निकल जाए, राजनीतिक दल के कैडरों या धनबल या बाहुबल की वजह से चुनाव जीत जाए तो ऐसे व्यक्ति को पांच साल तक झेलना क्या प्रजातंत्र कहलाएगा. फ़र्ज़ कीजिए, कोई सांसद भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा जाता है या फिर किसी मर्डर केस में उसे जेल जाना पड़ता है तो ऐसे सांसद का क्या करना चाहिए. संसद अगर प्रजातंत्र का मंदिर है तो इस मंदिर में ऐसे लोगों को कैसे बैठने दिया जा सकता है. दूसरा सवाल यह है कि अगर सांसद किसी अपराध में जेल चला जाता है तो उसके संसदीय क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा. यह सवाल इसलिए उठता है, क्योंकि सुरेश कलमाड़ी को कोर्ट ने संसद में जाने से मना कर दिया. ए राजा भी जेल में हैं. वह भी संसद की प्रक्रिया से बाहर हैं. इसका मतलब यह है कि कलमाड़ी और ए राजा के संसदीय क्षेत्र के लोग बिना किसी प्रतिनिधि के हैं. क्या यह पुणे और नीलगिरि के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है. क्या प्रजातंत्र में मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है. इस सवाल का जवाब राजनीतिक दलों को देना चाहिए. जो लोग राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट का विरोध कर रहे हैं, उनकी दलील यह है कि इसके कार्यान्वयन में काफ़ी कठिनाइयां हैं. चुनाव आयोग को काफ़ी मुश्किल होगी. तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग या सरकार की मुश्किलें महत्वपूर्ण हैं या संविधान के मूल तत्व. क्या हमने इसे लागू करके देख लिया? अगर यही दलील है तो देश

(शेष पृष्ठ 2 पर)

जबसे सरकार ने नव उदारवाद की नीति अपनाई है, तबसे स्थिति और भी ख़राब हो गई है. भ्रष्टाचार में इज़ाफ़ा हुआ, चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया. यही वजह है कि चुनाव में पैसे का महत्व बढ़ गया है. ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अपनी सारी ऊर्जा पैसा कमाने में लगा देते हैं. उनका मक़सद सिर्फ़ पैसा कमाना होता है, न कि समाज सेवा.

RIGHT TO RECALL & RIGHT TO REJECT

जनप्रतिनिधि को वापस बुलाने और ख़ारिज करने का मतलब क्या है

राइट टू रिकॉल का मतलब है सांसदों और विधायकों को वापस बुलाने का अधिकार और राइट टू रिजेक्ट का मतलब है कि चुनाव में उम्मीदवारों को ख़ारिज करने का अधिकार. इसे समझना ज़रूरी है. सांसदों और विधायकों को वापस बुलाने के अधिकार को ऐसे समझा जा सकता है कि अगर किसी भी इलाके के लोगों को लगता है कि उनका सांसद या विधायक अपना दायित्व नहीं निभा पा रहा है या फिर वह भ्रष्टाचार में लिप्त है या फिर लोगों को लगता है कि जिन मुद्दों पर उसने वोट लिया, वह वे काम नहीं कर रहा है तो जनता को यह अधिकार है कि वह अपने सांसद या विधायक को वापस बुला ले. यह अधिकार चुने हुए सांसदों और विधायकों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा सकता है. राइट टू रिजेक्ट इससे थोड़ा अलग है. इस अधिकार का इस्तेमाल मतदाता चुनाव के दौरान ही कर सकते हैं. अगर किसी भी क्षेत्र के लोगों को लगता है कि सारे ही उम्मीदवार भ्रष्ट या अयोग्य हैं तो वे इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं. हर ईवीएम में एक ऐसा बटन होगा, जिससे मतदाता सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट कर सकता है. सवाल यह है कि क्या भारत में ऐसा संभव है, क्या क़ानून में इस तरह का प्रावधान है. अगर वापस बुलाया भी जाए तो उसकी प्रक्रिया क्या हो, चुनाव में सभी उम्मीदवारों को रिजेक्ट करने की प्रक्रिया क्या हो. ऐसी कई सारी बातें हैं, जिनके बारे में जानना और समझना ज़रूरी है.

जनप्रतिनिधियों को बर्ख़ास्त करने की प्रथा प्राचीन है. सबसे पहले यूनान में इस प्रथा की शुरुआत हुई. आधुनिक काल में यह पहली बार स्विट्ज़रलैंड में शुरू हुई. दुनिया में ऐसे कई देश हैं, जहां नागरिकों को जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार प्राप्त है. अमेरिका के कई राज्यों में ऐसी व्यवस्था है. भारत में लोकनायक जय प्रकाश नारायण ने सबसे पहले राइट टू रिकॉल की मांग की थी. 4 नवंबर, 1974 को संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान सांसदों को वापस बुलाने का आह्वान किया गया था. इसके बाद जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार केवल एक विषय के रूप में सेमिनारों और गोष्ठियों तक ही सीमित रहा. राजनीतिक दलों ने तो इस मुद्दे को ही दबा दिया.

लेकिन उस समय काफी आश्चर्य हुआ, जब राज्य सरकार ने नए गृह सचिव के रूप में 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी एम डी अंतनी की नियुक्ति कर दी.

दिल्ली का बाबू

दिलीप चेरियन

चुनाव पूर्व जंग

कांग्रेसी नेता एवं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरेंद्र सिंह ने दो वरिष्ठ अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने सेवा नियमों का उल्लंघन करते हुए अकाली दल सरकार का खुले तौर पर साथ दिया. अमरेंद्र सिंह ने दोनों अधिकारियों के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है. अमरेंद्र सिंह के मुताबिक, राज्य के पुलिस महानिदेशक पी एस गिल और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डी एस गुरु अकाली दल के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं और अगले साल जनवरी में चुनाव लड़ने का मन भी बना रहे हैं, लेकिन अभी तक चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई हैं. ऐसे में आदर्श चुनाव संहिता का मामला भी आड़े नहीं आ रहा. बहरहाल, कांग्रेस ने अभी से ही शोर मचाना शुरू कर दिया है.

सज़ा के कड़े नियम

भ्रष्ट बाबुओं ने कई सालों तक जटिल नियमों का काफी लाभ उठाया है. उनके ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के कई सबूत मिलने के बावजूद वे अपने पद पर कायम रहे, लेकिन अब लगता है कि यह सब ज़्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला. सूत्रों के अनुसार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) ने एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिसके अनुसार यदि किसी बाबू पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी जांच शीघ्रता से की जाएगी. डीओपीटी राज्यमंत्री नारायण सामी ने अधिकारियों से इस प्रस्ताव के कानूनी पक्षों का अध्ययन करने के लिए कहा है और यह भी कहा है कि यदि आवश्यकता हो तो अनुच्छेद 311 में संशोधन किया जाए, ताकि दोषी बाबुओं को सजा दी जा सके. अगर ऐसा होता है तो भ्रष्ट बाबुओं की संपत्ति जब्त करने का प्रयास और तेज हो जाएगा.

आश्चर्यजनक नियुक्ति

वर्ष 2002 के गोधरा दंगों का असर अभी भी गुजरात के प्रशासनिक ढांचे पर देखने को मिल रहा है. सरकार की ओर से दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों, संजीव भट्ट और राहुल शर्मा को हाल में किनारे लगा दिया गया. सतीश वर्मा, विवेक श्रीवास्तव और हिमांशु भट्ट सहित कुछ और आईपीएस अधिकारियों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा. लेकिन उस समय काफी आश्चर्य हुआ, जब राज्य सरकार ने नए गृह सचिव के रूप में 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी एम डी अंतनी की नियुक्ति कर दी. यह वही अधिकारी है, जिसने दंगे के समय नेताओं की मदद करने से इंकार कर दिया था. इसके बाद इनके जैसे कई अधिकारियों को केंद्र में डेपुटेशन पर जाना पड़ा था. अंतनी की नियुक्ति से न केवल उनके सहयोगियों को आश्चर्य हुआ है, बल्कि कई बड़े अधिकारी भी खासे चकित हैं.

dilipcherian@gmail..com

साउथ ब्लॉक

चक्रवर्ती सलाहकार बने

जम्मू–कश्मीर कैडर के 1980 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. पी जी धर चक्रवर्ती को अंतर–राज्य परिषद सचिवालय का नया सलाहकार नियुक्त किया गया है. वह पश्चिम बंगाल कैडर के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी डॉ. जी बालचंद्रन की जगह लेंगे, जिन्हें एनपीपीए का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

नैनी एनसीआरपीबी में

वर्ष 1980 बैच की आईएएस अधिकारी एवं योजना आयोग की सलाहकार नैनी जयासीलन को शहरी विकास मंत्रालय के अधीन एनसीआरपीबी में नया सदस्य सचिव बनाया गया है.

विजय बनेंगे डायरेक्टर

वर्ष 1997 बैच के आईटीएस अधिकारी विजय अग्रवाल को जल्द ही रक्षा विभाग में डायरेक्टर बनाया जाएगा. यह पद नवसृजित है.

शैलेंद्र यूपीएससी जाएंगे

वर्ष 1997 बैच के आईएफएस अधिकारी शैलेंद्र सिंह संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में डायरेक्टर बनाए जाएंगे. वह वी पी सिंह की जगह लेंगे.

सुधीर को सेवा विस्तार

बिहार कैडर के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी एवं ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर कार्यरत सुधीर कुमार को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है. उनका वर्तमान कार्यकाल अगले महीने पूरा होने वाला था.

यह प्रजातंत्र अधूरा है

पृष्ठ एक का शेष

की उन सारी योजनाओं को भी बंद कर देना चाहिए, जो ठीक से लागू नहीं हो पातीं या फिर सरकार की मुश्किलों की वजह से विफल हो जाती हैं.

वोट देने का अधिकार मौलिक अधिकार है. इसे कोई नहीं छीन सकता है. वोट देने का मतलब क्या होता है. प्रजातंत्र का मतलब ऐसी सरकार से है, जो जनता के लिए काम करती है और जो जनता द्वारा चुनी जाती है. भारत में भी पांच सालों के लिए सांसदों और विधायकों को चुना जाता है. क्या यह मान लेना चाहिए कि एक बार चुनाव जीत जाने के बाद पांच साल तक मनमानी करने का अधिकार मिल जाता है. अगर नहीं तो जनप्रतिनिधियों को हटाने का अधिकार किसके पास हो? राजनीतिक दलों ने अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए प्रजातंत्र को ही उल्टा टांग दिया है. भारत के प्रजातंत्र में एक अनोखा विरोधाभास है. संविधान में तो यह कहा गया है कि सांसद और विधायक जनता के प्रतिनिधि हैं, लेकिन राजनीतिक दलों ने क़ानून में इस तरह फेरबदल कर दिया है कि सांसद या विधायक को जनता के प्रतिनिधि के बजाय पार्टी का एक प्यादा बना दिया गया. फ़र्ज़ कीजिए, कोई क़ानून बनता है, जिससे किसी सांसद या विधायक के क्षेत्र के लोगों पर विपरीत असर पड़ेगा. उसके क्षेत्र के सारे लोग उस क़ानून का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उस सांसद या विधायक की पार्टी उस क़ानून के पक्ष में है. जब वोटिंग होगी तो उसके सामने दो विकल्प होंगे, या तो वह जनता की आवाज़ सुने या फिर पार्टी की बात माने. अगर वह पार्टी की बात मानता है तो उसे इसका हिसाब अगले चुनाव में चुकाना होगा और अगर वह जनता की आवाज सुनता है और क़ानून के विरोध में वोट करता है तो उसकी सदस्यता ही ख़त्म हो जाएगी. यही है हमारे देश की संसदीय व्यवस्था का चरित्र. अब सवाल यह है कि ऐसे जनप्रतिनिधियों का प्रजातंत्र में क्या औचित्य है, जिनके लिए जनता की आवाज को अनसुना करना एक मजबूरी बन

जाती है.

इस बात का श्रेय नीतीश कुमार को देना ही चाहिए कि उन्होंने बिहार में लोगों को नगर पार्षदों को वापस बुलाने का अधिकार देने का फ़ैसला किया. इस अधिकार से लाभ यह होगा कि जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह बनेंगे. इस अधिकार से जनता भी सजग रहेगी और वह समाज की समस्याओं और जनप्रतिनिधियों के क्रियाकलापों पर नज़र रखेगी. इससे समाज का राजनीतिक सशक्तिकरण होगा. देश के हर इलाके में गरीबों, पिछड़ों और शोषितों की संख्या ज्यादा है, इसलिए जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने में उनकी सबसे ज्यादा भागीदारी होगी. अब यह तय है कि जनप्रतिनिधि इन वर्गों की समस्याओं के प्रति उदासीन रहने का ख़तरा नहीं उठाएंगे. इस अधिकार के बाद ही लोकतंत्र को सही मायने में जनता का राज कहा जा सकता है.

आज जो स्थिति है, उसमें यही कहा जा सकता है कि लोकतंत्र राजनीतिक दलों के हाथ की कठपुतली बन गया है. सत्ता पक्ष अपनी मनमर्जी से सरकारी तंत्र का जैसा इस्तेमाल करना चाहता है, कर लेता है. जनप्रतिनिधियों को वापस बुलाने का अधिकार देश की जनता को सशक्त करेगा. सांसदों–विधायकों को जनता के गुस्से का डर भी बना रहेगा, लेकिन इससे समस्या नहीं सुलझने वाली है, क्योंकि उनकी जगह जो भी चुनकर जाएगा, वह वही करेगा, जो पिछले जनप्रतिनिधि ने किया. इस बीमारी की असली वजह यह है कि देश में जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुने तो जाते हैं, लेकिन विधायिका में वे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि की तरह काम करते हैं. यह उनकी आदत नहीं, विधायिका के सदस्य बने रहने की शर्त है.

जब चुनाव होते हैं तो हर उम्मीदवार कुछ वायदे करता है. जब वह चुन लिया जाता है तो अपने वायदे के मुताबिक़ काम नहीं कर पाता है. विश्व के अधिकांश प्रजातंत्रों में जनप्रतिनिधि अपने वायदे को पूरा करने में लगे रहते हैं. अगर कोई योजना उसे ग़लत लगती है तो वह अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ भी वोट कर सकता है, अपने विचार रख सकता है. लेकिन हिंदुस्तान में जनप्रतिनिधियों को संसद में अपनी पार्टी की व्हिप के मुताबिक़ चलना पड़ता है. किसी सांसद का किस विषय पर क्या पक्ष होगा, यह तय करने का अधिकार उसे नहीं है. उसे पार्टी के मुताबिक ही चलना पड़ता है, वरना उसे निष्कासित कर दिया जाता है. वैसे मज़ेदार बात यह है कि व्हिप का मतलब भी चाबुक होता है. पार्टी चाबुक से अपने सदस्यों को हांकती है. यह जनप्रतिनिधि और जनता के प्रजातांत्रिक अधिकारों का घोर हनन है. यह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का अपमान है. यह प्रचलन दलबदल क़ानून लागू होने से शुरू हुआ. देश में आयाराम–गयाराम की राजनीति पर अंकुश लगाने के लिए 1985 में दलबदल निरोधक क़ानून लागू किया गया था. सत्ता में भागीदारी या दूसरे लाभ हासिल करने के चक्कर में अपनी पार्टी को छलने की नेताओं की आदत पर अंकुश लगाने के लिए यह क़ानून अमल में लाया गया था.

अफ़सोस तो इस बात का है कि देश की सभी पार्टियां अपने संगठन के संचालन में लोकतांत्रिक नहीं हैं. हिंदुस्तान में किसी भी पार्टी में वोटिंग के ज़रिए फ़ैसला लेने का प्रचलन नहीं है. कार्यकर्ताओं की बात तो दूर, सांसदों और विधायकों की भी किसी पार्टी में कोई सुनवाई नहीं है. हर पार्टी के शीर्ष पर एक ग्रुप बैठा है. देश की ज़्यादातर पार्टियां पारिवारिक पार्टियां हैं, इसलिए फ़ैसला लेने का अधिकार पार्टी चलाने वाले परिवार तक सीमित है. भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियों और जेडीयू आदि में परिवारवाद तो नहीं है, लेकिन वहां भी फ़ैसला लेने का हक़ कुछ लोगों तक सीमित है. राजनीतिक दल अगर वोटिंग करके सांसदों और विधायकों को निर्देश देते तो भी कुछ कहा जा सकता था, लेकिन यहां तो एक परिवार की राय ही पार्टी की राय बन जाती है और अगर उसी पार्टी की सरकार हो तो एक परिवार की राय सरकार की राय बन जाती है. कड़वा सच तो यह है कि भारत में राजनीतिक पार्टियां अलोकतांत्रिक हैं और वे किसी परिवार या कुछ ख़ास लोगों या समूहों की गिरफ्त में फंसकर सामंतवादी हो गई हैं. भारत का प्रजातंत्र एक अजीब तरह के सामंतवाद के जाल में फंस गया है. संविधान बनाने वाले महापुरुषों ने शायद यह कल्पना भी नहीं की होगी कि भारत में प्रजातंत्र की ऐसी दुर्दशा हो जाएगी, वरना वे बचाव के लिए संविधान में कोई प्रावधान ज़रूर करते. यह एक नई स्थिति पैदा हुई है, इसलिए इसका इलाज भी ज़रूरी है. अगर सांसदों को वापस बुलाए जाने का डर रहेगा तो वे दलबदल करने से बचेंगे. इसलिए आज ज़रूरत इस बात की है कि राइट टू रिकॉल और राइट टू रिजेक्ट के साथ–साथ संसद और विधानसभाओं में चीफ व्हिप को ख़त्म किया जाए, ताकि देश के प्रजातंत्र को परिपक्व होने का मौका मिल सके. जब तक संसद और विधानसभाओं में व्हिप को नहीं हटाया जाएगा और जब तक राजनीतिक दलों में आंतरिक प्रजातंत्र नहीं होगा, तब तक देश का प्रजातंत्र चंद लोगों की जागीर बना रहेगा.

दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गर्व तो हर भारतीय को है, लेकिन जब संसद के सदस्यों की असलियत का पता चलता है तो अफ़सोस होता है. सामान्य चुनावी प्रक्रिया अपराधियों और अयोग्य लोगों को चुनाव में हिस्सा लेने से रोक नहीं सकी. जबसे नव उदारवाद की नीति सरकार ने अपनाई है, तबसे स्थिति और भी खराब हो गई है. भ्रष्टाचार में इज़ाफ़ा हुआ, चुनाव जीतने के लिए उम्मीदवार किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गया. यही वजह है कि चुनाव में पैसे का महत्व बढ़ गया है. ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद अपनी सारी ऊर्जा पैसा कमाने में लगा देते हैं. उनका मक़सद पैसा कमाना होता है, न कि समाज सेवा. प्रजातांत्रिक संस्थाओं को 60 साल का वक़्त मिला कि वे स्वयं को मर्यादित कर सकें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका. अब वक़्त आ गया है कि देश में बड़े पैमाने पर राजनीतिक और चुनाव सुधार की ज़रूरत है. इससे पहले कि देश की जनता वर्तमान व्यवस्था से पूरी तरह भ्रमित हो जाए, उसका विश्वास ख़त्म हो जाए, सभी प्रजातांत्रिक संस्थाओं, उनके सदस्यों एवं अधिकारियों को ज़िम्मेदार और जवाबदेह बनना होगा.

manish@chauthiduniya.com

सभी फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

चौथी दुनिया
हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार

वर्ष 3 अंक 27
दिल्ली, 12 सितंबर–18 सितंबर 2011
RNI-DELHIN/2009/30467

संपादक
संतोष भारतीय

संपादक समन्वय
डॉ. मनीष कुमार

सहायक संपादक
सरोज कुमार सिंह (बिहार–झारखंड)

प्रबंध संपादक
श्रीनिवास गुप्ता (ठाकुर) (उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड)

प्रबंध संपादक (महाराष्ट्र)
प्रवीण महाजन

मैसर्स अंकुश पब्लिकेशंस प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक व प्रकाशक रामपाल सिंह भदौरिया द्वारा जागरण प्रकाशन लिमिटेड डी 210–211 सेक्टर 63 नोएडा उत्तर प्रदेश से मुद्रित एवं के – 2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001 से प्रकाशित

संपादकीय कार्यालय

के –2, गैनन, चौधरी बिल्डिंग
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली 110001
कैंप कार्यालय एफ–2, सेक्टर –11, नोएडा
गौतमबुद्ध नगर उत्तर प्रदेश–201301

फोन न.
संपादकीय 0120–4783999/011–23418962
0120–6450888, 0120–6452888
0120–6451999
विज्ञापन व प्रसार +91 120–4783999
+91 9266627366
फैक्स न. 0120–4783950

पृष्ठ–16+4 (बिहार–झारखंड, उत्तर प्रदेश–उत्तराखंड एवं महाराष्ट्र)

चौथी दुनिया में छपे सभी लेख अथवा सामग्री पर चौथी दुनिया का कॉपीराइट है. बिना अनुमति के किसी लेख अथवा सामग्री के पुनः प्रकाशन पर क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
समस्त कानूनी विवादों का क्षेत्राधिकार दिल्ली न्यायालयों के अधीन होगा.

सरकार ने इस बीच के समय का इस्तेमाल अन्ना टीम पर पलटवार करने के लिए करना शुरू कर दिया है. सबसे पहला निशाना बने स्वामी अग्निवेश.

टीम अन्ना के ख़िलाफ़ सरकार की साज़िश

अन्ना का अनशन ख़त्म होते ही सरकार की साजिश शुरू. दरअसल, टीम अन्ना के बहाने यह जनता के ख़िलाफ़ एक सरकारी साजिश है. आख़िर क्यों? जवाब साफ है, ताकि जनता को जन लोकपाल न मिले, ताकि व्यवस्था में बदलाव न हो. पहले स्वामी अग्निवेश का स्टिंग, फिर भूषण सीडी प्रकरण का वापस आना. इस सबसे एक क़दम आगे बढ़ते हुए सरकार ने कुछ बुद्धिजीवियों और मीडिया हाउसों के सहारे इस पूरे आंदोलन की फंडिंग पर सवाल उठवाना शुरू कर दिया है. आखिर क्या है इन आरोपों की सच्चाई? पेश है चौथी दुनिया की यह ख़ास रिपोर्ट...

शशि शेखर

अन्ना टीम पर अचानक आरोपों की बरसात होने लगी है. पहले टीम में फूट डाली गई. एक बार फिर से सीडी प्रकरण के बहाने भूषण पिता–पुत्र पर आरोप लगाने की तैयारी है. इस सबसे अलग, अब इस आंदोलन को विदेशी पैसों से चलाए जाने की बात कही जा रही है. कहा जा रहा है कि यह आंदोलन फोर्ड फाउंडेशन और विश्व बैंक की मदद से चलाया गया. और तो और, बुद्धिजीवी मानी जाने वाली एक लेखिका ने तो सीधे–सीधे अन्ना हजारे पर ही निशाना साधा. आख़िर अचानक यह सब क्यों शुरू हुआ? सोचने की बात है. जन लोकपाल को लेकर 12 दिनों तक चले अन्ना के अनशन ने सरकार को उनके तीन सुझाव मानने के लिए मजबूर कर दिया. लोअर ब्यूरोक्रेसी, राज्यों में लोकायुक्तों का गठन और सिटिजन चार्टर, ये तीनों मांगें अहम हैं और जन लोकपाल की भावना को मज़बूती देने वाली हैं. ज़ाहिर है, अगर केंद्र सरकार इन तीनों मांगों को ईमानदारी से मानकर इन्हें लोकपाल विधेयक में शामिल कर लेती है तो यह जनता की एक बड़ी जीत मानी जाएगी. फ़िलहाल इन सुझावों को स्थायी समिति के पास भेज दिया गया है, जहां इन पर चर्चा होगी और यह तय किया जाएगा कि कौन से सुझाव माने जाएं और किस तरह इनका क्रियान्वयन किया जाएगा. इस काम में अभी कम से कम दो से तीन महीने का वक़्त लगेगा.

सरकार ने इस बीच के समय का इस्तेमाल अन्ना टीम पर पलटवार करने के लिए करना शुरू कर दिया है. सबसे पहला निशाना बने स्वामी अग्निवेश. अन्ना के मंच से जब स्वामी अग्निवेश इस पूरी लड़ाई को आज़ादी की दूसरी लड़ाई बता रहे थे, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि यह भगवाधारी स्वामी जी कभी अन्ना और उनकी टीम को पागल हाथी तक बता डालेंगे और सरकार के एक ताक़तवर मंत्री को टीम अन्ना से सख्ती से निपटने की सलाह देते नज़र आएंगे. दरअसल, यह ख़ुलासा स्वामी अग्निवेश के एक स्टिंग ऑपरेशन से हुआ. सवाल यह है कि आख़िर अग्निवेश का स्टिंग ऑपरेशन किसने कराया और क्यों कराया. इसमें अग्निवेश को किसी कपिल महाराज से बात करते हुए दिखाया गया है, जिसमें वह अन्ना टीम को पागल हाथी बोल रहे हैं और उससे सख्ती से निपटने की वकालत करते सुनाई दे रहे हैं. यह ठीक है कि अन्ना के अनशन से कुछ समय पहले से ही अन्ना टीम से अग्निवेश की दूरी बनने लगी थी. सवाल सिर्फ़ अग्निवेश के बयान का नहीं है. अब जब स्टिंग सामने आ गया है तो यह सच भी सामने आना चाहिए कि आख़िर इसके पीछे कौन है. इस सवाल का जवाब टीम अन्ना के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं न कहीं, कोई न कोई ऐसा है, जो लगातार टीम अन्ना के सदस्यों को बदनाम करने की ताक में है और वे इसमें सफल भी हो रहे हैं.

अरुंधति रॉय

इसी बीच बुकर पुरस्कार से नवाजी गई और बुद्धिजीवी कहलाने वाली लेखिका अरुंधति रॉय ने तो इस आंदोलन को फोर्ड फाउंडेशन और विश्व बैंक से सहायता मिलने का आरोप लगाकर टीम अन्ना के सारे सदस्यों को ही कठघरे में खड़ा करने की कोशिश शुरू कर दी है. रॉय ने तो आंदोलन के दौरान वंदे मातरम के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाया है. वह कहती हैं कि

प्रशांत भूषण शांति भूषण

आज़ाद देश में राष्ट्रीय झंडा किसके ख़िलाफ़ उठाया जा रहा है. ऐसा करके आप लोगों को बांटते हैं, जोड़ते नहीं हैं. एक मीडिया हाउस से बातचीत में रॉय कहती हैं कि अन्ना के आंदोलन में कई ऐसी बातें थीं, जो बेहद ख़तरनाक हैं. उन्होंने यह भी कहा कि अन्ना ख़ुद कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग उनके साथ हैं, जो अन्ना के नाम पर अपना आंदोलन चला रहे हैं. बहरहाल, अन्ना टीम के सदस्यों और ख़ासकर अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी और मनीष सिसौदिया को चाहिए कि वे अरुंधति रॉय के विदेशी फंडिंग के आरोप का करारा जवाब दें, क्योंकि यहां सवाल सिर्फ़ इतना नहीं है कि आप पर कोई आरोप लगाए और आप यह कहकर अपना पल्ला झाड़ लें कि सबूत कहां है?

चौथी दुनिया की तफ्तीश में जो बातें खुलकर समाने आई हैं, उनके अनुसार, अरविंद केजरीवाल के निकटतम सहयोगी मनीष सिसौदिया की संस्था कबीर को फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिलता है. यह कोई ऐसा सच नहीं है, जिसे लोग नहीं जानते, लेकिन यहीं एक पेंच है. दरअसल, फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट पर जब हम डोनेशन पाने वाली संस्थाओं के नाम ढूंढते हैं तो उनमें एक नाम कबीर का भी आता है. फोर्ड फाउंडेशन ने 2011 के लिए कबीर संस्था को दो लाख डॉलर दिए हैं, ऐसा उसकी वेबसाइट पर लिखा है. बहरहाल, जब आप इस सूची को थोड़ा और खंगालेंगे तो पता चलेगा कि कबीर इस देश की अकेली संस्था नहीं है, जिसे फोर्ड से पैसा मिलता है, बल्कि हिंदुस्तान के कई और एनजीओ हैं, जिन्हें फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिलता है. चौथी दुनिया को मिली सूचना के मुताबिक़ , एक तथ्य यह भी है कि कबीर संस्था ने चालू वर्ष के लिए फोर्ड से पैसा लेने से मना कर दिया है, लेकिन आरोप लगाने वालों के लिए इतनी सूचना ही काफी है, जो उन्हें फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट से मिल रही है. हालांकि आरोप लगाने वालों के लिए यह साबित कर पाना भी आसान नहीं है कि वाकई इस आंदोलन में फोर्ड फाउंडेशन के पैसे का इस्तेमाल हुआ है. इसके अलावा किरण बेदी की संस्था पर भी विदेशी फंड लेने का आरोप लगाया जा रहा है. ख़ैर, आरोप लगाने वालों का मुंह बंद नहीं किया जा सकता, लेकिन सच्चाई को सामने रखने में भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. इंडिया अगेंस्ट करप्शन ने इस आंदोलन में ख़र्च हुए एक–एक पैसे का हिसाब अपनी वेबसाइट पर दिया है. ऐसे में यह ज़रूरी है कि टीम अन्ना के सभी सदस्य इन आरोपों का मज़बूती से जवाब दें. क्योंकि यह मसला सिर्फ़ आरोप लगाने भर का नहीं है. इसके पीछे निश्चित तौर पर सरकारी मशीनरी भी लगी हुई है, जो जानबूझ कर टीम अन्ना को एक बार फिर से बदनाम करने की कोशिश में जुटी हुई है.

एक सच्चाई यह भी है कि आरोप लगाने वाले ख़ुद दूध के धुले नहीं हैं, उनके दामन पर भी दाग हैं, लेकिन वक्त का तकाजा कुछ और है. टीम अन्ना को यह सोचना होगा कि जन लोकपाल की इस लंबी लड़ाई में उन्हें सरकार नामक एक मज़बूत संस्था से भी लोहा लेना है, जिसकी चालबाज़ियों का शिकार वह तब भी हुई थी, जब ज्वाइंट ड्राफ्ट कमेटी में भूषण पिता–पुत्र को शामिल किया गया था. तब अचानक एक टेप सामने आ गया था, जिसमें वे अमर सिंह से बात कर रहे हैं. एक बार फिर यह टेप प्रकरण सामने आ गया है. टीम अन्ना के एक महत्वपूर्ण सदस्य शांति भूषण की मुलायम सिंह यादव और अमर सिंह के साथ बातचीत की कथित सीडी को दिल्ली पुलिस अब फिर से सही बता रही है और अपनी क्लोज़र रिपोर्ट में भी उसने इस सीडी को सही बताया है. हालांकि शांति भूषण पहले से कह रहे हैं कि सीडी से छेड़छाड़ की गई है और इसके पीछे कोई बड़ी ताक़त है. टीम अन्ना

फोर्ड फाउंडेशन ने 2011 के लिए कबीर संस्था को दो लाख डॉलर दिए हैं, ऐसा उसकी वेबसाइट पर लिखा है. चौथी दुनिया को मिली सूचना के मुताबिक़ , एक तथ्य यह भी है कि कबीर संस्था ने चालू वर्ष के लिए फोर्ड से पैसा लेने से मना कर दिया है, लेकिन आरोप लगाने वालों के लिए इतनी सूचना ही काफी है, जो उन्हें फोर्ड फाउंडेशन की वेबसाइट से मिल रही है. हालांकि आरोप लगाने वालों के लिए यह साबित कर पाना भी आसान नहीं है कि वाकई इस आंदोलन में फोर्ड फाउंडेशन के पैसे का इस्तेमाल हुआ है.

के एक और अहम सदस्य संतोष हेगड़े भी अपने बयानों से यही संदेश देते रहे हैं कि वह अन्ना या टीम के अन्य साथियों की राय से थोड़ी अलग राय रखते हैं. मसलन, अन्ना के आमरण अनशन से वह भी सहमत नहीं थे.

बहरहाल, टीम अन्ना को भी यह पता होगा कि एक बार फिर सरकारी साजिश शुरू हो चुकी है. इसलिए बेहतर होगा कि टीम अन्ना हर आरोप का जवाब दे, पूरी पारदर्शिता के साथ, क्योंकि जब आप जन लोकपाल जैसा अहम मुद्दा लेकर जनता के बीच जाते हैं तो एक छोटा आरोप भी बड़ा बन जाता है. और हां, सरकार की कोई भी साजिश, जो टीम अन्ना के ख़िलाफ़ होगी, असल में वह जनता के ख़िलाफ़ ही होगी, क्योंकि जनता के लिए आज सबसे ज़रूरी है एक सशक्त लोकपाल बिल. इसमें कौन किस पर आरोप लगाता है, कौन क्या जवाब देता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है. महत्वपूर्ण यह है कि किसी भी सूरत में जनता के साथ कोई साजिश न हो और उसे एक मज़बूत लोकपाल मिल सके.

shashishekhar@chauthiduniya.com

सेक्टर 9 निवासी नसीम अहमद का कहना है कि झुग्गी टूटते ही हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और काम न होने के कारण दो वक़्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाएगी.

उत्तर प्रदेश

दागी, दबंग और पिटे मोहरों पर दांव

अजय कुमार

देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश वर्ष 2012 और नए मुख्यमंत्री के इंतज़ार में आंखें बिछाए बैठा है. कोई कहता है कि मायावती की वापसी होगी तो किसी का विश्वास मुलायम सिंह के प्रति अडिग हो रहा है. भाजपा जो लंबे समय से सत्ता से दूर है, उसे भी चमत्कार की उम्मीद कम नहीं है. कांग्रेस को सिर्फ़ अपने युवराज पर भरोसा है. सत्ता हासिल करने के लिए सभी दलों द्वारा बिसात बिछाई जा रही है. कई राजनीतिक दलों ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है. सपा और बसपा इस मामले में काफी आगे रहीं तो भाजपा और कांग्रेस के लिए यह काम मुश्किल दिखा. भाजपा तो आज तक अपने प्रत्याशियों के नाम नहीं तय कर पाई. कांग्रेस ने ज़रूर बाजी मार ली. उसने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की तो अंदर से बाहर तक उसे फ़ज़ीहत का सामना करना पड़ा. पार्टी के भीतर टिकट वितरण को लेकर नाराज़गी थी तो बाहर राष्ट्रीय लोकदल के चौधरी अजित सिंह इस बात से नाराज़ दिखे कि एक तरफ़ तो कांग्रेस उनके साथ हाथ मिलाने का नाटक करती रही, दूसरी तरफ़ उसने उन विधानसभा क्षेत्रों में भी टिकट बांट दिए, जहां लोकदल की दावेदारी थी. कांग्रेस की पहली सूची जातीय समीकरण बैठाने में काफी हद तक सफल दिखी. कांग्रेस में बसपा और सपा के घर में सेंध लगाने की हसरत भी नज़र आई.

बहरहाल, कांग्रेस ने राहुल गांधी के मिशन 2012 को पूरा करने के लिए जैसे ही प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की, उसे देखकर राजनीतिक पंडितों का माथा ठनक गया. कांग्रेस के थिंक टैंक ने आश्चर्यजनक रूप से दलबदलुओं, दागियों और पिछले चुनावों में मात खाए नेताओं को खासी तवज्जो देकर साबित कर दिया कि पार्टी के पास मज़बूत मोहरे नहीं हैं या फिर उसकी मानसिकता में कोई बदलाव नहीं आया है. पहली सूची में शामिल एक दर्जन से ज़्यादा प्रत्याशी आपराधिक पृष्ठभूमि वाले हैं. 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जो 21 उम्मीदवार जीतकर आए थे, उनमें से एक दर्जन का आपराधिक रिकॉर्ड था और उम्मीद यही की जा रही थी कि इस बार पार्टी इन दागी चेहरों को ख़ुद से दूर रखेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. दागी और दलबदलुओं के साथ ही कांग्रेस ने इस बार बड़ी संख्या में पिटे मोहरों पर भी दांव लगाया है. ऐसे नेताओं को टिकट दिया गया है, जिन्हें स्वयं याद नहीं कि वे आख़िरी बार कब जीते थे, कितनी बार से हार रहे हैं? सूची में कई नाम ऐसे हैं, जो बड़े राजनीतिक घरानों से

ताल्लुक रखते हैं. ऐसे लोगों की भरमार है, जो कुछ समय पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे. सपा के टिकट से चुनाव जीतने वाले विधायक अरविंद गिरि अबकी हाथ थाम कर जीत हासिल करना चाहते हैं. टिकट वितरण में ज़मीनी लोगों की जगह बड़े नेताओं, मंत्रियों एवं सांसदों की पत्नियों को तवज्जो दी गई. पार्टी का झंडा ऊंचा करने वालों को आश्वासन से काम चलाना पड़ा. सदन से सड़क तक अपराधियों से दूर रहने, उन्हें टिकट न देने की कसमें खाने के बावजूद आपराधिक पृष्ठभूमि के अरविंद गिरि, राना किंकर सिंह एवं अजय राय को टिकट थमा दिया गयाा. यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर सुर्ख़ियों में आईं गुलाबी गैंग की मुखिया संपत पाल भी कांग्रेस की उम्मीदवार बन गईं.

टिकट वितरण प्रक्रिया शुरू करने से पहले कहा गया था कि जो भी ज़िला–शहर अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे, उन्हें अपना पद छोड़ना होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया. लखनऊ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष श्याम किशोर शुक्ल और महाराजगंज के ज़िला अध्यक्ष आलोक प्रसाद को इस मामले में छूट मिल गई. आलोक प्रसाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे सुखदेव प्रसाद के पुत्र हैं. केंद्रीय क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद की पत्नी लुईस ख़ुर्शीद और बरेली के सांसद प्रवीण सिंह ऐरन की पत्नी एवं मेयर सुप्रिया ऐरन को उम्मीदवार बनाया गया है. समन्वय समिति की बैठकों में बार–बार दोहराया जाता रहा कि दूसरे दलों से आने वाले किसी भी नेता को तीन साल तक न तो संगठन में पद दिया जाएगा और न चुनाव में उतारा जाएगा, लेकिन सूची देखकर साफ है कि इस नसीहत की भी अनदेखी की गई. हाल में पीडीपी से आए यूसुफ कुरैशी और सपा से आए अरविंद गिरि एवं वंशीधर राज को सभी बातें भूलकर उम्मीदवार बनाया गया.

कांग्रेस के साथ महिलाओं का हाथ नहीं!

कांग्रेस से आधी आबादी ख़ुश नहीं है. इस बात का एहसास महिला कांग्रेस के सम्मेलनों से महिलाओं द्वारा बनाई गई दूरी से होता है. यह नज़ारा हाल–फ़िलहाल तब दिखा, जब लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बुलाए गए सम्मेलन में अधिकांश जनपदों की महिला पदाधिकारी ग़ायब रहीं. महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीता वर्मा ने जब इस पर आंखें तरेरी तो उन्हें समझा दिया गया कि प्रदेश के कई जनपद बाढ़ से प्रभावित हैं. इसलिए सम्मेलन में कई पदाधिकारी हिस्सा नहीं ले पा रही हैं. प्रदेश महिला कांग्रेस ने सभी 70 जनपदों से महिला कांग्रेस की ज़िला, शहर एवं ब्लॉक अध्यक्षों को आमंत्रित किया था. मकसद, विधानसभा चुनाव में महिला कांग्रेस की भूमिका का जायज़ा लेना था. ख़ासी मशक्कत के बाद अगली पंक्ति की कुर्सियां भरी गईं. मीडिया को भी यही बताया गया कि कई जनपदों के बाढ़ प्रभावित होने की वजह से वहां की पदाधिकारियों का आना संभव नहीं हो सका.

कांग्रेस की पहली सूची में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रीता बहुगुणा जोशी, रंजीत सिंह जूदेव, बिहारी लाल आर्य, वंशीधर राज, बैजनाथ रावत, सुरेंद्र प्रकाश गोयल, दलजीत सिंह, राजधारी सिंह एवं बच्चा पाठक सहित एक दर्जन ऐसे नाम हैं, जो पिछले चुनाव में कहीं मुक़ाबले में नहीं दिखे, इसके बावजूद कांग्रेस ने इन पर भरोसा करने में संकोच नहीं किया. रीता बहुगुणा दो लोकसभा और एक विधानसभा चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन कामयाबी एक में भी नहीं मिली. वह 1998 के लोकसभा चुनाव में सुल्तानपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थीं और दूसरे स्थान पर रहीं. इसके बाद कांग्रेस में शामिल हुईं और 2007 के विधानसभा चुनाव में इलाहाबाद दक्षिणी से चुनाव मैदान में उतरीं और तीसरे नंबर पर रहीं. 2009 के लोकसभा चुनाव में अंतिम समय पर कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें लखनऊ संसदीय क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारा गया, जिसमें वह दूसरे नंबर पर रहीं. इस चुनाव में उन्हें कैंट विधानसभा क्षेत्र से साढ़े पांच हज़ार से ज़्यादा वोटों की बढ़त मिली थी, इसलिए उन्हें इस बार यहीं से टिकट दिया गया. प्रदेश उपाध्यक्ष रंजीत सिंह जूदेव को चुनाव हारने के बाद विधान परिषद का सदस्य बना दिया गया था. इस बार फिर नेतृत्व ने भरोसा जताया है. आलाकमान ने जिन्हें टिकट देना चाहा, उन्हें यह कहकर टिकट थमा दिया कि पिछले चुनाव में वे रनर थे, इसलिए दूसरी बार टिकट के लिए उनकी दावेदारी बनती है. आरोप है कि प्रत्याशी चयन में दूसरे दल से आए लोगों को समायोजित करने के चक्कर में वफादार कांग्रेसियों की अनदेखी कर दी गई.

कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के लौटने के बाद इस सूची में बदलाव हो सकता है. कई सीटें ऐसी हैं, जहां बड़े नेताओं के परिवारीजनों को टिकट देते समय वर्षों से तैयारियों में लगे कार्यकर्ताओं की अनदेखी कर दी गई. पहली सूची में 21 दलितों–पिछड़ों, 12 ब्राह्मणों, नौ राजपूतों और 8 मुस्लिमों को टिकट देकर कांग्रेस ने जिस तरह जातीय संतुलन बनाने की कोशिश की, उससे तो यही लगता है कि वह बसपा और सपा का खेल बिगाड़ना चाहती है. बड़ी संख्या में दलितों और पिछड़ों को टिकट देना इस बात का प्रमाण है. बेनी प्रसाद वर्मा के आने के बाद कांग्रेस पिछड़ों का वोट हासिल करके सपा को झटका देने के लिए लालायित है. वहीं दलितों को टिकट देना राहुल के मिशन का हिस्सा है, जिस पर वह काफी समय से काम कर रहे थे. राष्ट्रीय लोकदल के अजित सिंह कांग्रेस की सूची से नाराज़ नज़र आए. अजित सिंह कांग्रेस से गठबंधन की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन कांग्रेस ने उन्हें झटका दे दिया. यही वजह थी कि अजित सिंह ने जन लोकपाल बिल का समर्थन करके सबको चौंका दिया. कांग्रेस से झटका खाए अजित सिंह अब एक तरफ़ सपा से पेंग बढ़ाने में लगे हैं, दूसरी तरफ़ पीस पार्टी जैसे छोटे दलों के साथ बने गठजोड़ को भी ज़िंदा करने की कोशिश में लगे हैं. वैसे मुलायम सिंह से उनकी कोई बात बन पाएगी, इसकी उम्मीद कम है, क्योंकि सपा क़रीब–क़रीब सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर चुकी है. अजित को एनडीए और बसपा को छोड़कर किसी से भी हाथ मिलाने में परहेज नहीं है, क्योंकि वह जानते हैं कि उनकी हांडी तभी पक सकती है, जब उन्हें कहीं से आग मिलेगी.

feedback@chauthiduniya.com

नोएडा

झुग्गीवालों पर विस्थापन की तलवार

लोकतंत्र में चुनाव सबसे बड़ा पर्व होता है. चुनाव क़रीब आते ही धमाचौकड़ी और हुड़दंग का माहौल बन जाता है. दो तरह के दृश्य नज़र आने लगते हैं. राजनीतिज्ञों की बंद तिजोरियां खुलने लगती हैं, मतदाताओं को लुभाने के लिए उपहारों की बारिश होने लगती है. लुभावने वायदों और भाषणों का दौर चल पड़ता है. दूसरा दृश्य होता है दिल दहलाने, मासूमों–बेगुनाहों के ख़ून से होली खेलने और ग़रीबों को उजाड़ने वाला, जैसे नोएडा, जहां के झुग्गीवालों को उजाड़ने की तैयारी चल रही है.

उत्तर प्रदेश में चुनाव सिर पर हैं. आजकल में चुनाव की तारीख़ें भी घोषित हो जाएंगी. चुनाव क़रीब आते देख नोएडा के झुग्गीवालों में गहमागहमी का माहौल है. उन्हें अपनी झुग्गियां उजड़ने का डर है. उनके बदले मिलने वाले मकान के लिए भी अंधेरगर्दी का माहौल है. नोएडा के सेक्टर 4,5,8,9 और 10 में दशकों से हज़ारों झुग्गियां आबाद हैं. पिछले कई वर्षों से इन पर सरकार की तलवार लटकी हुई है कि न जाने कब ये टूट जाएं, मगर अब वह दिन समीप आ गया है. निकट भविष्य में ये झुग्गियां टूट जाएंगी और इसके बदले लोगों को सेक्टर 122 में दो कमरे, एक शौचालय और एक रसोईघर वाला फ्लैट मिलेगा, जिसकी क़ीमत तक़रीबन 13 लाख रुपये होगी. इस मामले में कार्रवाई शुरू हो चुकी है. आवेदन फॉर्म सेक्टर 6 के विजया बैंक, केनरा बैंक, सेक्टर 18 के आरबीएस बैंक और सेक्टर 20 के सेंट्रल बैंक में उपलब्ध हैं. बहुत से लोगों ने यह फॉर्म ख़रीद भी लिया है और बहुत से लोग इसका विरोध कर रहे हैं. फ्लैट के लिए 20 शर्तें रखी गई हैं, जैसे कि अपनी उजड़ी हुई झुग्गी के बदले फ्लैट लेने वालों को 66 हज़ार रुपये का अग्रिम भुगतान करना होगा और बाक़ी धनराशि 240 महीनों यानी 20 साल तक 4912 रुपये की मासिक क़िस्त के रूप में देनी होगी. अग्रिम राशि जमा करने के दो वर्ष बाद इस मकान में रहने की अनुमति होगी. बक़ाया राशि के भुगतान से पहले कोई अपने मकान में न कोई काम कर सकता है और न उसे किराए पर दे सकता है. इसी तरह इन फ्लैटों की ख़रीद–फ़रोख्त को क़ानूनन अपराध घोषित किया गया है. यही कारण है कि झुग्गीवालों के मन में अनेक शंकाएं पैदा हो गई हैं और वे ख़ुद को परेशानियों में घिरा महसूस करने लगे हैं.

सेक्टर 9 निवासी नसीम अहमद का कहना है कि झुग्गी टूटते ही हज़ारों लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और काम न होने के कारण दो वक़्त की रोटी भी मुश्किल से नसीब हो पाएगी. ऐसी स्थिति में यह कैसे संभव होगा कि हम हर महीने पांच हज़ार रुपये की क़िस्त जमा करें. इसी तरह पंकज का कहना है कि अभी हमारे लिए हर महीने पांच हज़ार रुपये कमाना बहुत मुश्किल काम है. झुग्गी टूटने के बाद फ्लैट की क़िस्त कैसे भरेंगे. हम अपना पेट कैसे पालेंगे और बच्चों को शिक्षा कैसे दिलवाएंगे. सेक्टर 8 निवासिनी हिना कहती हैं कि पांच हज़ार रुपये की क़िस्त का भुगतान हम कैसे करेंगे? नहीं चाहिए हमें फ्लैट, झुग्गी में रहकर अपने पेट की आग बुझा लेंगे. यहीं के यूनुस कहते हैं कि क़ानून शायद हम ग़रीबों के लिए है. जब मन में आया, हमारे लिए क़ानून तैयार कर लिया जाता है. दो वर्ष पहले भी झुग्गी टूटने की हवा थी तो यहां आने–जाने वाले नेताओं ने कहा था कि आप लोगों को 26 गज़ ज़मीन मिलेगी. आप जिस तरह चाहें, अपना मकान बनाएंगे, मगर आज कुछ और हो रहा है. ज़ईफ़ कहते हैं कि हमें मकान नहीं चाहिए, हम यहीं रहेंगे या कोई छोटी सी ज़मीन दे दी जाए, जहां हम कच्चा–पक्का मकान बनाकर तन–बदन छुपा लें.

इन झुग्गीवासियों का कहना उचित है कि वे पांच हज़ार रुपये की मासिक क़िस्त पर फ्लैट कैसे ले सकते हैं. अगर वे इस योग्य होते तो वर्षों पहले दिल्ली के आसपास दो–तीन हज़ार रुपये मासिक क़िस्त पर ज़मीन ले चुके होते. वे अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़मीन का इस्तेमाल करते, क्यों वे झुग्गी में ज़िंदगी गुज़ारते? इन झुग्गीवालों में से 85 प्रतिशत लोग हर महीने पांच हज़ार रुपये नहीं कमा पाते हैं. जिनके पास कुल आमदनी इतनी नहीं है, उनके लिए पांच हज़ार की क़िस्त भरना असंभव है. दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में भी बहुत सी झुग्गियां थीं, मगर वहां सरकार ने उन्हें तोड़ते ही ज़मीन दे दी. वहां झुग्गीवालों को यह अधिकार है कि वे चाहें तो अपनी जगह बेच दें या किराए पर उठा दें, जिस तरह मन में आए मकान बनाएं, लेकिन दिल्ली के पड़ोस में नोएडा के झुग्गीवालों को फ्लैट लेने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है?

सलमान अब्दुस समद
feedback@chauthiduniya.com

अंग्रेज़ों को भारत में शुरू में सबसे अधिक मुसलमानों की ओर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस समय अंग्रेज़ भारत आए, उस समय भारत पर मुसलमानों का शासन था.

सारा माल लूटकर सरकार कहती है मुसलमान दलितों से भी पिछड़े हैं

डॉ. क़मर तबरेज़

भारत पर मुसलमानों ने लगभग 800 सालों तक शासन किया. इस दौरान कहीं पर उन्होंने क़िले बनवाए तो कहीं सरायख़ाने, कहीं मस्जिदें बनवाईं तो कहीं बावड़ियां. इन मुस्लिम बादशाहों की गंगा-जमुनी तहज़ीब से भला कौन वाक़िफ़ नहीं है. भारत में जहां एक ओर अदल जहांगीरी मशहूर है, वहीं दूसरी ओर अकबर की प्रतिष्ठा का सभी लोहा मानते हैं और दारा शिकोह की दूरदर्शिता एवं बुद्धिमानी के चर्चे भी प्रसिद्ध हैं. इन लोगों ने दुनिया भर की दौलत अपने लिए बटोरी. उनके द्वारा छोड़ी गई दौलत सरकार ने पुरातत्व विभाग के हवाले कर दी या फिर अवसर मिला तो उसे ख़ुद ही हड़प लिया अथवा औरों के हाथों लुटवा दिया. नतीजतन मुग़लिया वंश की कोई बहू कोलकाता रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर अपनी ज़िंदगी गुज़ार रही है या फिर इस वंश से संबंध रखने वाले लोग भीख मांगकर अपनी ज़िंदगी गुज़ारने पर मजबूर हैं. कोई उनकी ख़बर लेने वाला नहीं है. क्या इन मुस्लिम शासकों ने ताज महल, लाल क़िला, मोती महल, दीवाने-ए-आम, दीवान-ए-ख़ास और न जाने किन-किन नामों से भवनों के निर्माण इसलिए कराए थे कि उनके वारिस दर-दर की ठोकरें खाते फिरेंगे और उन्हें सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी. क्या दिल्ली के लाल क़िले में औरंगज़ेब द्वारा संगमरमर से बनवाई गई ख़ूबसूरत मोती मस्जिद का निर्माण इसलिए हुआ था कि एक ज़माने के बाद इसमें ताला लगा दिया जाएगा और मुसलमानों को इसमें नमाज़ पढ़ने तक की अनुमति नहीं होगी? पुरातत्व विभाग की निगरानी वाली देश की सभी मस्जिदों का यही हाल है.

अगर केवल दिल्ली की बात की जाए तो यहां वक़्फ़ की इतनी संपत्तियां हैं कि अगर वे मुसलमानों को वापस कर दी जाएं तो उनकी हालत में काफ़ी सुधार हो सकता है. राष्ट्रपति भवन की भूमि वक़्फ़ के नाम से है, प्रधानमंत्री का निवास वक़्फ़ की भूमि पर बना हुआ है, राष्ट्रीय संग्रहालय का निर्माण वक़्फ़ भूमि पर है और न जाने कितनी प्रसिद्ध धरोहरें हैं, जिन पर देश की प्रतिष्ठित हस्तियां आबाद हैं. सराय काले ख़ां के पास अभी हाल में शीला दीक्षित सरकार द्वारा दिल्ली के सबसे बड़े मिलेनियम पार्क का निर्माण किया गया है, वह ज़मीन कभी क़ब्रिस्तान की थी, जिस पर डीडीए ने अवैध क़ब्ज़ा कर लिया. अब हाल यह है कि दिल्ली की अधिकतर जगहों पर मुसलमानों को अपने मुर्दों को दफ़नाने के लिए जगह कम पड़ रही है. ओखला में दिल्ली की एक बड़ी मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन शाहीन बाग़ और अबुल फ़ज़ल इन्क्लेव में मुसलमानों के पास क़ब्रिस्तान का कोई प्रबंध नहीं है. यही हाल मालवीय नगर का है, जहां के मुस्लिम क़ब्रिस्तान पर डीडीए ने अवैध क़ब्ज़ा कर रखा है.

अंग्रेज़ों को भारत में शुरू में सबसे अधिक मुसलमानों की ओर से प्रतिरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि जिस समय अंग्रेज़ भारत आए, उस समय भारत पर मुसलमानों का शासन था. लिहाज़ा अंग्रेज़ों ने जब भारत की बागडोर अपने हाथों में ले ली, तो उन्होंने मुसलमानों को तरह-तरह से परेशान करना शुरू किया. इसके लिए उन्होंने भूमि बहाली अधिनियम पास करके वक़्फ़ की उन जमीनों से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिन पर पहले टैक्स नहीं लगता था. इस प्रकार केवल बंगाल में उन ज़मीनों से 1.1 मिलियन पाउंड की वसूली हुई, जिन पर पहले टैक्स नहीं लगता था. इनमें से अधिकतर ज़मीनें मुस्लिम संगठनों के प्रयोग में थीं, लेकिन अंग्रेज़ों की नीति के कारण सैकड़ों मुस्लिम परिवार तबाह हो गए और उनके शैक्षणिक प्रबंध पर सबसे गहरा असर हुआ, क्योंकि उन्हीं संपत्तियों से मदद मिलती थी. भारत के विभिन्न राज्यों और संघ क्षेत्रों में 4.9 लाख से अधिक रजिस्टर्ड वक़्फ़ संपत्तियां हैं. मसलन पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा 1,48,200 वक़्फ़ संपत्तियां हैं. इसके बाद केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का नंबर आता है. पूरे भारत में वक़्फ़ द्वारा अधिग्रहीत भूमि 6 लाख एकड़ है, जिसका किताबी मूल्य 6,000 करोड़ रुपये है (यह अनुमान आधी सदी पूर्व का है), लेकिन इसकी बाज़ार में कीमत कई गुना अधिक हो सकती है. वर्तमान में बाज़ार के हिसाब से इन संपत्तियों की क़ीमत 1.2 लाख करोड़ रुपये या 12,000 बिलियन डॉलर है. मिसाल के तौर पर केवल दिल्ली में वक़्फ़ की जितनी संपत्तियां हैं, उनकी वर्तमान बाज़ारी क़ीमत 6,000 करोड़ से अधिक है. लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि पूरे भारत में फैली वक़्फ़ की कुल संपत्तियों से वार्षिक आय केवल 163 करोड़ रुपये हो रही है, आख़िर क्यों? वसूली केवल 2.7 प्रतिशत हो पा रही है. अब वक़्फ़ संपत्तियों से जितनी वार्षिक आय होती है, उससे वक़्फ़ बोर्ड को अपनी प्रबंध व्यवस्था चलाने के लिए 7 प्रतिशत राशि दी जाती है. शेष 93 प्रतिशत राशि के बारे में आदेश है कि उन्हें अन्य जरूरी मदों पर ख़र्च किया जाना चाहिए. जैसे,

- शैक्षणिक संस्थान, छात्रावास, पुस्तकालय, क्रीड़ास्थलों का निर्माण, उनकी देखभाल एवं विकास, छात्रवृत्ति जारी करना, ताकि शिक्षा को विकसित किया जा सके.
- सांप्रदायिक दंगों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों समेत सभी ग़रीबों को चिकित्सा और आर्थिक मदद देना.
- मुस्लिम क़ौम के इस्तेमाल के लिए मुसाफिरख़ानों और शादीघरों का निर्माण.
- मस्जिदों, दरगाहों एवं क़ब्रिस्तानों का प्रबंध, तलाक़शुदा महिलाओं के भत्ते का प्रबंध.
- सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक़ इमामों और मुअज़्ज़िन के वेतन का भुगतान.

लेकिन कुछ को छोड़कर वक़्फ़ बोर्ड के अधिकतर उद्देश्यों को अब तक हासिल नहीं किया जा सका है. इसके लिए सरकार और वक़्फ़ बोर्ड के कर्मचारी जिम्मेदार हैं. सरकार ने भी अपनी ओर से मुसलमानों को परेशान करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए हैं. अब मुसलमानों के एक वर्ग की ओर से यह मांग बढ़ती जा रही है कि यूपीएससी की तर्ज़ पर इंडियन वक़्फ़ सर्विसेज़ कमीशन गठित किया जाए, ताकि उसके द्वारा मुसलमानों के बीच से ऐसे शिक्षित लोगों का चयन किया जा सके, जो एक आईएएस अधिकारी की तरह वक़्फ़ संपत्तियों के प्रबंधन को बेहतर ढंग से चला सकें और वक़्फ़ की सभी संपत्तियों को अवैध क़ब्ज़ों से मुक्त करा सकें, लेकिन यूपीए सरकार के नए क़ानून मंत्री सलमान ख़ुर्शीद मुसलमानों की इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हैं.

tabrez@chauthiduniya.com

दिल्ली की दरगाहों पर अवैध क़ब्ज़े

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ऐसे सैकड़ों औलिया-ए-कराम की दरगाहें हैं, जिन्होंने लोगों में भाईचारे और सद्भाव की भावना पैदा की और उन्हें मानवता का पाठ पढ़ाया. उन्होंने मज़हब, जाति, रंग और नस्ल के किसी भेदभाव को कभी सामने नहीं रखा. इन दरगाहों के इर्द-गिर्द कई ऐसी ज़मीनें थीं, जो नेक और दरगाहों से जुड़े लोगों की संपत्तियां थीं, लेकिन बाद में उन पर अवैध क़ब्ज़ा कर लिया गया. दरगाहों की ज़मीनों पर अधिकतर क़ब्ज़े उन हिंदू शरणार्थियों द्वारा किए गए, जो 1947 में भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान से पलायन करके दिल्ली पहुंचे थे. इसके अलावा हिंदू महासभा और विश्व हिंदू परिषद जैसे कट्टरपंथी संगठनों ने भी वक़्फ़ की अधिकतर संपत्तियों पर अपना अवैध क़ब्ज़ा जमा रखा है. मुसलमान तो बेबस हैं, क्योंकि उनमें न तो इन कट्टरपंथी संगठनों से लड़ने की शक्ति है और न सरकार ने सच्चे दिल से कभी उनका साथ दिया.

- ख्वाजा क़ुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से भला कौन वाक़िफ़ नहीं है. क़ुतुब मीनार के रूप में आज भी उनकी यादगार दिल्ली के महरौली क्षेत्र में मौजूद है. इस इलाक़े में उनकी दरगाह भी मौजूद है, लेकिन 1947 में देश विभाजन के बाद इस दरगाह का संरक्षक कोई नहीं रहा. इस पर पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने क़ब्ज़ा कर लिया. 1948 में महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद और पंडित जवाहर लाल नेहरू के हस्तक्षेप से इस दरगाह को अवैध क़ब्ज़ों से मुक्त कराया गया. इसी तरह पुराने क़िले के समीप ककांगर के एनडीएमसी प्राइमरी स्कूल के क़रीब सन् 1245 में बनी बीबी फ़ातिमा साहिब (चिश्ती) की दरगाह है. इस दरगाह के चारों ओर 5000 गज़ से अधिक ज़मीन ख़ाली पड़ी है, जिस पर अब सरकारी स्कूल की तरफ़ से क़ब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा दरगाह के उत्तरी भाग में 100 गज़ ज़मीन पर फूलों की एक नर्सरी भी चल रही है.
- प्रगति मैदान के पास पुराना क़िला रोड पर शेख़ अबुबकर तूसी हैदरी क़लंदर उर्फ़ मटका पीर की दरगाह एक ऊंचे टीले पर है. यहां के सज्जादानशीं ने बताया कि इस दरगाह की कुल 20 बीघा ज़मीन थी, जो क़ब्रिस्तान के नाम पर थी. 1971 में डीडीए ने उस पर क़ब्ज़ा कर लिया और उसे एक पार्क की शक्ल दे दी.
- दिल्ली के नबी करीम, पहाड़गंज में सन् 1376 में बनी दरगाह क़दम शरीफ़ और दरगाहे मख़दूम जहांनयान-ए-जहां गश्त (सहरवर्दी) है. किताबों में कहा गया है कि इस दरगाह में एक पत्थर लगा है, जिस पर पैग़ंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पवित्र क़दमों के निशान हैं. इस पवित्र क़दमों के पत्थर को शेख़ मख़दूम जहांनयान-ए-गश्त फ़िरोज़शाह तुग़लक़ के शासन में अपने सिर पर रखकर यहां लाए थे, लेकिन इस दरगाह पर 1947 के विभाजन के बाद पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थियों ने क़ब्ज़ा कर लिया और इसके विशाल परिसर में मकानों का निर्माण कर लिया. अब इसके अंदर ही बने भवनों का कोई पता नहीं है. उनके ऊपर भी घरों का निर्माण कर लिया गया है. केवल क़दम शरीफ़ की विशेष इमारत अभी सुरक्षित है, जिसे 1951 में अदालत ने दरगाह के सज्जादानशीं पीरजी सलीमुद्दीन को वापस दिलवा दिया था, जिसका गुरुद्वारे के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां से क़दम शरीफ़ का पत्थर उखाड़ कर फेंक दिया गया.
- केलोखरी स्थित दरगाहे सैयद महमूद बहार की भी यही कहानी है. इस दरगाह का एक बहुत बड़ा क़ब्रिस्तान है. दिल्ली नगर निगम ने 16 नवंबर, 1978 को इसे क़ब्रिस्तान के रूप में इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगा दी थी. दरगाह के प्रबंधक फ़तहुद्दीन ने कुछ लोगों के साथ मिलकर 1990 में इस पाबंदी के ख़िलाफ़ अदालत में याचिका दायर की और इसके बाद फ़तहुद्दीन ने समझौता करते हुए 100 गज़ ज़मीन इन लोगों के नाम कर दी. इसके बाद 1992 में डालचंद नामक एक व्यक्ति ने याचिका दायर करके 250 गज़ ज़मीन पर दावा किया. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक मामलों के विभाग के चेयरमैन अब्दुल वासे सलमानी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करके नोटिस जारी कराया कि क़ब्रिस्तान की ज़मीन पर अवैध रूप से बहुमंज़िला इमारत खड़ी की जा रही है, लिहाज़ा उस पर रोक लगाई जाए और ज़मीन मुस्लिम समाज को सौंपी जाए, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक निर्णय नहीं लिया जा सका.
- शेख़ अलाउद्दीन चिश्ती (1467-1541) की दरगाह मालवीय नगर, शेख़ सराय के सावित्री नगर में मकान नंबर 220 के समीप स्थित है. पहले दरगाह का एक बहुत बड़ा परिसर हुआ करता था, लेकिन अब शेख़ अलाउद्दीन के मक़बरे और इससे सटे किसी अज्ञात सूफ़ी बुज़ुर्ग के मक़बरे के अलावा कुछ भी बाक़ी नहीं बचा है. चाहरदीवारी वाले इस विशाल परिसर में स्थित अन्य इमारतें और बेशुमार पक्की क़ब्रें बर्बाद कर दी गईं. इस पर मकान बना लिए गए हैं. शेख़ अलाउद्दीन की दरगाह के अंदर दुकान चल रही है और इससे सटे उनके ख़ानदान के मशहूर बुज़ुर्ग शेख़ फ़ख़्र के मक़बरे के गुंबद के नीचे एक क़ब्र मौजूद थी, लेकिन अब यहां फर्नीचर का कारखाना चल रहा है. यहां अक़ीदतमंद आते हैं, लेकिन उन्हें दरगाह के अंदर दाख़िल नहीं होने दिया जाता, डरा-धमका कर भगा दिया जाता है.
- कनॉट प्लेस से एक किलोमीटर आगे कोइयां रोड पर नेत्रहीनों के स्कूल के पास सैयद हुसैन नुमा की दरगाह है, जिसका निर्माण 1691 में औरंगज़ेब के दौर में हुआ था. अंदर से यह दरगाह बहुत साफ़-सुथरी है, लेकिन इसका बाहरी हिस्सा जो चारों ओर से घिरा हुआ है, उसमें 20 से भी अधिक मुस्लिम परिवार रहते हैं. दरगाह परिसर में ही क़ब्रिस्तान है, जहां विभिन्न सूफ़ी बुजुर्गों की क़ब्रें मौजूद हैं, जो जर्जर हालत में हैं. छोटी-छोटी दरगाहों को लोग निवास के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं. बेशुमार पक्की क़ब्रें बिखरी पड़ी हैं. इसके बहुत बड़े हिस्से पर डीडीए का क़ब्ज़ा है, जिसे पार्क बना दिया गया है. इसी ज़मीन पर नेत्रहीनों के लिए एक स्कूल खोला गया है. बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने यहां अपने कार्यालय और गैराज खोल रखे हैं.
- क़रोल बाग़ के मशहूर हनुमान मंदिर के पीछे भोली भटयारी लिंक रोड पर हज़रत ख़ुदानुमा चिश्ती की दरगाह है, जिसे 1694 में बनवाया गया था. इस दरगाह की निगरानी एक कमेटी करती है, जिसके मुतवल्ली रईसुद्दीन हैं. उनके मुताबिक, इस दरगाह की ज़मीन साढ़े चार बीघा है, जिस पर डीडीए ने क़ब्ज़ा कर रखा है. मुक़दमा जीतने के बाद भी डीडीए ज़मीन ख़ाली नहीं कर रहा है. उसका कहना है कि उसने एक लाख रुपये के पेड़ लगाए हैं, जिसका भुगतान करने के बाद ही वह जमीन पर क़ब्ज़ा देगा. अब समस्या यह है कि सोसायटी के पास इतने पैसे नहीं हैं.
- सफ़दरजंग के मक़बरे के समीप पूर्व की ओर जोरबाग़ रोड है और उसके पूर्व में कर्बला रोड है. कर्बला रोड जहां ख़त्म होती है, वहीं दरगाह शाह-ए-मरदां है. 18वीं सदी में बनी दरगाह शाह-ए-मरदां का एक महत्वपूर्ण स्थान है. इसका कारण यह है कि इस जगह पर मुसलमानों के चौथे ख़लीफ़ा हज़रत अली के क़दमों के निशान एक पत्थर पर हैं. दूसरी ओर इसी जगह पर पैग़ंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद की पुत्री बीबी फ़ातिमा का प्याला, जो पत्थर का है, एक वज्र में रखकर सुरक्षित किया गया है. यह बीबी फ़ातिमा की चक्की के नाम से मशहूर है. मुग़लिया दौर के अंत में दरगाह शाह-ए-मरदां में विभिन्न निर्माण कार्य कराए गए. देश विभाजन के बाद यहां आए शरणार्थियों ने इन पर क़ब्ज़ा करते हुए चाहरदीवारी तोड़ दी और अपने घर बना लिए.

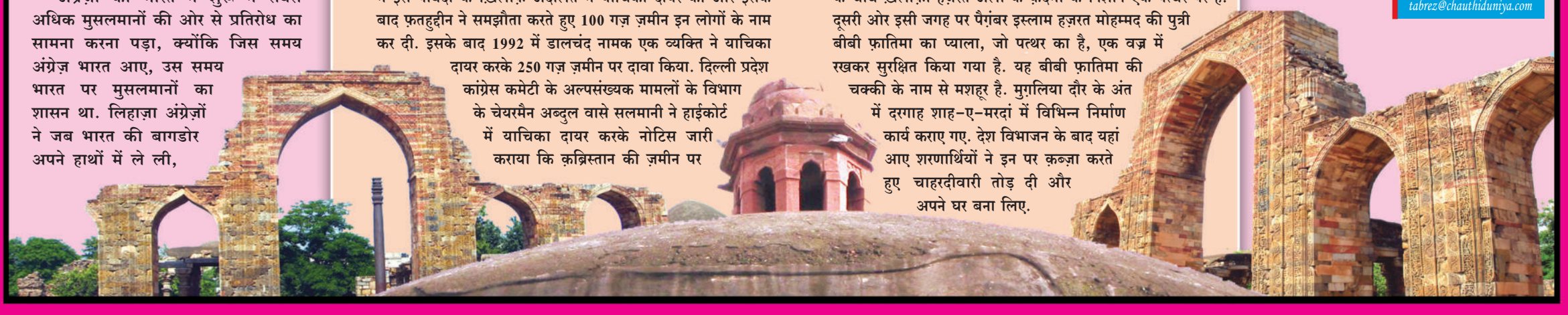

विकास की संवाहक इन परियोजनाओं के लटकने के कई कारण हैं, इनमें जहां-तहां वन भूमि के संदर्भ में क्लियरेंस न मिलना और रैयती ज़मीन के विवाद आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं.

झारखंड

रेल परियोजनाओं की कछुआ चाल

प्रशांत झा

खनिज संसाधनों के मामले में देश के सबसे धनी सूबे झारखंड में शायद ही ऐसी कोई योजना है, जो समय पर पूरी हुई हो. एक वर्ष के भीतर पूरी हो जाने वाली योजनाएं 3 से लेकर 5 साल तक खिंच जाती हैं. योजना के लिए प्राक्कलित राशि भी दोगुनी से तीन गुनी हो जाती है. राजनीतिक अस्थिरता, सुस्त एवं भ्रष्ट अधिकारी-कर्मचारी, असामाजिक तत्वों का हस्तक्षेप और शासन में इच्छाशक्ति का अभाव जैसे कारण इस समस्या के मूल में हैं. झारखंड की जनता का यह दुर्भाग्य है कि यहां राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित अधिकांश विकास योजनाएं अधर में लटक जाती हैं. हम बात कर रहे हैं रेलवे की. राज्य में रेलवे के विकास से जुड़ी कई छोटी-बड़ी योजनाएं पैसेंजर की तरह मंद रफ़्तार से चलने के कारण सफलता के स्टेशन तक नहीं पहुंच सकी हैं.

रेलवे राष्ट्रीय स्तर का महकमा है और विकास का एक अहम मापदंड भी, मगर झारखंड में इसके विकास के पहिए की गति बहुत धीमी है. यहां वर्ष 2002 में इसकी आठ परियोजनाएं शुरू की गई थीं. उनके लिए प्राक्कलित राशि उस समय 1997 करोड़ रुपये थी. कई कारणों से लगभग सारी योजनाएं आज भी लटकी हुई हैं. सूबे में इन आठ नई रेल परियोजनाओं के अतिरिक्त एक अमान (गेज) परिवर्तन, दस दोहरी लाइनें (डबलिंग) और विद्युतीकरण आदि कार्यों पर पिछले तीन वर्षों के दौरान 1055.86 करोड़ रुपये ख़र्च किए जा चुके हैं, परंतु अमान परिवर्तन को छोड़कर सारी की सारी परियोजनाएं-योजनाएं अभी तक अधूरी पड़ी हैं. समस्या यह भी है कि इनके पूरा होने का समय भी निश्चित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वक़्त-बेवक़्त इनकी लागत में उतार-चढ़ाव होते रहते हैं. ऐसा मूल्य सूचकांक और निर्माण के स्टैंडर्ड में बदलाव के कारण भी होता रहता है. सरकार संवेदक की विफलता और क़ानून व्यवस्था की समस्या आगे रखकर परियोजनाओं के पूरा होने में देरी के मुद्दे को सफाई से टाल जाती है.

विकास की संवाहक इन परियोजनाओं के लटकने के कई कारण हैं, इनमें जहां-तहां वन भूमि के संदर्भ में क्लियरेंस न मिलना और रैयती ज़मीन के विवाद आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं. बार-बार इन्हीं बहानों को सरकार द्वारा उलट-पलट कर दोहराया जाता है. बड़ा सवाल यह है कि क्या ऐसा संभव नहीं है कि रेल जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं की जब शुरुआत हो तो कम से कम वन भूमि संबंधी फ़ैसले तुरंत कर लिए जाएं. इससे फायदा यह होगा कि परियोजनाएं लटकेंगी तो नहीं. यह सर्वविदित है कि स्वर्ण रेखा जैसी अत्यंत महंगी, आवश्यक और उपयोगी परियोजना में तक़रीबन तीस वर्षों के लंबे अंतराल के बावजूद अभी तक केवल फुटकर काम हो सका है. इसका कारण यह बताया जाता है कि उसमें वन भूमि संबंधित क्लियरेंस का मामला फंसा है. इन अधूरी परियोजनाओं एवं कार्यों के बीच विभिन्न स्थानों को मिलाकर कुल 113 किलोमीटर रेल लाइन पर अमान परिवर्तन का कार्य किसी प्रकार संपन्न हो जाना एक सुखद संकेत है. रेलवे के विकास से किसी भी राज्य को काफी लाभ हुआ करता है. ख़ासकर, झारखंड के पहाड़ों और जंगलों से आच्छादित पठारी भू-भाग में तो रेलें सामान ढुलाई से लेकर लोगों के आवागमन का सर्वोत्तम ज़रिया हैं. ग्रैंड कार्डलाइन को छोड़ दें तो सीआईसी सेक्शन प्राय: परेशानी में ही रहता है, वहीं राज्य में आधे से अधिक इलाक़े रेल लाइन से अछूते हैं. जिन आठ परियोजनाओं पर काम होना है, अगर वे पूरी हो गईं तो कई ज़िलों की न केवल आपसी दूरियां घट जाएंगी, बल्कि आवागमन भी सरल हो जाएगा. यह तो अब केंद्र और राज्य सरकार दोनों पर निर्भर करता है कि वे इसके लिए कितने प्रभावी क़दम उठाती हैं.

विभिन्न परियोजनाओं के अधूरे कार्य

कहां से कहां तक	दूरी
कोडरमा से तिलैया के बीच रेल लाइन का निर्माण	68 किमी
गया से चतरा के बीच रेल लाइन का निर्माण	97 किमी
गिरिडीह से कोडरमा के बीच रेल लाइन का निर्माण	102.5 किमी
मंदार हिल से रामपुर हाट के बीच रेल लाइन का निर्माण	130 किमी
बांका से भीतिया के बीच रेल लाइन का निर्माण	147 किमी
देवघर-सुल्तानगंज-बांका-बरहेट के बीच रेल लाइन का निर्माण	149 किमी
कोडरमा से रांची के बीच रेल लाइन का निर्माण	189 किमी

अपूर्ण दोहरीकरण कार्य (डबलिंग)

1. बिमलगढ़-राजाबेड़ा
2. चंद्रपुरा-भंडारडीह
3. गोयलकेरा-मनोहरपुर
4. पाड़ा पाथर-बनासपानी
5. राजखरसावां-सोनी
6. तीन पाथर-भागलपुर
7. डागापासी-राजखरसावां
8. सीनी-आदित्यपुर
9. साहिबगंज-पीरपैंती
10. मुरी नॉर्थ आउटर केबिन के पास से स्वर्ण रेखा नदी के ऊपर दूसरे पुल तक

नक्सलियों की दखलंदाज़ी

प्रदेश के लिए नासूर बन चुका नक्सलवाद रेल परियोजनाओं के पूरा होने में सबसे बड़ी बाधा साबित हो रहा है. नक्सलवादी इन परियोजनाओं के कार्य में खलल डालते हैं, लेवी लेने के लिए अक्सर कामगारों की पिटाई करते हैं, जिससे सारा कामकाज ठप्प हो जाता है. अभी हाल में नक्सलियों ने कोडरमा-हजारीबाग-रांची रेल परियोजना के एक मुंशी की हत्या कर दी. नक्सलियों के फरमानों की अनदेखी करने वाले ठेकेदारों एवं कामगारों पर जब-तब हमले होते रहते हैं. उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर, 2005 को रीच नंबर दस पर एरिया कमांडर कृष्णा यादव के नेतृत्व में माओवादी दस्ते ने छह डंफर और एक पोकलेन मशीन को फूंक दिया, जिनकी अनुमानित राशि लगभग 2 करोड़ रुपये बताई गई. इस घटना के महज़ छह माह बाद मई 2006 में मंझगावा स्थित रीच नंबर पांच में जेएलटी प्रमुख सिकंदर यादव के नेतृत्व में दो रोलरों, पांच डंफरों, दो जेसीबी मशीनों और चार ट्रैक्टरों को आग के हवाले कर दिया गया. परिणामस्वरूप तक़रीबन चार करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. इसी तरह 29 मई, 2008 को बेस रेशाम स्थित रीच नंबर 21 पर माओवादियों ने रेलवे के चार कामगारों की पिटाई करने के साथ-साथ लगभग तीन करोड़ रुपये की संपत्ति फूंक दी. एक पखवारे के बाद उसी रीच पर नक्सलियों ने फिर आगजनी की घटना को अंजाम दिया, जिसमें क़रीब एक करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. 5 अप्रैल, 2009 को रीच नंबर तेरह में पुन: कृष्णा यादव के नेतृत्व में माओवादियों ने चार हाइवा, चार डंफरों और तीन पोकलेन को आग के हवाले कर दिया. इस घटना में लगभग पांच करोड़ रुपये का नुक़सान हुआ. 17 अक्टूबर, 2010 को भी नक्सलियों द्वारा रेलवे परियोजना में काम कर रहे लोगों की पिटाई करने का मामला प्रकाश में आया. नक्सलियों द्वारा लेवी वसूलने के उद्देश्य से अंजाम दी जाने वाली इस तरह की घटनाएं रेलवे की विभिन्न परियोजनाओं पर व्यापक असर डालती हैं.

feedback@chauthiduniya.com

मेरी दुनिया.... प्रधानमंत्री और महंगाई!

मई माह में मनोहर प्रखंड के वीरेंद्र कंडुलना ने अपनी पत्नी मुनिका कंडुलना के कहने पर फ़रसे से अपनी चचेरी भाभी रशांती कंडुलना का सिर धड़ से अलग कर दिया.

डायन प्रथा
जीने का हक़ मत छीनो

फ़िरदौस ख़ान

इंसान भले ही दूसरे ग्रहों पर जीवन तलाश रहा है, लेकिन दुनिया में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है, जो महिलाओं को डायन बताकर उन्हें मौत के घाट उतारने में पीछे नहीं रहते. महिलाओं को डायन क़रार देकर उनके साथ अमानवीय व्यवहार करना, उन्हें निर्वस्त्र घुमाना, जबरन अपशिष्ट पदार्थ पिलाना, उनकी आंखें फोड़ देना, उनके साथ दुराचार करना, उनके बाल काटना या सिर मुंडवा देना आदि मामले अक्सर सुर्ख़ियों में आते हैं और उसी तेज़ी के साथ ग़ायब भी हो जाते हैं, लेकिन ऐसी घटनाएं पीड़ित महिलाओं के पारिवारिक ही नहीं, बल्कि उनके सामाजिक जीवन को भी तहस-नहस करके रख देती हैं. वे मानसिक एवं शारीरिक कष्ट झेलने को मजबूर हो जाती हैं. भारत में भी ऐसे मामले सामने आते रहते हैं. पिछले माह अगस्त में राजस्थान के जोधपुर ज़िले के पाली के केशव नगर में डायन निकालने के नाम पर महिला नारंगी को उसकी जेठानी एवं अन्य परिवारीजनों ने न केवल चिमटे से जलाया, बल्कि उसे दहकते अंगारों पर बैठा दिया गया. इस दौरान महिला के शरीर पर अंगारे भी रखे गए. महिला के परिवारीजन उसे बचाने के बजाय जयकारे लगा रहे थे. जयकारों की आवाज़ सुनकर कुछ लोग वहां पहुंचे और उन्होंने यह ख़ौफ़नाक मंज़र देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने वहां पहुंच कर महिला को छुड़ाया और अस्पताल में दाख़िल कराया. जानकारी के मुताबिक़, केशव नगर निवासी पुखाराम मेघवाल मज़दूरी करता है. उसकी पत्नी ने दस दिनों तक अपने घर में दशा माता की पूजा के लिए एक कमरे को मंदिर का रूप देते हुए पूजा-पाठ की सारी व्यवस्था की थी. पूजा-पाठ में उसने अपनी तीन बच्चियों और एक अन्य महिला को भी बैठा रखा था. पुखाराम का छोटा भाई चुन्नीलाल रानी गांव में रहता है, उसकी शादी को 15 साल हो गए, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं हुई. परिवार के लोगों को अंदेशा है कि उसकी पत्नी नारंगी में किसी डायन की आत्मा घुसी हुई है. डायन को बाहर निकालने के लिए चुन्नीलाल को पत्नी सहित पाली बुलाया गया था. इसी माह राजस्थान के उदयपुर ज़िले के गांव पुनाली में 50 वर्षीय जसु कुंवर के साथ मारपीट की गई, उसके बाल काटे गए और उसे जबरन अपशिष्ट पदार्थ पिलाया गया. साथ ही उसे ख़ुद को डायन स्वीकार करने के लिए मजबूर भी किया गया. महिला का पति गोपाल सिंह डाबी गूंगा-बहरा है. उसकी बेटी गजु कुंवर की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया.

इसी तरह अगस्त में ही बिहार के मोतिहारी ज़िले के गांव तेलहिया में 50 वर्षीय महिला रंभा देवी को डायन बताकर जबरन मैला पिलाया गया. इससे पहले आधी रात को गांव के ही कुछ लोग उसके घर में घुस गए और उसके साथ मारपीट की. घटना के बाद महिला ने रोते-बिलखते हुए लोगों को आपबीती सुनाई. इसके बाद उसे पुलिस थाने ले जाया गया और आरोपियों के ख़िलाफ़ डायन अधिनियम रोकथाम की धारा 3/4 के तहत मामला दर्ज किया गया. जुलाई में झारखंड के लोहरदगा के गांव मुर्की तोड़ार के 60 वर्षीय ठकरू उरांव और उनकी 55 वर्षीय पत्नी तेतरी उरांव की लाठी-डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई. उन पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर उनके साथ मारपीट की गई. जानकारी के मुताबिक़, गुड़िया टोली निवासी बुधराम उरांव की 55 वर्षीय मां बिजो उरांव की मार्च में मौत हो गई थी. इसके 15 दिनों बाद बुधराम की नवजात बच्ची और फिर उसके एक माह बाद 10 वर्षीय बेटे निवास उरांव की पेड़ से गिरकर मौत हो गई थी. कुछ दिनों बाद उसके पांच वर्षीय बेटे नीरज उरांव की भी किसी ज़हरीले जीव के काटने से मौत हो गई. इस हादसे के बाद बुधराम ने ठकरू दंपत्ति पर डायन बिसाही का शक ज़ाहिर किया और किसी ओझा से संपर्क साधा. ओझा के कहने पर उसने अखाड़े में बैठक कर वृद्ध दंपत्ति को घर से बुलाया और फिर उनकी हत्या कर दी. दंपत्ति की बेटी सालो कुमारी ने पुलिस को इसकी जानकारी दी. जुलाई में ही हंटरगंज के गांव चिरैयाटांड के ओझा जीतन मांझी और उनकी पत्नी कपूरवा देवी की धारदार हथियारों से काटकर हत्या कर दी गई. उन पर भी डायन बिसाही का आरोप लगाया गया. बाद में दोनों के शवों को गांव में ही आग के हवाले कर दिया गया. जून में गुमला ज़िले के गांव नवगाई में विधवा ऐतवारी देवी पर डायन होने का आरोप लगाकर कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी. इतना ही नहीं, हत्यारों ने शव के टुकड़े-टुकड़े कर उसे पकाया और खाया भी. घटना के वक़्त महिला का बेटा अवध नायक भी मौजूद था, वह किसी तरह भागकर जान बचाने में कामयाब रहा. उसने पुलिस को इस दिल दहला देने वाले हादसे की जानकारी दी.

मई माह में मनोहर प्रखंड के वीरेंद्र कंडुलना ने अपनी पत्नी मुनिका कंडुलना के कहने पर फ़रसे से अपनी चचेरी भाभी रशांती कंडुलना का सिर धड़ से अलग कर दिया. उसने अपने चचेरे भाई दयाल कंडुलना पर भी हमला करके उसे जख्मी कर दिया. पुलिस के मुताबिक़, कंडुलना के दो वर्षीय बेटे की एक सप्ताह पहले मौत हो गई थी. इस पर मुनिका ने रशांती को डायन बताते हुए उसे बेटे की मौत के लिए ज़िम्मेदार ठहराया. गांव अरसंडे बोड़ेया की बसंती देवी को डायन बताकर उसके साथ भी मारपीट की गई. उसके कान से बालियां भी खींच ली गईं, जिससे उसका कान फट गया. पीड़िता का कहना है कि आरोपी उसे हमेशा डायन कहकर ही पुकारते हैं. जनवरी में दुमका ज़िले के गांव घोड़ाबांध में एक व्यक्ति ने अपनी 45 वर्षीय मां सांझली देवी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी. विशु नामक इस व्यक्ति के दो बच्चे थे. कुछ दिनों पहले किसी अज्ञात बीमारी से दोनों की मौत हो गई थी. बच्चों की मौत से दु:खी विशु को लग रहा था कि उसकी मां के कारण ही बच्चों की मौत हुई है. उसे अपनी मां पर डायन होने का संदेह था. इसलिए उसकी अपनी मां से अक्सर लड़ाई भी होती रहती थी. मार्च माह में उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले के जामपानी गांव में दो महिलाओं पहवा और जासो देवी को डायन बताकर उनके साथ मारपीट की गई. इसके बाद उनके जख्मों पर मिर्च भी छिड़की गई. महिलाओं के मुताबिक़, वे घर जा रही थीं, तभी रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और इस क़दर पीटा कि उनके शरीर पर गहरे जख्म हो गए. बाद में उन्हें कमरे में बंद कर दिया गया. ख़ास बात यह कि इस दौरान लोग तमाशबीन बने रहे और कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया. मई माह में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के नज़दीकी गांव सौरा में एक दंपत्ति पर डायन बिसाही का आरोप लगाकर उनकी आंखें फोड़ दी गईं. कुछ लोगों ने प्रौढ़ा श्याम कुंवर और उसके पति पर हमला बोल दिया. दंपत्ति के हाथ-पैर बांधकर कैंची से उनकी आंखें फोड़ दीं. इतना ही नहीं, महिला की जीभ भी काट दी गई. लोगों का आरोप है कि गांव में आने वाली विपत्तियों के लिए यही दंपत्ति ज़िम्मेदार है. लोग दंपत्ति को लहूलुहान छोड़कर फ़रार हो गए. गांव के ही एक व्यक्ति ने पुलिस को हादसे की जानकारी दी.

ग़ौरतलब है कि झारखंड में पिछले क़रीब एक दशक में डेढ़ हज़ार से ज़्यादा लोगों की जानें जा चुकी हैं, साथ ही डायन प्रताड़ना के क़रीब 12 सौ मामले दर्ज हुए हैं. डायन प्रताड़ना के सबसे ज़्यादा 150 मामले गढ़वा में दर्ज किए गए, जबकि हज़ारीबाग़ में 113, पलामू में 106 और दुमका में 100 मामले दर्ज किए गए. 2008 में सबसे ज़्यादा 170 मामले दर्ज हुए, जबकि 2009 और 2010 में 150-150 मामले दर्ज किए गए. डायन प्रताड़ना के मामले हज़ारीबाग़, छतरपुर, सदर, पाटन, गुमला, घाटशिला, पालकोट, मुसाबनी, सिसई, घाघरा, डुमरी, रायडीह, कोलेबिरा, लातेहार, लिटीपाड़ा, महेशपुर, भंडरिया, रंका, विश्रामपुर, चक्रधरपुर, धनवार, खरसांवा, बरही, टीटानगर आदि में ज़्यादा दर्ज किए गए हैं. ग़ैर सरकारी संस्था आशा के मुताबिक़, झारखंड में 1991 से मार्च 2006 के बीच चाईबासा में 117, गुमला में 100, लोहरदगा में 127, पलामू में 60, हज़ारीबाग़ में 36, सिमडेगा में 35, सरायकेला में 34, जमशेदपुर में 18, गढ़वा में 17, देवघर में 16, गिरिडीह में 15, कोडरमा में 15, साहेबगंज में 14, बोकारो में 12, दुमका में 11, गोड्डा में 11, चतरा में 10 और धनबाद में छह महिलाओं को डायन बताकर उनकी हत्या कर दी गई. मार्च 2006 से सितंबर 2007 तक 115 महिलाओं को मार दिया गया. इसी तरह 2008 में 43, 2009 में 31 और 2010 में जून तक 19 महिलाओं को मौत के घाट उतारा गया.

बीते माह जुलाई में राजस्थान हाईकोर्ट ने डायन के नाम पर महिलाओं को प्रताड़ित करने के मामले में राज्य सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया था. मुख्य न्यायाधीश अरुण मिश्रा एवं न्यायाधीश बेला एम त्रिवेदी की खंडपीठ ने यह अंतरिम आदेश नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन वूमेन की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया. याचिका में कहा गया था कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों सहित टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर में अधिकतर तलाक़शुदा या अकेली महिलाओं को डायन ठहराकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है. नेशनल वूमेन कमीशन की 2004 की रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्य में 400 महिलाओं को डायन मानकर उन्हें प्रताड़ित किया गया. अन्य राज्यों में इस प्रथा को रोकने के लिए क़ानून हैं. राज्य महिला आयोग ने भी 2005 में क़ानून बनाए जाने की जरूरत पर बल दिया था. दरअसल, डायन प्रथा की जड़ें इतनी गहरी हैं कि इससे प्रभावित इलाक़ों में प्रशासन द्वारा शिविर आदि लगाकर लोगों को जागरूक करने की सारी क़वायद धरी की धरी रह जाती है. डायन प्रथा के पीछे कई कारण हैं, जिनमें विधवा महिलाओं को परिवार की संपत्ति से बेदख़ल करना, आपसी रंजिश और उनका शारीरिक शोषण करना आदि शामिल हैं. जिन लड़कियों का शोषण करना होता है, पहले उनकी मां को डायन घोषित कर दिया जाता है, फिर उस महिला के साथ सहानुभूति जताते हुए उसकी बेटियों को नौकरी दिलाने के नाम पर शहर लाकर बेच दिया जाता है. आंकड़ों के मुताबिक़, झारखंड में पिछले तीन सालों में एक लाख 23 हज़ार महिलाएं और लड़कियां ग़ायब हो गईं. तस्करी का शिकार होने वालों में 77 फ़ीसदी आदिवासी महिलाएं हैं. इनमें 67 फ़ीसदी 20 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं. 65 महिलाएं फ़ीसदी अशिक्षित हैं. लड़कियों की तस्करी करने वालों में 53 फ़ीसदी पुरुष और 47 फ़ीसदी महिलाएं शामिल हैं. 53 फ़ीसदी मामलों में तस्कर लड़कियों को नौकरी का लालच देते हैं, जबकि 13 फ़ीसदी मामलों में लड़कियों को जबरन बेचा जाता है. 17 फ़ीसदी मामलों में लड़कियों के अभिभावकों को लालच देकर राज़ी किया जाता है.

ग़ैर सरकारी संस्था रूरल लिटिगेशन एंड एनटाइटिलमेंट सेंटर की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में हर साल 150-200 महिलाओं की डायन बताकर हत्या कर दी जाती है. पिछले 15 सालों में देश में डायन के नाम पर क़रीब ढाई हज़ार महिलाओं की जान ली जा चुकी है. राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक़, महिलाओं को डायन बताकर मारने के मामले में झारखंड का स्थान सबसे आगे है. यहां हर साल 50 से 60 महिलाओं की डायन कहकर हत्या कर दी जाती है. दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश है, जहां क़रीब 30 महिलाएं हर साल अंधविश्वासी लोगों का शिकार बन जाती हैं. इसके बाद उड़ीसा का स्थान आता है, जहां हर साल 24-28 महिलाओं को मौत के घाट उतार दिया जाता है. डायन प्रथा उन्मूलन के लिए काम कर रही संस्थाओं का अनुमान है कि लोकलाज, मजबूरी और दबाव के कारण क़रीब 70 फ़ीसदी मामले सामने नहीं आ पाते. बहरहाल, डायन प्रथा की आड़ में महिलाओं से उनका सम्मान से जीने का हक़ छीना जा रहा है, जिसे रोके जाने की ज़रूरत है.

firdaus@chauthiduniya.com

डायन प्रतिषेध क़ानून

डायन प्रतिषेध क़ानून 1999 से लागू है. इसके मुताबिक़, किसी महिला को सिर्फ़ डायन क़रार देने पर संबंधित व्यक्ति को तीन माह की क़ैद की सज़ा हो सकती है. साथ ही एक हज़ार रुपये जुर्माना भरना पड़ सकता है. किसी महिला को डायन क़रार देकर उसका शारीरिक या मानसिक शोषण करने वाले व्यक्ति को छह माह की क़ैद अथवा दो हज़ार रुपये जुर्माने का प्रावधान है. महिला को डायन बताकर उसका दुष्प्रचार करने अथवा इस कार्य के लिए लोगों को उकसाने वाले व्यक्ति को तीन महीने के सश्रम कारावास के साथ-साथ एक हज़ार रुपये जुर्माने का प्रावधान है.

कांग्रेस निस्सहाय दिखाई पड़ी. सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस की रणनीति लगातार बदलती रही.

शर्मिला का आंदोलन 11 साल से जारी है, मगर आज तक राज्य और केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं की. शर्मिला की मांग पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है.

महावीर प्रसाद आर मोरारका

ग़रीबों के हितैषी होने का भ्रम

सवाल उठता है कि धनिकों का प्रभाव जब इस तरह से प्रजा के दिमाग़ पर ठोक-पीटकर बैठाया जाता है और वह अवांछनीय भी है तो लोग इसे बर्दाश्त क्यों करते हैं? क्यों न इसके विरुद्ध विद्रोह खड़ा होता है? ठीक है, पर यह पूंजीवादी ज़हर आपको, हमको इस तरह पिलाया जा रहा है और हम ख़ुशी-ख़ुशी पी लेते हैं कि हम यह महसूस भी नहीं कर पाते कि इसमें उन धनिकों का कुछ दोष भी है. मनुष्य ज़्यादातर प्रत्यक्ष से प्रभावित होता है, परिणाम को सोचने-समझने का प्रयत्न बहुत कम आदमी करते हैं. प्रत्यक्ष में ये समृद्ध व्यक्ति देवता स्वरूप रहते हैं. जहां कहीं बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचानी है तो सर्वप्रथम दान देने के लिए ये लोग हाज़िर रहेंगे. महामारी या अन्य कोई भी दैवीय विपत्ति आई कि इन लोगों की तरफ़ से राहत का कार्य चालू हो जाएगा. यों भी धर्मशालाएं, कुएं, बावड़ी, धर्मशाला, स्कूल एवं अस्पताल आदि सार्वजनिक कार्य या संस्थाएं ये धनिक अपने धन का कुछ अंश ख़र्च करके चलाते ही रहते हैं. इनकी इस उदारता से प्रत्यक्ष में प्रभावित होकर जनता सहर्ष इनको अपना हितैषी मान लेती है और इनके विरुद्ध विद्रोह की बात तो अलग, उल्टे इनके गुणगान जगह-जगह होते रहते हैं.

ये लोग नहीं जानते कि आख़िर प्लेग या महामारी होती क्यों है, दवाखाने या अस्पताल क्यों चाहिए, धर्मशालाओं की आवश्यकता ही क्या है, इन सबका मूल कारण है इन्हीं के द्वारा ग़रीब जनता का शोषण. यह शोषण कई तरीक़ों से होता रहता है. ग़रीब प्रजा को पेट भर अच्छा भोजन खाने को न मिले, बच्चों को दूध न मिले तो स्वाभाविक ही है, उनकी शारीरिक क्षमता धीरे-धीरे क्षीण होती जाएगी और भारी से भारी संख्या में लोग क्षय जैसे भयानक रोग से पीड़ित होंगे. जब इन ग़रीबों को अपना गुज़र-बसर लायक वेतन या मज़दूरी न मिले और वे रोगों के शिकार बनते रहें, फिर भी धनिकों की कोशिश रहती है कि ज़रा भी वेतन या मज़दूरी न बढ़ने पाए. अपने शौक को पूरा करने के लिए ये धनिक अपनी हवेली के लिए या अपनी प्रेयसी के लिए 500 रुपये की बनारसी साड़ी ख़रीद देगा या हीरे का नेकलेस 10 हज़ार में ला देगा. यह कभी नहीं सोचेगा कि यही धन 10 या 20 ग़रीब बालकों को असामयिक मृत्यु के मुख में जाने से बचा सकता था. आप शायद समझते होंगे कि मृत्यु तो भगवान के हाथ में है. जस, अपजस, जीवन-मरण विधि हाथ, यह गोस्वामी जी की चौपाई हर आदमी की ज़ुबानी सुनी होगी. आम जनता की यही धारणा है कि आदमी की उम्र की सांसें या दिन भगवान के यहां से उसके तक़दीर में लिखे जाते हैं. उसमें कोई एक मिनट या घंटा घटा-बढ़ा नहीं सकता. मन को आश्वासन देने का यह बड़ा अजीब ढंग है. जब बात बीत चुकी है, झट कह दिया जाता है, यही लिखा था-विधाता के लेख को कौन मिटा सकता था. बड़ी ही पराजय की भावना है. आज के युग में यह सिद्ध हो गया है कि मानव अपने जीवन चक्र या प्रवाह को अच्छी तरह आयोजित कर ले तो जीवन और मरण दोनों पर बहुत हद तक क़ाबू पाया जाना संभव है.

शहरों या गांवों में हर जगह जहां अत्यंत दरिद्रता का वातावरण हो, वहां बाल मृत्यु दर बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जबकि अच्छे मोहल्लों में जहां खान-पान, साफ़-सफ़ाई का बहुत ध्यान रखा जाता है, बाल मृत्यु दर क़रीब-क़रीब नहीं के बराबर है. जिन देशों में या देश के उन हिस्सों में जहां बहुत ज़्यादा दरिद्रता विद्यमान है, आदमी की औसत उम्र बहुत कम रहती है. जैसे-जैसे देश की आर्थिक स्थिति सुधरती है, मनुष्य का जीवन स्तर थोड़ा-थोड़ा ऊंचा होता है और औसत उम्र बढ़ती जाती है. आज से 30 वर्ष पहले भारत में मानव की औसत उम्र 27 वर्ष की मानी जाती थी. सारे भारतवर्ष की जनगणना के आंकड़े सिद्ध करते हैं कि जितनी ग़रीब और युवा मृत्यु उस समय होती थी, उसके फलस्वरूप यह औसत उम्र इतनी कम 27 वर्ष की ही गिनी गई थी. औसत आयु का यह स्तर संसार के किसी दूसरे देश में शायद नहीं था. मूल कारण था आर्थिक पराधीनता, जीवन स्तर एकदम निम्न कोटि का होना, खान-पान के लिए कोई उचित व्यवस्था का न होना इत्यादि. आज 30 वर्ष में इतना फ़र्क़ हो गया है कि औसत उम्र 36 वर्ष की गिनी जा रही है. हालांकि अनाज की क़ीमत चौगुनी से भी ज़्यादा हो गई है, अन्य आवश्यक चीज़ों की क़ीमतें भी बहुत बढ़ गई हैं, फिर भी चूंकि जीवन स्तर कुछ-कुछ सुधर रहा है, मानव की औसत उम्र बढ़ गई है. क्या विधाता ने यही निश्चय किया था कि सन 1960 के बाद 36 वर्ष की औसत उम्र भारतवासियों की रहेगी और 30 वर्ष पहले 27 वर्ष की ही रहनी थी?

ये बीमारियां, महामारी या भुखमरी सब इन्हीं धनिकों की कृपा है. अगर वित्त वितरण समानता का कुछ भी ढंग इन्हें स्वीकार होता तो ऐसी परिस्थिति शायद कभी पैदा ही न होने पाती. इसी तरह से धर्मशालाओं की क्या ज़रूरत है? मानव को मुफ़्त में ठहरने के लिए या रहने के लिए कुछ स्थान क्या, जो अधिकतर गंदा और हल्के प्रकार का ही होता है, ये धनिक बंदोबस्त कर देते हैं. शहरों या क़स्बों में इनकी बनाई हुई धर्मशालाएं या सराएं मौजूद हैं, यात्री वहां 2-4 दिन मुफ़्त में ठहर सकते हैं. कई स्थानों पर इन्हीं धनिकों ने अन्न क्षेत्र भी खुलवा रखे हैं, जहां लोगों को मुफ़्त में खाने को मिल जाता है. ऐसी अनेक छोटी-छोटी सुविधाएं इन धनिक लोगों ने कई स्थानों पर आम जनता के लिए बना रखी हैं. इनका प्रत्यक्ष असर लोगों के दिमाग़ पर यही होता है कि ये बड़े उदार और भले व्यक्ति हैं. तभी उनके यशोगान होने लगते हैं. असल तथ्य पर कोई विचार नहीं करता कि अगर वहां धर्मशाला न होती तो यात्री अपने ख़र्च से कोई होटल में या किसी घर में उचित भाड़ा देकर ठहरते. अगर अन्न क्षेत्र न हो तो वह अपने आप किसी बासे में जाकर या किसी हलवाई की दुकान से क़ीमत देकर खाद्य वस्तु प्राप्त करके खाएगा. ऐसा करने में उसे जो व्यय होगा, उसका प्रबंध करने के लिए वह काम करेगा, संघर्षशील बनेगा, देश के लिए एक उपादेय वस्तु बन जाएगा, जबकि इसके विरुद्ध उसके आलसी और अकर्मण्य बन जाने की संभावनाएं ज़्यादा हैं. यह सब इन धनिकों की तथाकथित उदारता की बदौलत ही है.

इसी तरह जो छोटी-छोटी उदारता ये समृद्ध लोग प्रत्यक्ष में करते हैं, उसके पीछे उनका घोर स्वार्थ छिपा रहता है और जिसके बल पर वे लोकेषणा प्राप्त करते हैं. असल में प्रजा पर यह भयंकर भ्रम पैदा हो जाता है कि ये बड़े भले आदमी हैं. नतीजा यह होता है कि इन सबके विरुद्ध विद्रोह की भावना किसी के दिमाग़ में भी नहीं आती. इन धनिकों या समृद्धों में कई अच्छे व्यक्ति भी हैं, पर उन्हें यह मालूम ही नहीं होता कि उनके द्वारा किए गए तथाकथित दान-पुण्य या उदार कर्मों का वास्तविक असर जनता पर क्या पड़ता है? अगर उन्हें मालूम हो भी जाए तो वे परिणामजनक अच्छे कार्य भले ही करें, पर उन जघन्य कार्यों को तो नहीं करेंगे. असल में ये व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से बुरे नहीं हैं, इनकी यह पूंजीवादी प्रथा ही बुरी चीज़ है, जिसके संबंध में मैंने यह सब कहा है.

समृद्धों या धनिकों की देखादेखी अन्य साधारण व्यक्ति भी ऐसा करना चाहते हैं. अगर ये अपनी स्त्री को 500 रुपये की साड़ी पहनाते हैं तो तमन्ना इनकी भी कुछ ऐसी ही होती है. रुपया प्राप्त करने के लिए ये कोई सरल या सहज तरीक़ा ढूंढ़ते हैं. जो सीधा मार्ग उनकी समझ में आता है, वह है जुआ. हर शहर में, हर गांव में आंकफरक, वर्षा, बादल या अन्य किसी न किसी प्रकार का जुआ चलता ही रहता है. इन सब जुओं में साधारण व्यक्ति हमेशा नुक़सान ही उठाता है. दैनिक मज़दूरी करने वाला मज़दूर या वेतनभोगी कार्यकर्ता इस लत में पड़कर हर महीने 10-20 रुपये या कम-ज़्यादा ह्रास उठाता ही है. कदाचित किसी एक व्यक्ति को हज़ार-पांच सौ रुपये प्राप्त हो जाएं. ऐसी ही आशा में तो लोग हमेशा आंकफरक या अन्य जुआ खेलते ही रहते हैं. जो मध्यवर्गीय समृद्ध पुरुष या धनिक लोग सट्टे में, वे हमेशा फ़ायदे में रहते हैं. यह भी एक व्यसन है, जिसके परिणामस्वरूप ग़रीब और अधिक ग़रीब होता जाता है और धनिक और अधिक धनवान होता है.

भगवान ने बुद्धि का परिमाण शायद बहुत से ग़रीब बालकों को भी दिया है, जितना धनिक या समृद्धों को. फिर भी अवसर न मिल सकने की वजह से ग़रीब की बुद्धि पूर्ण विकसित नहीं हो पाती और शिक्षा अधूरी रह जाने की वजह से देश की होने वाली इस एक महान संपत्ति या धरोहर से समाज वंचित रह जाता है. धनिक बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करके अपनी बुद्धि के विकास का अवसर प्राप्त कर लेता है, उसे चमकाते देर नहीं लगती. पर धनिकों या समृद्धों में भी उसी अनुपात से मूर्ख या ठस बालक भी होते हैं जो अवसर मिलने पर भी न तो शिक्षा ही पूरी पा सकते हैं, न उनकी बुद्धि ही विकसित होती है, क्योंकि उनमें नैसर्गिक बुद्धि ही होती है. ऐसी ही त्रुटि वाले बालक ग़रीब वर्ग में भी होते हैं, उनको तो ख़ैर कोई पूछता ही नहीं, पर जो बुद्धि या प्रखर प्रज्ञा वाले बालक ग़रीब वर्ग में होते हैं, उन्हें अवसर न मिल सकने की वजह से पिछड़ जाना पड़ता है. अगर समान वित्त वितरण हो सकता तो देश की यह परोक्ष संपत्ति या धरोहर ख़ूब पनपती, पुष्पित या पल्लवित होती, यों बेकार नष्ट न हो पाती.

महावीर प्रसाद आर मोरारका का जन्म 12 अगस्त, 1919 को नवलगढ़ (झुंझनू) राजस्थान में हुआ था. उद्योगपति, स्वप्नदृष्टा और लेखक से कहीं अधिक वह उदात्त मानवीय मूल्यों के संवाहक थे. उनकी गणना भारत के प्रमुख उद्योगपतियों में की जाती है.

feedback@chauthiduniya.com

संतोष भारतीय

जब तोप मुक़ाबिल हो

राहुल जी, यह वक़्त बहुत महत्वपूर्ण है

अन्ना हजारे का आंदोलन सारे देश की चेतना को उभार रहा था. गली-गली, मैदान-मैदान, हर जगह आंदोलन हो रहे थे. ऐसे समय में संसद के ऊपर ज़िम्मेदारी थी कि वह कोई हल निकाले, लेकिन संसद अन्ना हजारे के आंदोलन के ख़िलाफ़ खड़ी नज़र आई. उस समय यह ज़रूर लग रहा था कि अगर सोनिया गांधी यहां होतीं तो वह शायद कोई हल निकालने में पहल कर पातीं. कर पातीं या न कर पातीं, पता नहीं, लेकिन लोगों को लग रहा था कि एक ऐसा केंद्र था, जो शायद कोई रास्ता निकालने में महत्वपूर्ण रोल निभा पाता, पर सोनिया गांधी अपनी बीमारी की वजह से देश में नहीं थीं. उनका देश में न होना कांग्रेस के लिए थोड़ा संकट पैदा कर गया. ऐसे समय में राहुल गांधी के ऊपर लोगों की निगाहें थीं. राहुल गांधी ने जब संसद में भाषण दिया, कांग्रेस के लोगों ने उनका समर्थन किया. राहुल गांधी के भाषण में कोई रास्ता नहीं था, कोई समाधान नहीं था. वह बस एक भाषण था. उस भाषण में दूरंदेशी भी नहीं थी. उन्होंने जो सवाल खड़े किए, उनसे यह ध्वनि निकली कि राहुल गांधी भ्रष्टाचार से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि यह तर्क कि क्या एक लोकपाल बनने से भ्रष्टाचार ख़त्म हो जाएगा, यह भ्रष्टाचार के पक्ष में खड़ा हुआ तर्क है. उन्हें और रास्ते सुझाने चाहिए थे कि इन-इन से भ्रष्टाचार ख़त्म होगा, लेकिन वे रास्ते राहुल गांधी ने नहीं सुझाए.

दरअसल, देश के लोग यह चाह रहे थे और जो मौक़ा राहुल गांधी ने गंवाया, वह यही ऐतिहासिक मौक़ा था. देश को कांग्रेस पार्टी से एक ऐसे नेतृत्व की उम्मीद थी, जो विचारधारा का आधार लेकर देश से कुछ नई बातें कहे. यह मौक़ा था, जिसमें राहुल गांधी कह सकते थे कि लोकपाल भी बनेगा और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए दस और उपाय भी किए जाएंगे. किसानों के लिए यह किया जाएगा, मज़दूरों, ग़रीबों और अल्पसंख्यकों के लिए यह किया जाएगा. कुल मिलाकर देश में एक नए कार्यक्रम, एक नई बात कहने का आगाज़ राहुल गांधी कर सकते थे. राहुल गांधी ने यह नहीं किया. हो सकता है कि उनके मन में कुछ करने की ख्वाहिश रही हो, लेकिन उनके सलाहकारों का वैचारिक स्तर वैसा न हो, जो देश चलाने वालों का होना चाहिए. इसीलिए यह अवसर भांपने में राहुल गांधी और उनके सलाहकार चूक गए.

साधारण से साधारण आदमी, जो कांग्रेस से सहानुभूति रखता है, उसे लग रहा था कि इस अवसर का फ़ायदा राहुल गांधी अवश्य उठाएंगे और एक नई तस्वीर देश के सामने आएगी. वह नहीं आ पाई. हम यह नहीं कहते कि राहुल गांधी में समझ नहीं है, पर जब समझ की और जैसी समझ की जहां ज़रूरत होती है, वैसी समझ उस समय वहां दिखाई नहीं देती, तो देश का नेता बनने का सपना पालने वाले व्यक्ति के लिए यह ख़तरनाक स्थिति है. अगर सही मौक़े पर उसकी अक्ल काम न करे या सही मौक़े पर उसके सलाहकार उसे स्ट्राइक करने की सलाह न दें तो फिर यह मानना चाहिए कि देश को संभालने लायक़ अभी उसका व्यक्तित्व, उसकी समझ और बुद्धिमानी नहीं बनी है. वह अभी उतना परिपक्व नहीं है कि ऐसी स्थितियों का सामना कर सके. मनमोहन सिंह की सरकार उस समय अजीब-अजीब फ़ैसले कर रही थी. कौन वार्ता कर रहा है, वार्ता करने के बाद कौन फ़ैसले ले रहा है, हर क़दम पर मनमोहन सिंह की सरकार ने प्याज भी खाए और जूते भी खाए. यह कहावत कांग्रेस पार्टी और सरकार के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है. आपने अन्ना को गिरफ़्तार करके जेल भेज दिया, आपकी इंटेलिजेंस यह नहीं बता पाई कि अन्ना हजारे के पक्ष में किस तरह जनमानस बन गया है. फिर जेल में डालते ही चार-पांच घंटे के बाद आपने उन्हें छोड़ने का फ़ैसला कर लिया. जब अन्ना ने कहा कि वह जेल से नहीं निकलेंगे, तब आपको समझ में नहीं आया कि क्या करना है. जिस रामलीला मैदान को न देने के पीछे आपने सैकड़ों तर्क दिए, वही आपको मिन्नतें करके देना पड़ा और वहां झाड़ू लगवानी पड़ी, मिट्टी डलवानी पड़ी, पानी हटवाना पड़ा, टेंट लगवाना पड़ा, माइक लगवाने पड़े. यह सब करके आपने फिर अन्ना हजारे को मैदान दिया. इसके बाद आपने शर्त रखी कि तीन दिन, सात दिन, दस दिन. बाद में आपको फिर बात से पलटना पड़ा.

जब जन लोकपाल पर पहले बातचीत होती थी, तब कपिल सिब्बल एवं पी चिदंबरम का रुख़ और उसके बाद जो लोग बातचीत में शामिल हुए, उनका रुख़, दोनों अलग-अलग थे. लेकिन शायद कहीं कपिल सिब्बल और पी चिदंबरम पर्दे के पीछे खेल कर रहे थे. जब अन्ना हजारे की टीम के लोग आंख दिखाते थे और बाहर निकल कर कहते थे कि सरकार हमारे साथ धोखा कर रही है, तब दो घंटे के भीतर ही सरकार यू टर्न ले लेती थी. और तो और, शनिवार को यानी जिस दिन संसद में बहस हो रही थी, नारायण सामी एक बात कह रहे थे, पवन बंसल दूसरी बात कह रहे थे और सलमान खुर्शीद तीसरी बात कह रहे थे. सलमान ख़ुर्शीद ने अन्ना हजारे की टीम को टका सा जवाब दे दिया कि संसद में सिर्फ़ बात होगी, कोई प्रस्ताव पेश नहीं होगा. जब टीम अन्ना ने आंखें दिखाईं और कहा कि हमसे

> **साधारण से साधारण आदमी, जो कांग्रेस से सहानुभूति रखता है, उसे लग रहा था कि इस अवसर का फ़ायदा राहुल गांधी अवश्य उठाएंगे और एक नई तस्वीर देश के सामने आएगी. वह नहीं आ पाई. हम यह नहीं कहते कि राहुल गांधी में समझ नहीं है, पर जब समझ की और जैसी समझ की जहां ज़रूरत होती है, वैसी समझ उस समय वहां दिखाई नहीं देती, तो देश का नेता बनने का सपना पालने वाले व्यक्ति के लिए यह ख़तरनाक स्थिति है.**

धोखा कर रहे हैं, हमसे कहा था कि प्रस्ताव पास करेंगे और उसके पक्ष में मतदान होगा. एक घंटे के भीतर सलमान ख़ुर्शीद को पलटना पड़ा और उन्होंने कहा कि नहीं, प्रस्ताव पेश होगा और मतदान भी होगा. मतदान की स्थिति इसलिए नहीं आई कि सदन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर दिया. जब प्रधानमंत्री ने अन्ना हजारे को पत्र भेजा, जिसे लेकर विलासराव देशमुख गए, वह पत्र कहता है कि संसद ने प्रस्ताव पास किया है, जिसमें अन्ना हजारे की तीनों मांगों के ऊपर संसद में सर्वसम्मति है. अन्ना हजारे ने अनशन तोड़ दिया. इसके बाद कांग्रेस के लोगों ने सवाल उठा दिया कि प्रस्ताव है कहां, प्रस्ताव की भाषा क्या है, कौन सा प्रस्ताव है. यह कैसी भावना है? यहां पर कांग्रेस के भीतर एक मज़बूत नेतृत्व की ज़रूरत लोगों को महसूस हुई, लेकिन राहुल गांधी इस अवसर को चूक गए.

हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हो सकता है, राहुल गांधी के मन पर उनकी मां की बीमारी का प्रभाव रहा हो. राहुल और प्रियंका या कांग्रेस पार्टी ने, किसी ने भी देश को सोनिया गांधी की बीमारी के बारे में नहीं बताया. सोनिया गांधी देश की और कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री पद ठुकरा दिया था. उन्हें अगर कैंसर हुआ है, जिसके बारे में अफवाहें चारों तरफ़ चल रही हैं, तो भी देश को बताना चाहिए. बीमारी कोई ऐसी बात नहीं है, जिसे छुपाकर आप देश को धोखे में रखें. आख़िर आपके घर से ही बात निकलती है, आपकी पार्टी से बात निकलती है, आपकी पार्टी के महासचिव प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, लेकिन ऐसी प्रेस कांफ्रेंस करते हैं, जो अटकलें लगाने के लिए लोगों को मजबूर करती हैं. हो सकता है, उनकी बीमारी का दबाव राहुल गांधी के दिमाग़ पर रहा हो, लेकिन राहुल गांधी देश में थे. भले ही सप्ताह भर के लिए थे. उनकी मां अमेरिका में अस्पताल में थीं. अगर वह सात दिनों के लिए देश में थे तो उनके सलाहकारों ने उन्हें क्यों नहीं समझाया कि यह ऐसा मौक़ा है, जिसे नहीं चूकना चाहिए.

अन्ना हजारे के साथ 80 प्रतिशत नौजवान थे. वही नौजवान, जिन्हें राहुल गांधी अपनी कंस्टीट्यूएंसी मानते हैं, जिन्हें सत्ता में हिस्सेदारी या जिनके सपनों को पूरा करने की बात वह करते हैं, जिनके सहारे वह अगला चुनाव जीतने की योजना बना रहे हैं. वह नौजवान तो अन्ना हजारे के साथ खड़ा दिखाई दिया तो राहुल गांधी के साथ कौन सा नौजवान है? राहुल गांधी को एक बात समझनी चाहिए कि देश में नौजवानों के पास आप अपनी बात नहीं पहुंचाएंगे और उनसे उनकी बात नहीं सुनेंगे तो आप धोखा खाएंगे. फिर नौजवान कम से कम आपको अपना नेता नहीं मानेगा. कांग्रेस पार्टी एक संगठित पार्टी की तरह काम करती नहीं दिखाई दे रही है. जितने भी महासचिव हैं, वे सभी अपने नज़दीकी प्रेस वालों के पास उतनी ही कहानियां रोज़ निकाल रहे हैं. कुछ अख़बार छाप रहे हैं, कुछ नहीं छाप रहे हैं. कभी चैनल परस्पर विरोधी बातें दिखा देते हैं. 24 अकबर रोड पर पार्टी का दफ्तर है, जहां महासचिव और संयुक्त महासचिव बैठते हैं और वहीं से भिन्न-भिन्न कहानियां बाहर आती हैं. कांग्रेस को एक मज़बूत नेतृत्व की ज़रूरत है. ऐसे नेतृत्व की, जो सारे लोगों को बांध सके, सारे लोगों को चुनाव में उतार सके. ऐसे नेतृत्व से कांग्रेस का भला नहीं होने वाला, जो लोगों के मन में यह भ्रम पैदा करे कि जहाज डूबने वाला है. मेरे पास कांग्रेस से जुड़ी जो कहानियां आती हैं, उन कहानियों को तो नहीं कहूंगा, लेकिन उनका लब्बोलुबाब बताता हूं.

कांग्रेस के एक बड़े नेता ने मुझसे कहा कि अगर मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पार्टी चुनाव में उतरती है तो वह मौजूदा सीटों से 50 फ़ीसदी सीटें कम लाएगी. ज़िम्मेदार शख्स हैं, जिन्होंने ये बातें मुझसे कहीं. कांग्रेस पार्टी के एक दूसरे ज़िम्मेदार शख्स ने कहा कि हो सकता है, आने वाला एक महीना कांग्रेस में बदलाव का महीना हो. उनका इशारा सीधा था कि प्रधानमंत्री बदला जा सकता है. प्रधानमंत्री बदला जाए या न बदला जाए, पर पार्टी को चाहिए कि वह इस तरह की अफवाहों पर रोक लगाए. यह रोक लगाने का काम दो लोग ही कर सकते हैं. सोनिया गांधी, जो इस समय बीमार हैं और राहुल गांधी, जो उस कोर कमेटी के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं, जो सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में पार्टी को चलाने के लिए ज़िम्मेदार हैं. राहुल गांधी सोनिया गांधी के बेटे भी हैं. उन्हें चाहिए कि वह इन सारी बातों पर लगाम लगाएं. अगर वह लगाम नहीं लगाते हैं तो अपनी क्षमता को लेकर भ्रम पैदा कर रहे हैं. पार्टी संगठन को वह चला सकते हैं या नहीं, इस पर भी सवाल खड़ा होने लगा है. अब जबकि सोनिया गांधी बीमार हैं और शायद अगले कुछ महीनों तक वह शारीरिक और दिमाग़ी रूप से सक्षम नेतृत्व नहीं दे पाएंगी, राहुल गांधी के लिए यह ट्रांजिशनल फेज है. राहुल गांधी अगर इस वक़्त का फ़ायदा नहीं उठाते हैं और अपनी सांगठनिक और दिमाग़ी क्षमता का परिचय नहीं देते हैं तो यह बात नेहरू परिवार या फ़िरोज़ गांधी के परिवार या इंदिरा गांधी के परिवार के एक ऐसे शख्स के प्रति लोगों में मोहभंग की व्यापक स्थिति बनाएगी, जिसके बारे में अब तक यह तस्वीर गढ़ी जाती रही है कि यह शख्स, यह नौजवान बहुत समझदार है, सांगठनिक क्षमता वाला है, बेबाक है और यह देश का भावी प्रधानमंत्री है.

संपादक
editor@chauthiduniya.com

मेघनाद देसाई

चरमराती संसदीय व्यवस्था

पानी के एक साफ तालाब की कल्पना करें. कोई व्यक्ति उस तालाब में एक वायरस डाल देता है, जो उस तालाब के एक फ़ीसदी के बराबर है, लेकिन वह वायरस प्रतिदिन दोगुना हो जाता है. लोगों के पास इस तालाब को साफ करने के लिए सात दिनों का समय है और यदि वे इन सात दिनों के अंदर इस तालाब को साफ नहीं करते हैं तो आठवें दिन पूरा तालाब गंदा हो जाएगा. भारतीय राजनीति की स्थिति कुछ ऐसी ही होती दिखाई पड़ रही है. भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जिसमें सभी पार्टियां शामिल हैं, ने भ्रष्टाचार के वायरस को भारतीय लोकतंत्र की आत्मा समाप्त करने की अनुमति दे दी है. कोई भी सांसद लोकतंत्र को बचाने के लिए आगे आता नहीं दिखाई पड़ता. जो लोग इस संसदीय व्यवस्था की सहायता करना चाहते हैं, उनकी ओर ध्यान ही नहीं दिया जाता है.

पिछले अप्रैल से कांग्रेस पार्टी ने अन्ना के साथ संघर्ष करने की ज़िम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है. पहले उसने अन्ना की अवहेलना की, उनके अनशन को अलोकतांत्रिक कहा और फिर अगले तीन महीनों तक अन्ना हजारे और उनके जन लोकपाल बिल को अनदेखा किया गया. अगस्त में अन्ना हजारे ने कहा कि कांग्रेस ने उनके साथ चालाकी की है और इसी के साथ दूसरा आंदोलन प्रारंभ हुआ. 14 अगस्त को अन्ना हजारे की आलोचना की गई. 16 अगस्त को उन्हें गिरफ़्तार किया गया, जिसके बारे में कहा गया कि इसके पीछे दिल्ली पुलिस का हाथ है, कांग्रेस का नहीं, लेकिन शाम तक सारा मामला साफ हो गया और अन्ना हजारे को छोड़ दिया गया. अन्ना की गिरफ़्तारी और उनकी रिहाई दोनों ही बड़े राजनेताओं के इशारे पर हुई थी. जब अन्ना ने तिहाड़ जेल से बाहर आना अस्वीकार कर दिया तो कांग्रेस ने इस संघर्ष की सारी वैधता खो दी. इसने गांधी के नाम के इस्तेमाल का अपना अधिकार भी खो दिया. लोग कांग्रेस को गांधीवादी तरीक़े से विरोध करने वालों का शत्रु समझने लगे. उसके बाद आठ दिनों तक पर्दे के पीछे से समझौते होते रहे. इसके बाद अरुणा राय को सामने किया गया, जिन्होंने अपना लोकपाल बिल प्रस्तुत किया. उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब वह सरकार के साथ काम कर रही हों तो कर भी क्या सकती हैं.

कांग्रेस निस्सहाय दिखाई पड़ी. सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस की रणनीति लगातार बदलती रही. सोनिया गांधी की अनुपस्थिति में कांग्रेस के सभी काबिल वकील एवं सांसद बेकार साबित हुए और किसी ने अपनी राजनीतिक सहज बुद्धि का एक छटांक भी नहीं दिखाया. यह नहीं कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी को क्या हुआ है या वह कब तक सक्रिय राजनीति से दूर रहती हैं. उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में कांग्रेस की देखभाल के लिए चार लोगों का एक दल नियुक्त किया है, लेकिन हम लोग यह नहीं जानते कि सोनिया गांधी ने किसी को अपने बाद गठबंधन संभालने के लिए नियुक्त किया है. उन्होंने किसी को नियुक्त किया ही नहीं. ऐसी स्थिति में भला क्या आश्चर्य, जब कांग्रेस के अतिरिक्त गठबंधन में शामिल सभी अन्य दल इस लड़ाई से अलग हैं और कांग्रेस को ही अकेले लड़ने के लिए छोड़ दिया गया है.

देखा जाए तो पूरी राजनीतिक व्यवस्था ने इन वर्षों में संसदीय व्यवस्था का मखौल उड़ाया है. हर वर्ष कुछ दिनों के लिए संसद की बैठक होती है और जब बैठक होती है तो कुछ ही घंटों तक काम करती है. सरकार चाहे यूपीए की हो या एनडीए की, वह यही पसंद करती है कि संसद की बैठक इसी तरह चलती रहे, ताकि उन्हें बिल पारित करने में कोई परेशानी न हो. पिछले साल सरकार ने दस मिनट में सत्तरह बिल पारित किए. संसद और उसमें होने वाली कार्रवाई तो अब मायने ही खोती जा रही है. कोई भी जनप्रतिनिधि गंभीरता से संसद की कार्रवाइयों को लेता ही नहीं है. यह वास्तव में हमारी संसदीय व्यवस्था के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है. संसद की कार्रवाई के समय सांसदों के व्यवहार को देखा जा सकता है. संसद की गरिमा को ताक पर रख दिया जाता है. पिछले दिसंबर माह में प्रधानमंत्री ने कहा कि वह लोकलेखा समिति के समक्ष उपस्थित होंगे, लेकिन यह विपक्ष की संयुक्त संसदीय समिति की मांग को दबाने का एक तरीक़ा मात्र था. ऐसा इस कारण कहा जा सकता है, क्योंकि जब पीएसी की रिपोर्ट आई तो कांग्रेस ने भरसक प्रयास किया कि वह उसे कचरे के डिब्बे में डाल दे. कारण स्पष्ट था, इस रिपोर्ट में मुरली मनोहर जोशी ने प्रधानमंत्री की आलोचना की थी. इस प्रकार देखा जाए तो जबसे कांग्रेस पार्टी सत्ता में है, यह पवित्र संस्था अपवित्र होती दिख रही है. जिस तरह माग्रेट थैचर को कैबिनेट का सर्वेसर्वा कहा जाता था, वही स्थिति आज सोनिया गांधी की है, जिनकी अनुपस्थिति में कांग्रेस कोई भी अहम फ़ैसला नहीं ले पा रही है.

feedback@chauthiduniya.com

मणिपुर और शर्मिला को अन्ना का इंतज़ार

अन्ना हजारे के आंदोलन ने संसद को हिला दिया. सरकार अन्ना की आवाज़ अनसुना नहीं कर पाई, उसने अन्ना की मांग को गंभीरता से लिया और उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया. पूरे देश की जनता ने अन्ना का साथ दिया. दो सप्ताह तक पूरा देश अन्नामय रहा. दूसरी तरफ़ इरोम शर्मिला चनु हैं, जो पिछले 11 वर्षों से अहिंसात्मक तरीक़े से आमरण अनशन कर रही हैं, सेना के विशेषाधिकार क़ानून को मणिपुर से हटवाने के लिए. इस क़ानून की आड़ में सेना जो चाहे कर सकती है. थांगजम मनोरमा इस बात का जीता-जागता उदाहरण है. आतंकवादियों से कथित संबंधों के आरोप में सुरक्षाबल के जवान उसे घर से उठाकर ले गए और सामूहिक बलात्कार करने और मौत के घाट उतारने के बाद अगले दिन उसकी लाश घर के पास फेंक गए. मनोरमा को सात गोलियां मारी गईं. मनोरमा जैसे कई और उदाहरण हैं, जिन्हें लोग सुनना और जानना नहीं चाहते. इस घिनौनी हरकत के विरोध में पेबम चितरंजन नामक एक सामाजिक कार्यकर्ता ने आत्मदाह कर दिया. वर्ष 1958 में यह क़ानून इस उद्देश्य के साथ लागू किया गया था कि नगालैंड में सशस्त्र विद्रोह का सामना करने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को अधिक शक्तियां प्रदान की जा सकें. 1980 में यह क़ानून मणिपुर में भी लागू हो गया.

2 नवंबर, 2000 को असम रायफल्स के जवानों ने मणिपुर घाटी के मालोम क़स्बे में बस की प्रतीक्षा कर रहे दस निर्दोष नागरिकों को गोलियों से भून डाला. एक किशोर और एक बूढ़ी महिला को अपनी जान गंवानी पड़ी. हादसे की दर्दनाक तस्वीरें अगले दिन अख़बारों में छपीं. 28 वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ता, पत्रकार एवं कवयित्री इरोम शर्मिला ने भी ये तस्वीरें देखीं. असम रायफल्स ने अपने बचाव में तर्क दिया कि आत्मरक्षा के प्रयास में क्रॉस फायर के दौरान ये नागरिक मारे गए, लेकिन आक्रोशित नागरिक स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग कर रहे थे. इसकी अनुमति नहीं दी गई, क्योंकि असम रायफल्स को अफसपा के तहत ओपन फायर के अधिकार हासिल थे. तभी से शर्मिला ने शपथ ली कि वह लोगों को इस क़ानून से मुक्त कराने के लिए संघर्ष करेंगी. उनके सामने अनशन के अलावा और कोई चारा नहीं था. उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और 4 नवंबर, 2000 को अनशन शुरू कर दिया. एक दशक बीतने के बावजूद क़ानून यथावत लागू है और शर्मिला का अभियान भी जारी है.

> **मणिपुर वूमेन गन सरवाइवर्स नेटवर्क की संस्थापक महासचिव बीना लक्ष्मी नेप्रम कहती हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन को देखकर मणिपुर के हज़ारों युवाओं के दिल में यह सवाल उठ रहा है कि आख़िर शर्मिला के अहिंसात्मक आंदोलन को नज़रअंदाज़ क्यों किया जा रहा है. मणिपुर में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है. एक ओर देश की संसद लोगों को जीने का अधिकार देती है, मगर अफसपा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट) लोगों का वह अधिकार छीन लेता है.**

मणिपुर वूमेन गन सरवाइवर्स नेटवर्क की संस्थापक महासचिव बीना लक्ष्मी नेप्रम कहती हैं कि अन्ना हजारे के आंदोलन को देखकर मणिपुर के हज़ारों युवाओं के दिल में यह सवाल उठ रहा है कि आख़िर शर्मिला के अहिंसात्मक आंदोलन को नज़रअंदाज़ क्यों किया जा रहा है. मणिपुर में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है. एक ओर देश की संसद लोगों को जीने का अधिकार देती है, मगर अफसपा (आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट) लोगों का वह अधिकार छीन लेता है. अगर केंद्र सरकार वाकई पूर्वोत्तर के लोगों की चिंता करती है तो उसे यह क़ानून हटा लेना चाहिए. मणिपुर में प्रतिदिन तीन-चार आदमी सेना की गोली का शिकार बनते हैं. लोग कहते हैं कि हमें अन्ना पर गर्व है. इस देश को उनकी ज़रूरत है. अन्ना इंफाल आएं और शर्मिला के आंदोलन का समर्थन करें.

शर्मिला का आंदोलन 11 साल से जारी है, मगर आज तक राज्य और केंद्र सरकार ने कोई पहल नहीं की. शर्मिला की मांग पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है. 2005 में जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी भी इस क़ानून को दोषपूर्ण बता चुकी है. फिर भी सरकार ने चुप्पी साध रखी है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या अनशन केवल उत्तर भारतीयों के लिए विरोध का हथियार है. अगर दो सप्ताह के अंदर ही सरकार और संसद अन्ना की मांग पर चर्चा करना ज़रूरी समझ लेती है तो उसे 11 सालों से अनशन कर रही शर्मिला की मांग ज़रूरी क्यों नहीं लगती? शर्मिला को बीते 30 अगस्त को एक मामले की सुनवाई के लिए अदालत आई थीं, तब उन्होंने कहा कि एक दिन मानवाधिकार हनन के ख़िलाफ़ मेरे संघर्ष और मांग को सरकार मान्यता देगी. उन्होंने कहा कि अन्ना मणिपुर आएं और यहां की स्थिति अपनी आंखों से देखें. शर्मिला के भाई सिंहजीत सिंह का कहना है कि सरकार शर्मिला की मांग को नहीं सुन रही है. शर्मिला आम लोगों की लड़ाई लड़ रही है. उसका अनशन अंतिम समय तक चलता रहेगा. मणिपुर के सांसद थोकचोम मैन्य सिंह कहते हैं कि 2005 में जस्टिस जीवन रेड्डी कमेटी ने कहा था कि अफसपा को हटाना ज़रूरी है. कई मंत्रियों ने भी इसका समर्थन किया. मैं हमेशा इस एक्ट को हटवाने के लिए अपील करता रहता हूं, मगर संसद में अकेला पड़ जाता हूं.

उत्तर-पूर्व को देश की मुख्यधारा में लाने के लिए सरकार को वहां की जनता की भावनाओं को समझना होगा. एक अनुरोध अन्ना से भी है कि वह अब आप सिर्फ़ महाराष्ट्र या उत्तर भारत के नहीं हैं, पूरा देश उनका है. वह शर्मिला का समर्थन करके यह दिखा दें कि आज भी भारत एक है, हम सब एक हैं. मणिपुर और शर्मिला को आपका इंतज़ार है अन्ना.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

पाठकों की दुनिया

सर्वश्रेष्ठ पत्र

दोषियों को फांसी हो

देश में फ़र्ज़ी एनकाउंटर के अनेक मामले सामने आए हैं. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर चिंता ज़ाहिर करते हुए सख्त टिप्पणियां की हैं, लेकिन पुलिस ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया और एक के बाद एक फ़र्ज़ी मुठभेड़ को अंजाम दिया जाता रहा. पुलिस द्वारा फ़र्ज़ी एनकाउंटर के मामलों को रोकने के लिए सख्ती बरतने की ज़रूरत है. ऐसे मामलों के अभियुक्तों को फांसी की सज़ा देनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने भी इसकी पैरवी की है. उनका कहना है कि यह सरासर संविधान की अवहेलना है. किसी भी व्यक्ति को दूसरे की जान लेने का अधिकार नहीं है. पुलिसवालों का काम लोगों की जान बचाना है, लेकिन वे अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष लोगों की जानें लेने से जरा भी नहीं झिझकते. फ़र्ज़ी एनकाउंटर के दोषी पुलिसकर्मियों एवं और अधिकारियों को फांसी पर लटका देना चाहिए, ताकि दूसरे इससे सबक़ हासिल कर सकें.

-सीत मिश्रा, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश.

युवा सबक़ लें

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने घाटी में पिछले साल गर्मियों में पथराव के तक़रीबन 12 सौ मामलों में शामिल युवाओं के लिए आम माफ़ी देने का ऐलान करते हुए कहा कि सरकार ने उन्हें एक मौक़ा देने का फ़ैसला किया है और युवा इसे सरकार की ओर से ईदी समझें. यह माफ़ी आगज़नी में शामिल युवाओं पर लागू नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं का आपराधिक रिकॉर्ड मिटाकर उन्हें बेहतर भविष्य बनाने का मौक़ा दिया जाएगा. बेशक, यह एक बेहतर पहल है, लेकिन युवाओं को भी समझना होगा कि वे इस मौक़े से फ़ायदा लेने के साथ ही सबक लें और प्रण करें कि भविष्य में कभी भी इस तरह की घटनाओं में शामिल नहीं होंगे.

-सरफ़राज़ ख़ान, *दिल्ली.*

सभी को इंसाफ़ मिले

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-ग्रेटर नोएडा: सपने संजोने और बिखरने की दास्तां पढ़ा. लेखिका का कहना सही है कि सरकार की लापरवाही का ख़ामियाज़ा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. यह सरकार की नाकामी रही कि आज तक अंग्रेजों के ज़माने का भूमि अधिग्रहण कानून लागू रहा. देश को आज़ाद हुए क़रीब साढ़े छह दशक हो चुके हैं, इसके बावजूद इस क़ानून में संशोधन न करना एक बड़ी भूल है. सरकार की कोताही के कारण किसानों से उनकी पुश्तैनी ज़मीन छिन गई, उन्हें इसकी वाजिब क़ीमत भी नहीं दी गई. इस मुद्दे को लेकर ख़ूनी संघर्ष हुए और कई जानें भी चली गईं. सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसा रास्ता निकाले, जिससे किसानों के साथ-साथ उन लोगों को भी राहत मिल सके, जिन्होंने वहां अपने फ्लैट बुक कराए हैं.

-सईद, *नोएडा, उत्तर प्रदेश.*

खादी को बढ़ावा मिले

चौथी दुनिया में प्रकाशित आलेख-खादी की दुर्दशा पढ़ा. लेखक ने समग्र रूप से खादी से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई है. सच में खादी एक वस्त्र नहीं, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का एक सपना था. उन्होंने खादी को बढ़ावा देने के लिए सूत तक काता. अफ़सोस की बात यह है कि सरकार ने खादी के प्रति लापरवाही बरती, जिसके कारण खादी केंद्रों की हालत बद से बदतर होती चली गई. सरकार को चाहिए कि वह खादी को बढ़ावा देने के लिए ईमानदारी से प्रयास करे. इससे जहां लोगों को रोज़गार उपलब्ध हो सकेगा, वहीं महात्मा गांधी का सपना भी परवान चढ़ सकेगा.

-नरेश कुमार सिंह, *खगड़िया, बिहार.*

गद्दाफ़ी की क्रूरता

गद्दाफी की सेना ने त्रिपोली से कुछ दूर 150 लोगों की बर्बर तरीक़े से हत्या कर दी. इनमें से कई लोगों को पहले तो गोलियों से छलनी किया गया, फिर एक वेयर हाउस में बंद कर बाहर से आग लगा दी गई. मारे गए लोगों में दो सैनिक भी हैं, जिनके हाथ पीछे की ओर बंधे थे. लाशों की हालत अत्यधिक जलने से बेहद ख़राब गई. अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों को इस मामले में कारगर क़दम उठाने चाहिए.

-फ़ौज़िया, *दरियागंज, दिल्ली.*

जादू-टोने पर रोक लगे

महाराष्ट्र सरकार नरबलि और अन्य अमानवीय, अनिष्ट, अघोरी प्रथा तथा जादू-टोने पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास में है. इसके लिए विधानमंडल के मानसून सत्र में एक विधेयक भी लाया गया. सरकार के इस प्रयास की सराहना की जानी चाहिए. आज के आधुनिक युग में भी कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लोगों को गुमराह कर जादू-टोने की दुकान चला रहे हैं. इतना ही नहीं, इसकी आड़ में अमानवीय कृत्य भी किए जाते रहे हैं, वह चाहे नरबलि हो या किसी को जलती सलाख़ों से दागने का मामला. नया क़ानून बन जाने से जादू-टोने पर कुछ हद तक रोक लग सकती है.

-हिमांशु, *नांदेड़, महाराष्ट्र.*

भ्रष्टाचार से लड़ना होगा

उठो जवानो तुम्हें जगाने क्रांति द्वार पर आई है, आलेख पढ़ा. भ्रष्टाचार का मुक़ाबला करने के लिए उसे बेनक़ाब करने वालों को संरक्षण दिया जाना चाहिए. यह बहुत जरूरी है.

-राजीव कुमार, *ईमेल से.*

राजकमल प्रकाशन समूह
चौथी दुनिया में प्रकाशित सप्ताह के सर्वश्रेष्ठ पत्र को राजकमल प्रकाशन की ओर से 700 रुपए की किताबें दी जाएंगी.
राजकमल प्रकाशन की किसी भी पुस्तक की समीक्षा चौथी दुनिया को भेजें. हर महीने की सर्वश्रेष्ठ समीक्षा को 1100 रुपए की पुस्तकें दी जाएंगी.

पाठक पूरा नाम, पता व फोन नंबर के साथ अपने विचार व प्रतिक्रियाएं इस पते पर भेजें :
चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा-201301
ई मेल : feedback@chauthiduniya.com

शौहर-बीवी के बीच का यह मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंच चुका है. परामर्शदाता इस प्रयास में हैं कि मामला सुलझ जाए और शौहर-बीवी फिर से साथ रहने लगें.

सूचना का अधिकार
जानने का अधिकार जीने का अधिकार
चौथी दुनिया की पहल

सूचना आयुक्त

आरटीआई के रक्षक या कुछ और...

सूचना क़ानून को लागू हुए 6 साल हो गए और इस बीच इसने कई उतार-चढ़ाव देखे. संशोधन की मार से बचते हुए भी इस क़ानून पर पीआईओ (लोक सूचना अधिकारियों) और सूचना आयुक्तों की टेढ़ी नज़र से गुजरना पड़ा. सूचना आयुक्तों पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं कि वे अधिकारियों का पक्ष लेते हैं और आवेदकों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं. इस अंक में हम कुछ ऐसे उदाहरण दे रहे हैं, जहां सूचना आयुक्तों का व्यवहार उनके पद की गरिमा और इस क़ानून की आत्मा के एकदम ख़िलाफ़ रहा है.

अगर आवेदक सूचना मांगने के लिए अपना पक्ष स्पष्ट करे तो हरियाणा की सूचना आयुक्त मीनाक्षी आनंद चौधरी उसे कमरे से बाहर भगा देती है. बहादुरगढ़ के नरेश जैन के एक मामले की सुनवाई करते हुए वह सूचना न देने वाले अधिकारी का पक्ष लेने और नरेश को डांटने लगीं कि इतनी सूचनाएं लेकर क्या करोगे? नरेश ने इसके जवाब में कहा कि इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए. आप सूचना देने के लिए बैठाई गई हैं, न कि लोक सूचना अधिकारियों के लिए. यह सुनकर उन्होंने नरेश को सुनवाई से बाहर निकाल दिया. नरेश ने बहादुरगढ़ के सिविल अस्पताल से संबंधित सूचनाएं मांगी थीं. मीनाक्षी आनंद ने हिसार के राजेंद्र यादव को भी यह कहकर झिड़क दिया कि मुझे जो करना था कर दिया, तुम्हें जो करना है कर लो. राजेंद्र ने मीनाक्षी आनंद के फ़ैसले के प्रति नाराज़गी व्यक्त की थी, जिसकी प्रतिक्रिया में मीनाक्षी ने यह बात कही.

उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त बृजेश कुमार सिंह ने सामाजिक कार्यकर्ता उर्वशी शर्मा को भरी अदालत में धमकी दी और कहा कि यदि वह अपना मामला आयोग में फ़िर लेकर आईं तो उन्हें गिरफ़्तार करा दिया जाएगा. उसके बाद काफी समय तक आयोग में उर्वशी के मामलों की सुनवाई नहीं हुई. उर्वशी ने प्रदेश के समाज कल्याण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को सूचना के अधिकार के ज़रिए उठाया था, जिसमें अनेक अधिकारी फंस रहे थे. उत्तर प्रदेश के राजा भैया यादव जब तत्कालीन सूचना आयुक्त सुनील चौधरी के यहां गए तो उन्होंने कहा, तो आप हैं राजा भैया! आपने क्या आरटीआई का ठेका ले रखा है? राजा भैया ने अपने आवेदनों में नरैनी के तालाबों पर अतिक्रमण के बारे में जानकारी मांगी थी. अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर तारिक इस्लाम जब अपनी अपीलों की सुनवाई के लिए तत्कालीन केंद्रीय सूचना आयुक्त ओ पी केजरीवाल के यहां गए तो उन्होंने खीझते हुए कहा, हम इतनी छोटी-छोटी बातों की कब तक सुनवाई करते रहेंगे. यदि ऐसा चलता रहा तो मैं ऐसे मामलों के ख़िलाफ़ वार्निंग इश्यू कर दूंगा. तारिक ने अलीगढ़ के

मराठा किले के संबंध में सूचना मांगी थी. किले के संरक्षण और देखभाल की ज़िम्मेदारी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने एएमयू को सौंपी थी. किले जैसी धरोहरों में किसी भी प्रकार का निर्माण मना है, लेकिन किले के भीतर स्कूल बनवा दिया गया. यह स्कूल किसकी अनुमति से बना, यही जानने के लिए उन्होंने आरटीआई दायर की थी. तारिक इस किले के अलावा विश्वविद्यालय से जुड़े तीन अन्य मामलों की सुनवाई के लिए आयोग गए थे.

यह मेरा बाज़ार है और यहां जो मैं चाहूंगा, वही होगा. यह बात तत्कालीन मुख्य केंद्रीय सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्ला ने दिल्ली की स्वाति और उसके सहयोगियों से कही थी. हबीबुल्ला काफी समय से उन्हें आश्वासन दे रहे थे कि वह स्वास्थ्य विभाग के मामले सूचना आयुक्त पदमा बालासुब्रमण्यम से लेकर स्वयं देखेंगे या ओ पी केजरीवाल को ट्रांसफर कर देंगे. इस संबंध में जब स्वाति और क़रीब 30 गरीब लोग वजाहत साहब के पास पहुंचे और उनसे सुनवाई के लिए कमिश्नर बदलने का आग्रह करने लगे तो उन्होंने ये बातें कहीं. वजाहत हबीबुल्ला के कहने के बावजूद सूचना आयुक्त एम एम अंसारी दिल्ली के एम के त्यागी की अपील की सुनवाई की तारीख़ नहीं दे रहे थे. आवेदक ने जब सुनवाई के लिए अंसारी से कहा तो वह बोले, मेरे पास समय नहीं है, आप अपने काग़ज़ात छोड़ जाइए, मैं देख लूंगा.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

यदि आपने सूचना क़ानून का इस्तेमाल किया है और अगर कोई सूचना आपके पास है, जिसे आप हमारे साथ बांटना चाहते हैं तो हमें वह सूचना निम्न पते पर भेजें. हम उसे प्रकाशित करेंगे. इसके अलावा सूचना का अधिकार क़ानून से संबंधित किसी भी सुझाव या परामर्श के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमें पत्र लिख सकते हैं. हमारा पता है :

चौथी दुनिया
एफ-2, सेक्टर-11, नोएडा (गौतमबुद्ध नगर) उत्तर प्रदेश, पिन -201301
ई-मेल : rti@chauthiduniya.com

ज़रा हट के

मंजन और बीवी

अभी तक आपने एक्सट्रा मेराइटल अफेयर को लेकर पति-पत्नी में तलाक या अलगाव होते सुना होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग ही वजह है. साफ-सफाई कितनी ज़रूरी है, यह आप इस ख़बर से अंदाज़ा लगा सकते हैं. एक बीवी ने अपने पति से कह दिया है कि जब तक वह अपने दांतों और शरीर को साफ-सुथरा नहीं करेगा, वह ससुराल नहीं जाएगी. मोहतरमा पिछले एक साल से इसी शर्त पर अड़ी हुई हैं. यह दिलचस्प मामला उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले का है, जहां एक बीवी ने अपने शौहर के सामने शर्त रखी है कि वह रोज दांतों में मंजन करेगा और शरीर साफ-सुथरा रखेगा, तभी उसके साथ रहेगी.

शौहर-बीवी के बीच का यह मामला परिवार परामर्श केंद्र में पहुंच चुका है. परामर्शदाता इस प्रयास में हैं कि मामला सुलझ जाए और शौहर-बीवी फिर से साथ रहने लगें. शौहर का नाम अब्दुल रहमान है. वह कपड़े का कारोबार करते हैं और खुर्जा के रहने वाले हैं. छह साल पहले उनका निकाह जुबैदा से हुआ था. जुबैदा के मुताबिक़, उनके शौहर शरीर की साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखते. वह दांतों में रोज सुबह मंजन भी नहीं करते. उनके मुंह से इतनी बदबू आती है कि आप नज़दीक नहीं जा सकते. अनेक बार कहने के बावजूद उन्होंने साफ-सफाई पर ध्यान नहीं दिया, उलटे उसे ही मारना-पीटना शुरू कर दिया तो वह साल भर पहले अपनी बहन के घर चली गई. उसके बाद यह मामला परिवार परामर्श केंद्र पहुंचा. परामर्शदाताओं के समझाने पर जुबैदा ने शौहर के साथ रहना तो स्वीकार किया, लेकिन इस शर्त पर कि वह रोज मंजन करेगा. अगर अब्दुल रोज़ाना मंजन करने की बात मान लेते हैं तो जुबैदा घर लौट आएंगी.

पीलिया और मकोय की पत्ती

अगर आप अंग्रेजी और अन्य तरह की दवाइयों के इलाज के बावजूद पीलिया से छुटकारा न पा सके हों तो आपके लिए यह एक अच्छी ख़बर है. पीलिया का आयुर्वेद में अचूक इलाज है. मौसम बदलने के साथ ही पीलिया का प्रकोप बढ़ रहा है. आयुर्वेद चिकित्सकों के अनुसार, यदि मकोय की पत्तियों को उबाल कर उसका सेवन किया जाए तो पीलिया से जल्द राहत मिलती है. मकोय एक अचूक दवा है, इसका सेवन किसी भी रूप में किया जाए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है. चिकित्सक कहते हैं कि जब भी किसी को यह लगे कि उसका शरीर पीला हो रहा है और उसे पीलिया हो सकता है तो वह पानी की मात्रा बढ़ा दे, क्योंकि पानी की मात्रा कम होने पर शरीर से उत्सर्जित होने वाले तत्व रक्त में मिल जाते हैं. इससे व्यक्ति की हालत बिगड़ने लगती है. यदि कच्चा पपीता सलाद के रूप में लिया जाए तो भी पीलिया का असर कम होता है.

इसके अलावा परवल, लौकी और मूंग की दाल भी पीलिया के रोगी के लिए काफी लाभप्रद होती है. पीलिया से बचने लिए प्रोटीनयुक्त भोजन करें और वसायुक्त खाद्य पदार्थों से बचें, क्योंकि यह पीलिया के स्तर को बढ़ाते हैं. कई लोग मानते हैं कि पीलिया के रोगी को मीठा नहीं खाना चाहिए, जबकि आयुर्वेद चिकित्सकों का कहना है कि पीलिया का रोगी गाय के दूध से बना पनीर और छेने का रसगुल्ला आराम से खा सकता है. ये रोगी को नुक़सान नहीं, लाभ पहुंचाते हैं. जिन्हें क़ब्ज़ की शिकायत रहती हो, वे प्रतिदिन सोते समय अमलतास के गूदे का एक-दो चम्मच सेवन करें, क़ब्ज़ से राहत मिलती है. मौसमी फलों का सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इससे बीमारियों की रोकथाम होती है.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

राशिफल

मेष (21 मार्च से 20 अप्रैल)
आय के नवीन स्रोत बनेंगे. पारिवारिक जीवन सुखमय होगा. जीवनसाथी, पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा. राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी. धन हानि की आशंका है. आर्थिक क्षेत्र में सफलता के योग हैं.

वृष (21 अप्रैल से 20 मई)
यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभपूर्ण होगी. कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. नेत्र विकार की आशंका है. रुपये-पैसे के लेनदेन में सावधानी अपेक्षित है. स्वास्थ्य के प्रति और वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है. वाणी पर संयम बनाए रखें.

मिथुन (21 मई से 20 जून)
इस सप्ताह किसी के लड़ाई-झगड़े में न उलझें नहीं तो आप ख़ुद विवाद में फंस सकते हैं. व्यवसायिक योजना सफल होगी. किया गया परिश्रम सार्थक होगा. वाद-विवाद की स्थिति आपके हित में नहीं होगी. धन, पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. शासन-सत्ता का सहयोग मिलेगा.

कर्क (21 जून से 20 जुलाई)
वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, वरना दुर्घटना हो सकती है. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. खानपान में संयम रखें. कोई महत्वपूर्ण निर्णय न लें. कोई बहुमूल्य वस्तु पाने की अभिलाषा पूरी होगी. जारी प्रयास सार्थक होंगे.

सिंह (21 जुलाई से 20 अगस्त)
समाज के कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. भाग्यवश कुछ ऐसा होगा, जिसका आपको लाभ मिलेगा. शासन-सत्ता और जीवनसाथी का सहयोग एवं सानिध्य मिलेगा. रुपये-पैसे के लेनदेन में सावधानी अपेक्षित है. रुका हुआ कार्य संपन्न होगा.

कन्या (21 अगस्त से 20 सितंबर)
व्यय पर नियंत्रण बनाए रखें. अचानक कहीं यात्रा पर जाना पड़ सकता है. अपनों का सहयोग मिलेगा. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. स्थानांतरण एवं परिवर्तन की दिशा में किया गया प्रयास सार्थक होगा. स्वास्थ्य पर ध्यान दें और समय पर डॉक्टर से सलाह अवश्य लें.

तुला (21 सितंबर से 20 अक्टूबर)
पेट से संबंधी शिकायत हो सकती है. व्यवसाय में परिवर्तन के योग हैं. जारी प्रयास सार्थक होंगे. व्यवसायिक दिशा में किया गया प्रयास सफल होगा. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद होगी.

वृश्चिक (21 अक्टूबर से 20 नवंबर)
कहीं दूर यात्रा पर जाने का कार्यक्रम बनाएंगे. धन, पद एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा. वाणी की सौम्यता आपको धन लाभ कराएगी. व्यवसायिक क्षेत्र में व्यवधान आ सकते हैं. वाहन प्रयोग में सावधानी अपेक्षित है.

धनु (21 नवंबर से 20 दिसंबर)
घर में लड़ाई-झगड़े की आशंका है, अपने गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखें. सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा. शिक्षा-प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी. यात्रा-देशाटन की स्थिति सुखद एवं लाभप्रद होगी.

मकर (21 दिसंबर से 20 जनवरी)
यात्रा करते समय अपने सामान का ध्यान अवश्य रखें, वरना खोने की आशंका बनी हुई है. किया गया परिश्रम सार्थक होगा. खानपान में संयम बनाकर रखें. स्वास्थ्य शिथिल रहेगा. परिवारीजनों का सहयोग मिलेगा. आय के नए स्रोत प्राप्त होंगे.

कुंभ (21 जनवरी से 20 फरवरी)
दांपत्य जीवन सुखमय होगा. वाणी में मधुरता बनाए रखें. शिक्षा के क्षेत्र में किसी प्रतियोगिता-परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना है. संतान के पक्ष में कोई सुखद समाचार मिल सकता है.

मीन (21 फरवरी से 20 मार्च)
जीवनसाथी के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें. शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी. रुका हुआ कार्य संपन्न होगा. समाज के कार्यों में अधिक व्यस्त रहेंगे. मनोरंजन के अवसर प्राप्त होंगे.

पंडित सुदर्शन
feedback@chauthiduniya.com

भारतीय मूल के आईएसआई एजेंट फाई की गिरफ्तारी भारत के लिए गंभीर मुद्दा है. फाई वाशिंगटन में कश्मीर अमेरिकन काउंसिल (केएसी) नामक संगठन चला रहा था.

कश्मीर पर वार्ताकारों की ज़रूरत क्या है

ब्रिगेडियर हेमंत महाजन (सेवानिवृत्त)

कश्मीर वार्ताकारों ने अपनी गतिविधियों के कारण विश्वसनीयता खो दी है. अब उन्हें और मौक़ा दिया जाना व्यर्थ है. शुरू से ही हम इनकी मुहिम को लेकर आशंकित थे. यह बात समझ से परे है कि संप्रग सरकार इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंची कि कश्मीर समस्या का हल वार्ताकारों की टीम नियुक्त करने से हो जाएगा. वार्ताकार ऐसा क्या कर सकते हैं, जो राजनीतिक प्रक्रिया के तहत नहीं किया जा सकता. ऐसी कोई भी टीम नियुक्त करने से पहले केंद्र सरकार को आवश्यक अध्ययन कर लेना चाहिए था. जिस तरीक़े से वार्ताकारों की नियुक्ति की गई, वह सरकार की अनिश्चित कार्यशैली को दर्शाता है. पहला सवाल यह है कि क्या वार्ताकारों में घाटी के विभिन्न वर्गों से चर्चा करने की वाकई योग्यता है? वे न तो बड़ी राजनीतिक हस्तियां हैं. न ही वे कश्मीर की समस्याओं के विशेषज्ञ माने जाते हैं. अधिकांश भारतीयों ने कभी इन वार्ताकारों का नाम भी नहीं सुना. टीम के तीन सदस्यों में ऐसा क्या खास है कि उनके विचारों को राज्य या देश की जनता स्वीकार करे. यदि केंद्र सरकार कश्मीर मुद्दे पर बातचीत का कोई वास्तविक और प्रभावी एजेंडा ढूंढना चाहती है तो उसे इन सब बातों को ध्यान रखना चाहिए था. कश्मीर समस्या के निराकरण के लिए राष्ट्रीय सहमति होना आवश्यक है. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. कश्मीर में अलगाववादियों से समझौते को लेकर किसी भी अध्ययन दल का गठन या पाक समर्थित तत्वों, अन्य राजनीतिक नेताओं से चर्चा के लिए कोई भी नियुक्ति निर्विवाद होनी चाहिए. उसे सभी तरह के अधिकार दिए जाने चाहिए. केवल चर्चा करने से काम नहीं चलेगा, अन्यथा देशवासी उसे गंभीरता से नहीं लेंगे.

नित नए ख़ुलासे

यह बात पूरी तरह उजागर हो गई है कि वार्ताकारों की टीम के मुखिया दिलीप पड़गावकर ने आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाई का साथ दिया. पड़गावकर ने अमेरिका में फाई द्वारा आयोजित सेमिनार में हिस्सा लिया, क्या वार्ताकारों की टीम का अस्तित्व ख़त्म करने के लिए यह प्रमाण काफी नहीं है? हर दिन नए ख़ुलासे हो रहे हैं, जिनमें टीम के सदस्यों में मतभेद भी शामिल हैं. फाई के साथ संबंधों के ख़ुलासे के बाद टीम के एक सदस्य ने पड़गावकर को हटाने की मांग की है. जबकि एक अन्य सदस्य राधा कुमार के भी आईएसआई के सेमिनार में हिस्सा लेने का ख़ुलासा हुआ है. उनका कहना है कि वह किसी सभा–सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगी. इस संपूर्ण घटनाक्रम के बीच गृह मंत्रालय आश्चर्यजनक रूप से ख़ामोश है. क्या यह समझ लेना चाहिए कि केंद्र सरकार वार्ताकारों की भूमिका को लेकर गंभीर नहीं है, क्या सरकार यह मान रही है कि वार्ताकारों को लेकर हुए ख़ुलासों के बाद उनके प्रयासों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा? कश्मीर वार्ताकारों की नियुक्ति को लेकर गृह मंत्रालय पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं. टीम के बेमेल होने के चलते इसके प्रयासों के विषय में कुछ कह पाना मुश्किल है. लोगों का कहना है कि इन तथाकथित स्वतंत्र विचारकों की कोशिशों का आख़िर क्या लाभ हो सकता है, जब यह बात साबित हो गई कि वे आईएसआई एजेंट के क़रीबी हैं.

11 महीने पहले टीम के ऐलान के समय ही वार्ताकार विवादों से घिर गए थे, जब पड़गावकर ने विवादास्पद बयान दिया था, जो काफी हद तक हुर्रियत का पक्ष रखने वाला साबित हुआ. 24 अक्टूबर, 2010 को जब पहली बार यह टीम घाटी पहुंची, पड़गावकर ने कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए इस्लामाबाद को शामिल करने संबंधी बयान देकर सनसनी फैलाई. वार्ताकारों ने जानबूझ कर मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिश की. अमेरिका में फाई की गिरफ़्तारी के बाद संदेह गहरा गया है कि सरकार द्वारा गठित इस समिति के इरादे ठीक नहीं थे. क्या यह टीम कश्मीर घाटी में माहौल को और तनावपूर्ण बनाने और मतभेद बढ़ाने का काम कर रही थी? घाटी के लोगों का आईएसआई की भारत में ताक़त बढ़ाने के अलावा दूसरा कोई एजेंडा नहीं है. सारी बातें जानते हुए गृह मंत्रालय इन बुद्धिजीवियों का पक्ष लेता रहा. राधा कुमार के विदेश दौरों से संबंधित जानकारी एक आरटीआई आवेदन द्वारा मांगी गई है. वह यह बताने से इंकार करती रही हैं. रिपोर्ट में कहा गया है कि राधा कुमार, जो केंद्र सरकार से प्रतिमाह लगभग डेढ़ लाख रुपये और अन्य सुविधाएं प्राप्त करती रही हैं, आरटीआई के दायरे के बाहर नहीं हैं. वह आईएसआई से संबंधित संस्थाओं द्वारा आयोजित सेमिनार में शामिल होने संबंधी जानकारी का खुलासा करने से इंकार नहीं कर सकती हैं. टीम के सदस्य एम एम अंसारी ने पड़गावकर और कुमार द्वारा आईएसआई की दावतों में शामिल होने के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है. कश्मीरी पैनल की दोहरी नीति का ख़ुलासा करने वाली बातें यहीं खत्म नहीं हो जातीं. इन सदस्यों द्वारा इस मुद्दे को ईमानदारी, निष्पक्षता और स्वतंत्रता से हल करने पर भी सवालिया निशान लगा हुआ है. पैनल के पास न जनमत है और न विश्वास. केंद्र सरकार के लिए यही बेहतर होगा कि वह इस टीम का बोरिया–बिस्तर समेट दे और आईएसआई एवं पाक समर्थकों के साथ मिलकर अंजाम दी गई इनकी गतिविधियों की भी जांच कराए.

मीडिया और आईएसआई

भारतीय मूल के आईएसआई एजेंट फाई की गिरफ्तारी भारत के लिए गंभीर मुद्दा है. फाई वाशिंगटन में कश्मीर अमेरिकन काउंसिल (केएसी) नामक संगठन चला रहा था. आईएसआई उसे गुपचुप तरीक़े से पैसे उपलब्ध करा रही थी. यह संगठन नियमित रूप से कश्मीर समस्या पर कांफ्रेंस और सेमिनार आयोजित करता रहा है, जिनमें नामचीन राजनेता एवं पत्रकार शामिल होते हैं. इनमें आने वाले मेहमानों की सभी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाता है, अच्छी–खासी रकम का भुगतान किया जाता है. उच्च प्रतिष्ठित भारतीय एक तरह से फाई और केएसी की मदद कर रहे थे. एफबीआई ने इसे उजागर कर दिया है. क्या इस बात पर यक़ीन किया जा सकता है कि इन प्रतिष्ठित राजनेताओं और बुद्धिजीवियों को फाई की पृष्ठभूमि के बारे में पता नहीं था?

क्या बयां करते हैं तथ्य

केपीएस गिल के नेतृत्व वाले विवाद प्रबंधन संस्थान ने जून 2001 में जो रिपोर्ट सौंपी थी, उसमें साफ उल्लेख है कि एचएम (हिजबुल मुजाहिदीन) का जमात–ए–इस्लामी से घनिष्ठ संबंध है. जमात–ए–इस्लामी को गुलाम नबी फाई के कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल का पूरा समर्थन है. आतंकवाद के विशेषज्ञ प्रवीण स्वामी ने भी फरवरी 2003 में लिखा था कि हिजबुल अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में अयूब ठाकुर एवं फाई जैसे कार्यकर्ताओं से नियमित तौर पर फंड हासिल करता है.

डबल एजेंट की शर्मनाक भूमिका

यह पता लगाया जाना चाहिए कि फाई जैसे मानवाधिकार कार्यकर्ता कैसे पड़ोसी मुल्क के भेदिए बन जाते हैं? कैसे वे डबल एजेंट बनकर शत्रु राष्ट्र के लिए काम करना शुरू कर देते हैं. फाई तो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल हुआ ही, उसने पड़गावकर जैसे पत्रकारों, जिनकी भारत सरकार में अच्छी पैठ है, को भी अपना मोहरा बनाया. इन मोहरों को पाकिस्तान से धन दिलाया गया. वाशिंगटन, लंदन या ब्रूसेल्स में आयोजित सम्मेलन में बुलाकर ख़ूब आवभगत की गई और जेबों को डॉलरों से भर दिया गया. फिर उन्हें भारत वापस जाकर गृह मंत्रालय को बताने के लिए कहा गया कि वाशिंगटन के सम्मेलन में क्या हुआ? इस तरह वार्ताकारों की टीम ने डबल एजेंट की भूमिका निभाई. एक तरफ़ तो वे फाई के खासमखास बने रहे, डॉलरों की कमाई की, बिजनेस क्लास का एयर टिकट हासिल किया, दूसरी ओर गृह मंत्रालय के माननीय अतिथि भी बने रहे. पड़गावकर जैसे लोग स्वयं को वामपंथी विचारक प्रचारित करते हैं, लेकिन उनकी भूमिका इसके विपरीत होती है. फाई पाकिस्तान का कोई साधारण एजेंट नहीं था. वह पाकिस्तानी घुसपैठिया था और आईएसआई से प्रतिवर्ष 6 लाख से लेकर साढ़े सात लाख डॉलर तक की राशि हासिल करता था. भारत सरकार द्वारा अपने लॉबिस्टों पर ख़र्च की जाने वाली राशि से भी यह ज़्यादा है. वर्जीनिया में रहने वाले इस शख़्स की जीवनशैली किसी राजा–महाराजा से कम नहीं थी. उसके भारतीय अतिथियों में बिकाऊ पत्रकार और बोगस लेखकों का समावेश रहता था, जो खाते भारत की हैं, लेकिन गुणगान पाकिस्तान का करते हैं. सीधे तौर पर ऐसा करना मुमकिन नहीं, इसलिए मानवाधिकार की आड़ में बयानबाज़ी की जाती है. फाई अच्छी तरह जानता था कि भारतीय नेताओं एवं तथाकथित पत्रकारों के विदेशी दौरों में ख़ूब पैसों की आवश्यकता होती है, ताकि वे विदेशी वस्तुएं ख़रीद सकें. ऐसे लोग तब तक विदेश यात्रा पर नहीं जाते, जब तक कोई उनके जाने–आने और रहने–खाने का प्रबंध न कर दे. ऐसे में यदि फाई जैसे लोग 5 से 10 हज़ार डॉलर अतिरिक्त उपलब्ध कराने के लिए राजी हो जाते हैं तो फिर ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं. चाहे इन्हें अपने देश को गाली ही क्यों न देनी पड़े.

सरकार में कितना दम

क्या भारत सरकार में इतना दम है कि सब कुछ जानने के बाद वह उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई करे. संभव है कि वह किन्हीं और नामों में से वार्ताकारों की नियुक्ति कर दे. पड़गावकर जैसे लोगों का नाम इस मामले में हमेशा भारतीय सूची में सबसे ऊपर होगा. यदि नहीं भी हुआ तो पाकिस्तान की सूची में तो है ही, जहां आपके बैंक खाते में डॉलरों की बारिश होती रहती है. हम केवल ऐसे लोगों का विरोध कर सकते हैं. बचपन से हमें सिखाया जाता है कि अपने देश और सरकार का दूसरों के सामने कभी विरोध मत करो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों. पाकिस्तान और फाई ऐसे भारतीयों की ओर देखकर ज़रूर हंसते होंगे, जो कुछ डॉलरों के लिए अपने देश के ख़िलाफ़ कुछ भी करने–कहने के लिए तैयार हो जाते हैं. ऐसे भारतीयों को, जो सोचते हैं कि उनके विचार देश से भी बड़े हैं, जो विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा धूमिल करते हैं, दंडित करना ही होगा.

feedback@chauthiduniya.com

देश का पहला इंटरनेट टीवी

हर दिन 50,000 से ज़्यादा दर्शक

- दो टूक–संतोष भारतीय के साथ
- ब्लैक एंड व्हाइट रोज़ाना 1 बजे
- पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया
- स्पेशल रिपोर्ट
- नायाब हैं हम–उर्दू के मशहूर शायरों, गीतकारों के साथ मुलाक़ात
- साई की महिमा

एफ–2, सेक्टर–11, नोएडा–201301 www.chauthiduniya.tv

विजयदशमी का दिन हिंदुओं को बहुत शुभ है और सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन को चुना जाना सर्वथा उचित है.

सभी पर दया और उपकार

एक समय रामचंद्र पाटिल बहुत बीमार हो गए. उन्हें बहुत कष्ट हो रहा था. सब प्रकार के उपचार किए गए, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ और जीवन से हताश होकर वे मृत्यु के अंतिम क्षणों की प्रतीक्षा करने लगे. तब एक दिन मध्य रात्रि के समय बाबा अनायास उनके सिरहाने प्रगट हुए. पाटिल उनके चरणों से लिपट कर कहने लगे कि मैंने अपने जीवन की समस्त आशाएं छोड़ दी हैं. अब कृपा करके मुझे इतना तो निश्चित बतलाइए कि मेरे प्राण अब कब निकलेंगे. दया सिंधु बाबा ने कहा कि घबराओ नहीं, तुम्हारी हुंडी वापस ले ली गई है और तुम शीघ्र ही स्वस्थ हो जाओगे. मुझे तो केवल तात्या का भय है कि 1918 में विजयदशमी के दिन उसका देहांत हो जाएगा, किंतु यह भेद किसी से प्रगट न करना और न किसी को बतलाना, अन्यथा वह अधिक भयभीत हो जाएगा. रामचंद्र अब पूर्ण स्वस्थ हो गए, परंतु वह तात्या के जीवन के लिए निराश हुए. उन्हें ज्ञात था कि बाबा के शब्द कभी असत्य नहीं निकल सकते और दो वर्ष के पश्चात तात्या इस संसार से विदा हो जाएंगे. उन्होंने यह भेद बाला शिंपी के अतिरिक्त किसी से भी प्रगट नहीं किया. केवल दो ही व्यक्ति रामचंद्र दादा एवं बाला शिंपी तात्या के जीवन के लिए चिंताग्रस्त और दु:खी थे.

रामचंद्र ने शैया त्याग दी और वह चलने-फिरने लगे. समय तेजी से व्यतीत होने लगा. शके 1840 का भाद्रपद समाप्त होकर आश्विन मास प्रारंभ होने ही वाला था कि बाबा के वचन पूर्णत सत्य निकले. तात्या बीमार पड़ गए और उन्होंने चारपाई पकड़ ली. उनकी स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि अब वह बाबा के दर्शनों को भी जाने में असमर्थ हो गए. इधर बाबा भी ज्वर से पीड़ित थे. तात्या का पूर्ण विश्वास बाबा पर था और बाबा का भगवान श्री हरि पर, जो उनके संरक्षक थे. तात्या की स्थिति अब और अधिक चिंताजनक हो गई. वह हिल-डुल भी नहीं सकते थे और सदैव बाबा का ही स्मरण करते रहते थे. इधर बाबा की भी स्थिति उत्तरोत्तर गंभीर होने लगी. बाबा द्वारा बताया हुआ विजयदशमी का दिन भी निकट आ गया. तब रामचंद्र दादा और बाला शिंपी बहुत घबरा गए. उनके शरीर कांप रहे थे, पसीने की धाराएं प्रवाहित हो रही थीं कि अब तात्या का अंतिम साथ है. जैसे ही विजयदशमी का दिन आया, तात्या की नाड़ी की गति मंद होने लगी और उनकी मृत्यु सन्निकट दिखाई देने लगी. उसी समय एक विचित्र घटना घटी. तात्या की मृत्यु टल गई और उनके प्राण बच गए, परंतु उनके स्थान पर बाबा स्वयं प्रस्थान कर गए और ऐसा प्रतीत हुआ, जैसे परस्पर हस्तांतरण हो गया हो. सभी लोग कहने लगे कि बाबा ने तात्या के लिए प्राण त्यागे. ऐसा उन्होंने क्यों किया, यह वह ही जानें, क्योंकि यह बात हमारी बुद्धि के बाहर की है. ऐसा भी प्रतीत होता है कि बाबा ने अपने अंतिम काल का संकेत तात्या का नाम लेकर ही किया था.

दूसरे दिन 16 अक्टूबर को प्रात:काल बाबा ने दासगणू को पंढरपुर में स्वप्न दिया कि मस्जिद अर्रा करके गिर पड़ी है. शिरडी के प्राय: सभी तेली-तंबोली मुझे कष्ट देते थे, इसलिए मैंने अपना स्थान छोड़ दिया है. मैं तुम्हें यह सूचना देने आया हूं कि कृपया शीघ्र वहां जाकर मेरे शरीर पर हर तरह के फूल इकट्ठा कर चढ़ाओ. दासगणू को शिरडी से भी एक पत्र प्राप्त हुआ और वह अपने शिष्यों को साथ लेकर शिरडी आए तथा उन्होंने बाबा की समाधि के समक्ष अखंड कीर्तन और हरिनाम प्रारंभ कर दिया. उन्होंने स्वयं फूलों की माला गूंथी और ईश्वर का नाम लेकर समाधि पर चढ़ाई. बाबा के नाम पर एक भोज का भी आयोजन किया गया.

विजयदशमी का दिन हिंदुओं को बहुत शुभ है और सीमोल्लंघन के लिए बाबा द्वारा इस दिन को चुना जाना सर्वथा उचित है. इसके कुछ दिनों पूर्व से ही उन्हें अत्यंत पीड़ा हो रही थी, परंतु आंतरिक रूप में वह पूर्ण सजग थे. अंतिम क्षण के पूर्व वह बिना किसी की सहायता लिए उठकर सीधे बैठ गए और स्वस्थ दिखाई पड़ने लगे. लोगों ने सोचा कि संकट टल गया और अब भय की कोई बात नहीं है तथा अब वह शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएंगे, परंतु वह तो जानते थे कि अब मैं शीघ्र ही विदा लेने वाला हूं और इसलिए उन्होंने लक्ष्मीबाई शिंदे को कुछ दान देने की इच्छा प्रगट की. लक्ष्मीबाई एक उच्च कुलीन महिला थीं. वह मस्जिद में बाबा की दिन-रात सेवा किया करती थीं. केवल भगत म्हालसापति, तात्या और लक्ष्मीबाई के अतिरिक्त रात को मस्जिद की सीढ़ियों पर कोई नहीं चढ़ सकता था. एक बार संध्या समय जब बाबा तात्या के साथ मस्जिद में बैठे हुए थे, तभी लक्ष्मीबाई ने आकर उन्हें नमस्कार किया. तब बाबा कहने लगे कि अरी लक्ष्मी, मैं अत्यंत भूखा हूं. वह यह कहकर लौट पड़ीं कि बाबा, थोड़ी देर ठहरो, मैं अभी आपके लिए रोटी लेकर आती हूं. उन्होंने रोटी और साग लाकर बाबा के सामने रख दिया, जो उन्होंने एक भूखे कुत्ते को दे दिया. तब लक्ष्मीबाई कहने लगीं कि बाबा, यह क्या? मैं तो शीघ्र गई और अपने हाथ से आपके लिए रोटी बना लाई. आपने एक ग्रास भी ग्रहण किए बिना उसे कुत्ते के सामने डाल दिया. तब आपने व्यर्थ ही मुझे यह कष्ट क्यों दिया? बाबा ने उत्तर दिया, व्यर्थ दु:ख न करो. कुत्ते की भूख शांत करना मुझे तृप्त करने के बराबर ही है. कुत्ते की भी तो आत्मा है. प्राणी चाहे भले ही भिन्न आकृति-प्रकृति के हों, उनमें कोई बोल सकते हैं और कोई मूक हैं, परंतु भूख सबकी एक सदृश ही है. इसे तुम सत्य जानो कि जो भूखों को भोजन कराता है, वह यथार्थ में मुझे ही भोजन कराता है. यह एक अकाट्य सत्य है.

इस साधारण घटना द्वारा बाबा ने एक महान आध्यात्मिक सत्य की शिक्षा प्रदान की कि बिना किसी की भावनाओं को कष्ट पहुंचाए किस प्रकार उसे नित्य व्यवहार में लाया जा सकता है. इसके बाद लक्ष्मीबाई उन्हें नित्य प्रेम और भक्तिपूर्वक दूध, रोटी एवं अन्य भोजन देने लगीं, जिसे वह स्वीकार कर बड़े चाव से खाते थे. वह उसमें से कुछ खाकर शेष लक्ष्मीबाई द्वारा ही राधाकृष्ण माई के पास भेज दिया करते थे, जिसे वह प्रसाद स्वरूप समझ कर प्रेमपूर्वक खाती थीं. इस कथा से सिद्ध होता है कि सभी प्राणियों में बाबा का निवास है, जो सर्वव्यापी, जन्म-मृत्यु से परे और अमर हैं. बाबा ने लक्ष्मीबाई की सेवाओं को सदैव याद रखा. बाबा उनको भुला भी कैसे सकते थे. देह त्याग के पूर्व बाबा ने अपनी जेब में हाथ डाला और पहले उन्होंने लक्ष्मी को पांच रुपये और बाद में चार रुपये यानी इस प्रकार कुल नौ रुपये दिए. बाबा सदैव सजग और चैतन्य रहते थे और उन्होंने अंतिम समय भी पूर्ण सावधानी से काम लिया. अपने भक्तों के प्रति बाबा का हृदय प्रेम, ममता या मोह से ग्रस्त न हो जाए, इस कारण उन्होंने अंतिम समय सबको वहां से चले जाने का आदेश दिया. चिंतामग्न काका साहेब दीक्षित, बापू साहेब बूटी और अन्य महानुभाव, जो मस्जिद में बाबा की सेवा में उपस्थित थे, उन्हें भी बाबा ने वाड़े में जाकर भोजन करके लौट आने को कहा. ऐसी स्थिति में वे बाबा को अकेला छोड़ना तो नहीं चाहते थे, परंतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी तो नहीं कर सकते थे, इसलिए इच्छा न होते हुए भी उदास और दु:खी हृदय से उन्हें वाड़े में जाना पड़ा. उन्हें विदित था कि बाबा की स्थिति अत्यंत चिंताजनक है और इस प्रकार उन्हें अकेला छोड़ना उचित नहीं है. वे भोजन करने के लिए बैठे तो, परंतु उनके मन कहीं और (बाबा के साथ) थे. अभी भोजन समाप्त भी नहीं हो पाया था कि बाबा द्वारा शरीर त्यागने का समाचार उनके पास पहुंचा और वे अपनी-अपनी थाली छोड़कर मस्जिद की ओर भागे और जाकर देखा कि बाबा सदा के लिए बयाजी आपा कोते की गोद में विश्राम कर रहे हैं. न वह नीचे लुढ़के और न शैय्या पर लेटे. अपने ही आसन पर शांतिपूर्वक बैठे हुए और अपने ही हाथों से दान देते हुए उन्होंने मानव शरीर त्याग दिया. संत स्वयं देह धारण करते हैं और कोई निश्चित ध्येय लेकर ही इस संसार में प्रगट होते हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

श्री सद्गुरु साई बाबा के ग्यारह वचन

1. जो शिरडी आएगा, आपद दूर भगाएगा.
2. चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर.
3. त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा.
4. मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस.
5. मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो, सत्य पहचानो.
6. मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए.
7. जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का.
8. भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा.
9. आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर.
10. मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया.
11. धन्य धन्य व भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य.

www.nationalinsuranceindia.com

Your happiness has been our greatest reward

For the last 105 years we have been securing our customers against unforeseen circumstances, keeping every worry out of their lives. This has made us the fastest growing public sector non-life insurance company (growing at a rate of 34.42%) besides having been bestowed the highest awards for customer service. But for us, it is your satisfaction that has been our biggest motivation, always.

"Most Preferred Non-Life Insurer" (CNBC Awaaz Consumer Awards from 2007 - 2009), "Highest in Customer Satisfaction" (JD Power Asia Pasific 2010 India Auto Insurance Customer Satisfaction Index Study) & "Top PSU for Customer Service" (HT- MaRs Survey of India's Best Medical Insurers)

- Gross Premium - ₹6245 crores as compared to ₹4646 crores last year
- Largest in volume, Best in service for Motor (OD)
- Leader in RSBY scheme (Health) amongst Non-Life PSUs

Thoda Simple Socho

नेशनल इन्श्योरेन्स
National Insurance

Prompt Service. Hassle-free Process. Fair Settlement.

National Insurance Company Limited(A Govt. of India undertaking), Registered Head Office : 3 Middleton Street, Kolkata 700 071

Highest Accretion in the industry: ₹1600 crores

Highest Growth in the industry*: 34.42%

Insurance is the subject matter of solicitation

105 YEARS OF SERVING THE NATION

*Among Non-Life Insurance Companies with turnover more than ₹1500crs. Figures as per 2010-11

शिक्षा पूर्ण करने के बाद आर सी बाबू की साहित्यिक रुचि एवं लेखन शैली से प्रभावित होकर बेनीपुरी जी ने उन्हें युवक में अवसर प्रदान किया. बेनीपुरी जी उन दिनों युवक के संपादक थे.

अनंत विजय

व्यक्तित्व की पाखी

मैं जब यह स्तंभ लिखने बैठा तो एक बार फिर से राजेंद्र यादव मेरे ध्यान में आए, लेकिन मैं अभी दो हफ्ते पहले ही यादव जी के इर्द–गिर्द दो लेख लिख चुका हूं. इस वजह से एक बार फिर उन पर लिखते हुए सोचने को मजबूर हूं कि लिखूं या नहीं लिखूं. दरअसल पहला लेख तो हंस पत्रिका के पच्चीस वर्ष पूरे होने और छब्बीसवें वर्ष में प्रवेश करने पर था और दूसरा लेख दिल्ली में आयोजित हंस की सालाना गोष्ठी पर, लेकिन दोनों के ही केंद्र में राजेंद्र यादव थे. साहित्य की दुनिया में हर वर्ष जुलाई और अगस्त का अंतिम सप्ताह राजेंद्र यादव के नाम होता है. जुलाई के अंत में हंस की सालाना गोष्ठी और अगस्त के अंत में राजेंद्र यादव का जन्मदिन समारोह. इस साल भी हर वर्ष की भांति राजेंद्र यादव का जन्मदिन दिल्ली में कांग्रेस के युवा सांसद संजय निरूपम के घर के लॉन में मनाया गया. पिछले वर्ष की तुलना में इस बार का आयोजन भव्य था. लोगों की उपस्थिति भी ज़्यादा. रसरंजन करते टुन्न होते लोग भी ज़्यादा, लेकिन इस बार मैं यादव जी के जन्मदिन समारोह पर नहीं लिख रहा हूं. जिक्र इस वजह से कि जिस पत्रिका पर लिखने जा रहा हूं, वह मुझे यादव जी के जन्मदिन समारोह में मिली. पत्रिका का नाम है पाखी, जिसके संपादक हैं प्रेम भारद्वाज.

प्रेम भारद्वाज जी से मेरी फोन पर कई बार बात हुई थी, लेकिन कभी आमने–सामने की मुलाक़ात नहीं हुई थी. मुझे पता नहीं, उन्होंने कैसे पहचाना और बेहद गर्मजोशी से मुझसे मिले. मिलने के बाद उन्होंने मुझे पाखी का राजेंद्र यादव पर केंद्रित भारी–भरकम अंक दिया, जो एक दिन पहले लोकार्पित हुआ था. वहां तो कवर पर यादव जी की भव्य तस्वीर ही देख पाया. पाखी के इस अंक का विज्ञापन कई अंकों से संभावित लेखकों के नाम के साथ छप रहा था. इसके अलावा मैत्रेयी जी, भारत भारद्वाज जी से भी कई बार इस प्रस्तावित अंक पर बात हुई थी. यादव जी का व्यक्तित्व इतना तिलिस्मी है कि वह मुझे बार–बार खींचता है और जब भी उनके बारे में कुछ पढ़ता हूं या उनके आसपास के लोगों से बात होती है तो कुछ न कुछ नया मिल ही जाता है, चाहे वे लोगों के अनुभव हों या फिर यादव जी के

दिलचस्प कारनामे.

जन्मदिन की पार्टी से जब घर लौटा तो पाखी को पढ़ना शुरू किया. कई लेख पुराने हैं, लेकिन नए लेखों की संख्या ज़्यादा है. सबसे पहले मैंने संपादकीय पढ़ा. संपादकीय पहले पढ़ने का फ़ायदा यह होता है कि अंक का अंदाज़ा लग जाता है. पाखी के इस अंक का संपादकीय अद्भुत है. प्रेम भारद्वाज ने राजेंद्र यादव के व्यक्तित्व को राजकपूर से जोड़कर अनोखे तरीक़े से व्याख्यायित किया है. वह लिखते हैं, राजकपूर द्वारा पहली निर्देशित फिल्म आग की शुरुआत 6 जुलाई, 1947 को होती है. राजेंद्र यादव की पहली कहानी प्रतिहिंसा भी इसी साल कर्मयोगी में प्रकाशित होती है. आग दोनों में है, रचनात्मकता की. आग का नायक जीवन में कुछ नया कर गुजरना चाहता था. जलती हुई महत्वाकांक्षा उसका ईंधन बनी. क्या यही सच राजेंद्र यादव का नहीं है. राजू को स्त्री की देह (अनावृत्त स्त्री) पसंद है, जिसे चलती भाषा में नंगापन कहा जाता है. नंगेपन को वह रचनाओं में दिखाता है...थोड़ी ज़्यादा उम्र बढ़ने पर स्त्री सौंदर्य के प्रति उसका नज़रिया मांसल हो जाता है. सत्यम शिवम सुंदरम और राम तेरी गंगा मैली...हासिल और होना सोना एक दुश्मन साथ ऐसी ही रचनाएं हैं. वह आवारा, छलिया, श्री 420 है. बहुत दिनों बाद नए तरीक़े से लिखा गया संपादकीय पढ़कर मजा आ गया. प्रेम भारद्वाज को बधाई देने के लिए फोन भी किया, लेकिन फोन बंद था. ख़ैर...

आम तौर पर ऐसे विशेषांकों में लेखक की प्रशस्ति करते लेखों को संग्रहित किया जाता है और वह लगभग अभिनंदन ग्रंथ बनकर रह जाता है, लेकिन राजेंद्र यादव पर केंद्रित पाखी का यह अंक इस दोष का शिकार होने से बच गया. इसमें कई लेख ऐसे हैं, जो यादव जी के व्यक्तित्व की तो धज्जियां उड़ाते ही हैं, उनके लेखन को भी कसौटी पर कसते हैं. पुराने लेखों की चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा, लेकिन चाहे वह निर्मला जैन का लेख हो या फिर यादव जी के भाई भूपेंद्र सिंह यादव या फिर उनकी बेटी रचना के लेख हों, सब में एक ही स्वर है कि यादव जी पारिवारिक व्यक्ति नहीं हैं और उन्होंने अपनी पारिवारिक ज़िम्मेदारियों का निर्वाह नहीं किया. ये बातें जब बेटी और भाई कहें तो मान लेना चाहिए.

मैत्रेयी पुष्पा को अब तक राजेंद्र यादव की पसंदीदा लेखिका माना जाता था. दिल्ली के साहित्यिक हलके में यह बात बार–बार उठती रहती थी कि मैत्रेयी पुष्पा अब यादव जी के खेमे में नहीं रहीं और उन्होंने अशोक वाजपेयी के कैंप में अपनी जगह बना ली है. अफवाहों को नित नए पंख लगते रहे, लेकिन पाखी के इस अंक में मैत्रेयी पुष्पा ने साफ–साफ ऐलान कर दिया है कि उन्हें अब राजेंद्र यादव से कुछ लेना–देना नहीं. छिनाल विवाद के बाद जिस तरह मैत्रेयी जी ने विभूति नारायण राय के ख़िलाफ़ मोर्चा खोला था, उसमें यादव जी के साथ न आने से आहत मैत्रेयी कहती हैं कि राजेंद्र जी ने भरोसे को तोड़ा है. विभूति नारायण राय के ख़िलाफ़ उस वक़्त मैत्रेयी ने मोर्चा खोला हुआ था, लेकिन साल बीतते हालत यह हो गई कि उनके बड़े से बड़े सिपहसालार ने राय का दामन थाम लिया. विरोध तो हवा में गुम हो गया, कुछ तो राय साहब के प्रशंसक तक बन बैठे हैं. सुधा अरोड़ा का साक्षात्कार सामान्य है. दामोदर दत्त दीक्षित और भारत यायावर ने यादव जी को जरा ज़्यादा ही कस दिया है. साहित्यिक पत्रकारिता के पच्चीस वर्ष पर प्रेमपाल शर्मा का छोटा, लेकिन गंभीर लेख है. प्रेमपाल शर्मा चाहें तो उस लेख को और विस्तार दे सकते हैं, अभी उसमें काफी गुंजाइश है. इस अंक का जो सबसे कमज़ोर पक्ष है, वह है संस्मरण. सभी में लगभग एक जैसी बात है और लोग अपने बारे में ज़्यादा, यादव जी के बारे में कम लिख रहे हैं. भारत भारद्वाज के संस्मरण में मृत्यु को लेकर लेखक और यादव जी का संवाद दिलचस्प है. भारत भारद्वाज पूछते हैं, आप नहीं रहेंगे तो जनसत्ता में क्या शीर्षक छपेगा. पहले तुम बताओ. मैंने कहा, खलनायक नहीं रहे. उन्होंने प्रतिवाद किया, अच्छा और उपयुक्त शीर्षक रहेगा, अब खलनायक नहीं रहे. दो रचनाकार अपनी मृत्यु को लेकर इतने खिलंदड़े अंदाज़ में बात कर रहे हों और मौत के बाद अख़बार का शीर्षक तय कर रहे हों, कमाल है. पाखी के इस अंक में इस बात का भी ख़ुलासा हुआ है कि पिछले बीस सालों से हंस में प्रकाशित लोकप्रिय स्तंभ–समकालीन सृजन संदर्भ अब बंद हो गया है. अब लोग हंस को आगे से खोला करेंगे (काशीनाथ जी समेत कई लेखकों ने मुझसे व्यक्तिगत बातचीत में कहा था कि वह हंस को पीछे से खोलते हैं)

पाखी का राजेंद्र यादव पर निकला तीन–सवा तीन सौ पृष्ठों का यह अंक हिंदी के पाठकों के लिए एक थाती है और इसे संभाल कर रखना चाहिए. हिंदी के नए पाठकों के लिए यह एक ऐसे व्यक्ति के व्यक्तित्व की परतें उघाड़ता है, जो नए से नए लोगों को भी लिखने और पढ़ने के लिए लगातार प्रेरित करता है. इस अंक के लिए संपादक प्रेम भारद्वाज की जितनी भी सराहना की जाए, वह कम है.

(लेखक IBN7 से जुड़े हैं)
anant.ibn@gmail.com

महाकवि आर सी प्रसाद सिंह

अपनी ही धरती पर गुमनाम

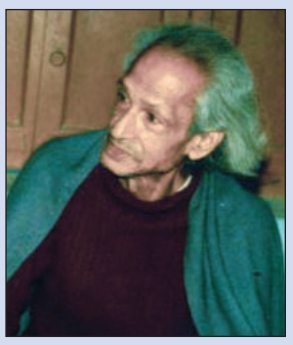

हिंदी साहित्य के छायावाद काल के द्वितीय चरण में गोपाल सिंह नेपाली, हरिवंश राय बच्चन, जानकी बल्लभ शास्त्री के समकालीन थे महाकवि आर सी प्रसाद सिंह, लेकिन साहित्य जगत में अपनी अमिट छाप छोड़ चुके कविवर आरसी के साथ किसी ने न्याय नहीं किया. साहित्यकारों, जनप्रतिनिधियों एवं सत्ता–शासन से जुड़े किसी भी व्यक्ति ने महाकवि को उचित सम्मान दिलाने के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी. स्थानीय जनप्रतिनिधियों और केंद्र में मंत्री रह चुके लोगों ने क्षेत्र में आकर घोषणा तो अवश्य की, लेकिन वापस जाते ही वे अपना वायदा भूल गए. कविवर आर सी का जन्म समस्तीपुर ज़िले के अंतर्गत रोसड़ा प्रखंड के एरौत गांव में 19 अगस्त, 1911 को हुआ था. महाकवि ने हिंदी साहित्य में बालकाव्य, कथाकाव्य, महाकाव्य, गीतकाव्य, रेडियो रूपक एवं कहानियों समेत कई रचनाएं हिंदी एवं मैथिली साहित्य को समर्पित की. शिक्षा पूर्ण करने के बाद आरसी बाबू की साहित्यिक रुचि एवं लेखन शैली से प्रभावित होकर बेनीपुरी जी ने उन्हें युवक में अवसर प्रदान किया. बेनीपुरी जी उन दिनों युवक के संपादक थे. युवक में प्रकाशित रचनाओं में उन्होंने ऐसे क्रांतिकारी शब्दों का प्रयोग किया कि तत्कालीन अंग्रेजी हुकूमत ने उनके ख़िलाफ़ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया.

आरसी बाबू साहित्य से जुड़े रहने के अलावा राजनीतिक रूप से भी जागरूक एवं निर्भीक रहे. उन्होंने अपनी लेखनी से नेताओं पर कटाक्ष करने में कोई कोर–कसर नहीं छोड़ी. नेताओं पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने लिखा है, बरसाती मेंढक से फूले, पीले–पीले गदराए, गांव–गांव से लाखों नेता खद्दरपोश निकल आए. पर्यावरण एवं हरियाली के प्रति सदा सजग रहने वाले महाकवि पेड़–पौधों की हो रही कटाई से मर्माहत होकर लिखते हैं, आज अरण्य स्वयं रूदन करता है और उसका रूदन कोई नहीं सुनता. अरण्य का रूदन कोई सुनता तो उस पर भला कुल्हाड़ी ही क्यों चलाता? आर सी प्रसाद सिंह से जुड़े संस्मरण सुनाते हुए पत्रकार संजीव कुमार सिंह बताते हैं, 1956 से 1958 के बीच उन्होंने आकाशवाणी लखनऊ एवं आकाशवाणी इलाहाबाद में हिंदी कार्यक्रम अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दीं. इस दौरान आकाशवाणी के एक अधिकारी उन पर हमेशा हावी रहते थे. एक दिन उन्होंने अमर चेतना का कलाकार, शिल्पी पराधीन होना नहीं चाहता, भुवन मोहिनी सृष्टि का विधाता कभी दीन होना नहीं चाहता, लिखकर अपना त्यागपत्र उसे सौंप दिया. आकाशवाणी की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन साहित्य के नाम कर दिया और मरते दम तक वह काव्य साधना में लीन रहे. किसी बुद्धिजीवी कलम का नियंत्रण सरीखा नहीं है पाप कोई, उदर के लिए स्वाभिमानी हृदय के दमन सा नहीं अन्य संताप कोई, न वनराज को पिंजड़ा है सुहाता, न गजराज को मंत्र अंकुश गंवारा, जैसी रचना उनके स्वाभिमान को परिलक्षित करती है. उनकी रचनाओं में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता एवं भाईचारे की झलक देखने को मिलती है. उनकी प्रमुख रचनाओं में आजकल (1937) कलापि (1938), संचियता (1942), आरसी (1942), जीवन और यौवन (1944), नई दिशा (1944), द्वंद्व समास (1961), आरण्यक (1985), कथामाला (1966), युद्ध अवश्यंभावी (1991), चाणक्य शिखा (1992), बदल रही है हवा (1992), आस्था का अग्निकुंड (1992) और भारत सावित्री (1996) आदि शामिल हैं. 1938 में कलापी के प्रकाशन पर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा था, कलापी का कवि मस्त है, सौंदर्य को देख लेने पर बिना कहे नहीं रुकता, भाषा पर सवारी करता है. आरसी के काव्य ग्रंथों में नंददास (1953), संजीवनी (1964), कुंवर सिंह (1989), रजनीगंधा (1980) और कथा संकलनों में पंचपल्लव (1942), खोटा सिक्का (1942), कालरात्रि (1944), एक प्याली चाय (1945), आंधी के पत्ते (1945), ठंडी छाया (1956), वे तुतलाते थे (1989) आदि प्रमुख हैं. बाल साहित्य में भी उनका योगदान अविस्मरणीय है. चंदा मामा (1944), चित्रों की लोरियां (1953), ओनामासी (1953), रामकथा (1954), जादू की वंशी (1954), सोने का झरना (1985), कागज की नाव (1966), बाल गोपाल (1966), जगमग (1967), कलम और बंदूक (1981), पंचमेल (1996) आदि रचनाएं महाकवि के लेखन की गवाह बनीं.

इसके अलावा पांच दर्जन से अधिक पांडुलिपियां अभी भी अप्रकाशित हैं. आरसी बाबू देश–प्रदेश की अनेक संस्थाओं एवं सरकार द्वारा समय–समय पर सम्मानित और पुरस्कृत भी हुए. बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति विभाग ने कई बार उनकी पांडुलिपियां लीं, जो आज तक प्रकाशित नहीं हो सकीं. रोसड़ा के सांसद रह चुके राम विलास पासवान ने अपने रेलमंत्रित्व काल में रोसड़ा स्टेशन का नाम बदल कर महाकवि के नाम पर करने की घोषणा की थी, जो आज तक लंबित है. पूर्व मंत्री गजेंद्र प्रसाद सिंह ने रोसड़ा–हथौड़ी पथ का नाम आर सी सुमन पथ करने की घोषणा की. दोनों स्थलों पर बोर्ड भी लगाया गया, लेकिन नामकरण आज भी ठंडे बस्ते में है.

विकास कुमार
feedback@chauthiduniya.com

किताब मिली

पुस्तक का नाम
कश का विनाश

लेखक
रॉबर्तो कलासो

प्रकाशक
राजकमल प्रकाशन

मूल्य
600 रुपये

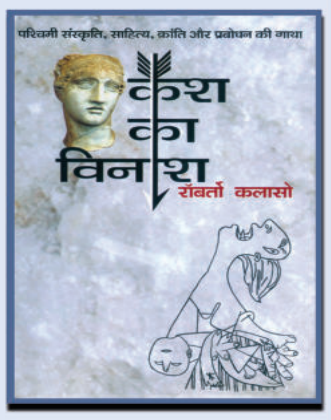

इस पुस्तक में पश्चिमी संस्कृति, साहित्य और क्रांतियों के बारे में विस्तार से बताया गया है.

सभी के लिए उपयोगी पुस्तकें

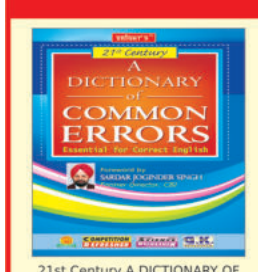

21st Century A DICTIONARY OF COMMON ERRORS
₹ 99

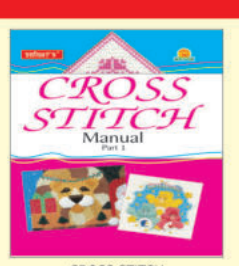

CROSS STITCH Manual Part - 1
₹ 60

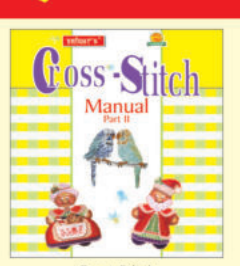

Cross-Stitch Manual Part - II
₹ 70

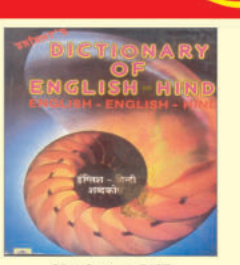

21st Century DICT ENGLISH - HINDI
₹ 75

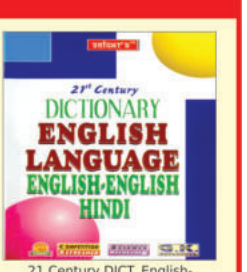

21 Century DICT. English-English-Hindi
₹ 125

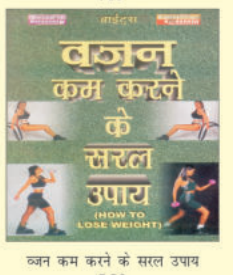

वजन कम करने के सरल उपाय
₹ 50

इंगलिश सीखिए और बोलिए
₹ 199

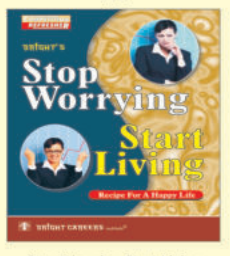

Stop Worrying Start Living
₹ 50

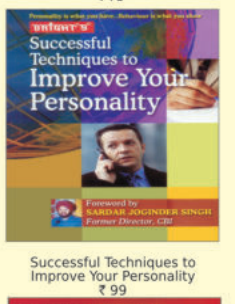

Successful Techniques to Improve Your Personality
₹ 99

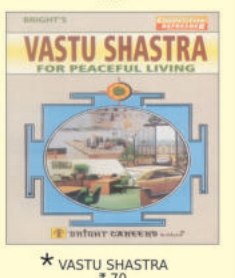

★ VASTU SHASTRA
₹ 70

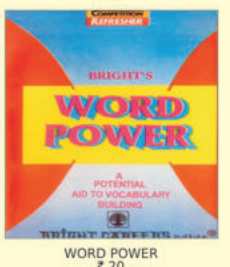

WORD POWER
₹ 20

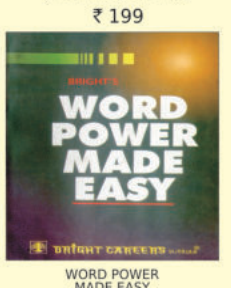

WORD POWER MADE EASY
₹ 80

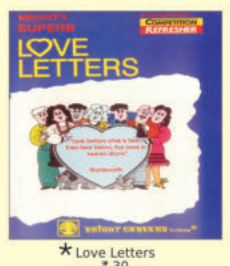

★ Love Letters
₹ 30

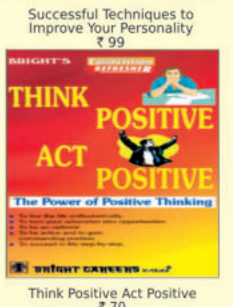

Think Positive Act Positive
₹ 70

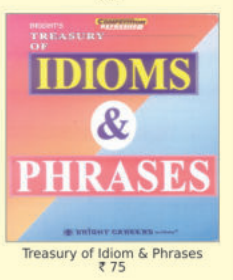

Treasury of Idiom & Phrases
₹ 75

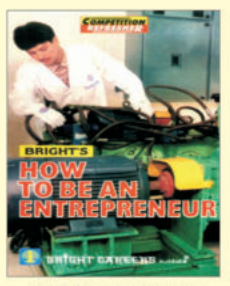

How to be an Entrepreneur
₹ 50

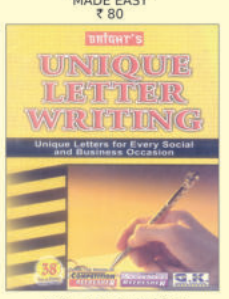

Unique Letter Writing
₹ 45

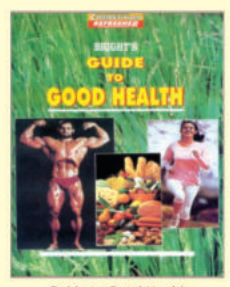

Guide to Good Health
₹ 40

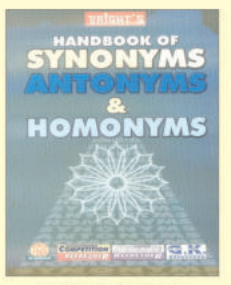

Handbook of Synonyms, Antonyms & Homonyms
₹ 75

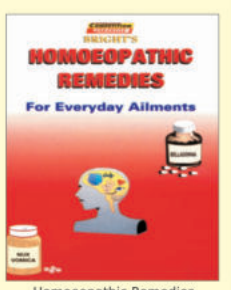

Homoeopathic Remedies
₹ 40

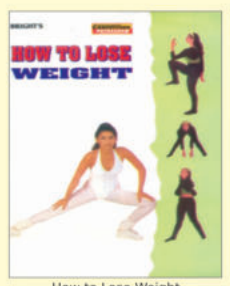

How to Lose Weight
₹ 50

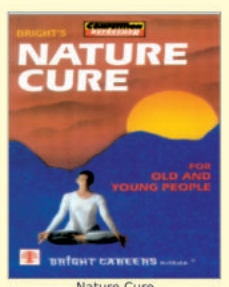

Nature Cure
₹ 35

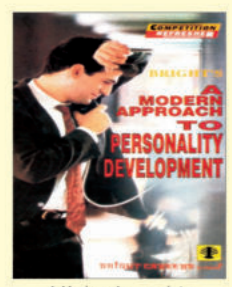

A Modern Approach to Personality Development
₹ 45

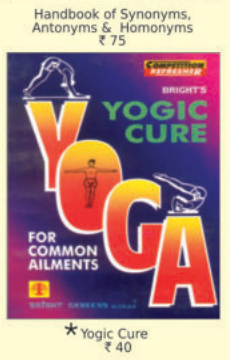

★ Yogic Cure
₹ 40

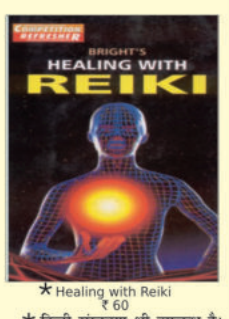

★ Healing with Reiki
₹ 60
★ हिन्दी संस्करण भी उपलब्ध है।

ब्राईट पब्लिकेशंस
भारत में सर्वाधिक बिकने वाली प्रतियोगिता पुस्तकों के प्रकाशक
2767, कूचा चैलान, दरियागंज, दिल्ली–110002 (भारत) (स्थापित : 1968)
फोन : 011-64632226, 23282226, 23283226 — फैक्स : 011-23269227
ई–मेल: sales@brightpublications.com | वैब साइट: http://www.brightpublications.com

ऑडी क्यू-5 पहले से ही भारत में काफी लोकप्रिय है. इसकी आकर्षक क़ीमत अब इसे और बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचाएगी.

मोटोरोला के नए फोन

बाज़ार में आएदिन नई-नई कंपनियां अलग-अलग तरीक़े के मोबाइल फोन लांच कर रही हैं. वे अब आम लोगों को ध्यान में रखकर अपने मोबाइल सेट बाज़ार में उतार रही हैं.

देशी-विदेशी कंपनियां मोबाइल बाज़ार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा को देखते हुए नए फीचरों से लैस विभिन्न तरीक़े के मोबाइल फोन लांच करने में लगी हुई हैं. आजकल मोबाइल फोन न केवल एक ज़रूरत, बल्कि दिनचर्या का हिस्सा बन गए हैं. हर उम्र और वर्ग के लोगों में मोबाइल की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए बाज़ार में आएदिन नई-नई कंपनियां अलग-अलग तरीक़े के मोबाइल फोन लांच कर रही हैं. वे अब आम लोगों को ध्यान में रखकर अपने मोबाइल सेट बाज़ार में उतार रही हैं. इसी क्रम में प्रमुख मोबाइल निर्माता कंपनी मोटोरोला ने एक साथ तीन मोबाइल फोन बाज़ार में उतारे हैं. ये सभी फोन डुअल सिम वाले हैं. ईएक्स-212, मोटोरोला-119 और मोटोरोला-109 नामक इन स्लिम स्टाइलिश फोनों के डिज़ाइन विशेष रूप से बनाए गए हैं. इन सभी में 2.4 इंच की टच स्क्रीन लगाई गई है. कंपनी का कहना है कि इनकी स्क्रीन में विशेष तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इसमें ज़्यादा साफ़ और स्पष्ट तस्वीरें देखने को मिलेंगी. दो सिम वाले मोबाइलों के बढ़ते बाज़ार को देखते हुए ही कंपनी ने ये स्लिम मोबाइल लांच किए हैं. इनमें 2 मेगा पिक्सल कैमरा लगा है, साथ ही ऑडियो और वीडियो प्लेयर की सुविधा भी दी गई है.

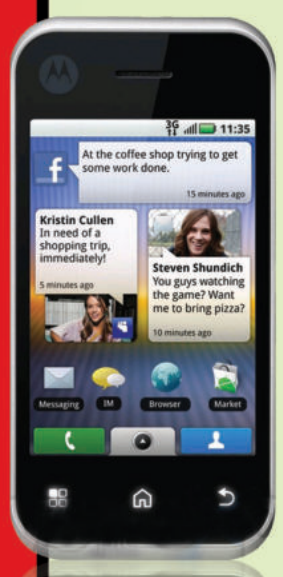

आसुस की नई नेटबुक

अब लैपटाप के प्रति भी लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है. उसकी जगह अब नेटबुक लेती जा रही है. कारण, यह लाने-ले जाने में काफी हल्की और ट्रेंडी होती है. वर्ड प्रोसेसिंग के साथ-साथ इसमें इंटरनेट सर्फ़िंग भी बड़े आराम से की जा सकती है.

एक समय था, जब लोग महंगी तकनीक के चलते लैपटॉप के बजाय डेस्कटॉप पर ज़्यादा निर्भर थे, मगर दिनोंदिन सस्ती होती तकनीक के चलते अब आम आदमी की पहुंच भी लैपटॉप तक है. इस समय बाज़ार में 15,000 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक के लैपटॉप मौजूद हैं, पर अब लैपटाप के प्रति भी लोगों का आकर्षण कम होता जा रहा है. उसकी जगह अब नेटबुक लेती जा रही है. कारण, यह लाने-ले जाने में काफी हल्की और ट्रेंडी होती है. वर्ड प्रोसेसिंग के साथ-साथ इसमें इंटरनेट सर्फ़िंग भी बड़े आराम से की जा सकती है. इसी को ध्यान में रखते हुए लैपटॉप और नेटबुक तकनीक में अग्रणी कंपनी आसुस ने बाज़ार में नई नेटबुक लांच की है. कंपनी का कहना है कि आसुस एक्स-101 नामक यह नेटबुक बाज़ार में इस श्रेणी की अन्य किसी नेटबुक के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा बेहतर है. इस नेटबुक में इंटेल का एन-455 सीपीयू लगाया गया है. एक किलोग्राम से कम वजन वाली इस नेटबुक को आप कहीं भी बहुत आसानी के साथ ले जा सकते हैं. इस नेटबुक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें एंटी वायरस सिस्टम लगाया गया है, जो इसे सुरक्षित बनाता है. कंपनी का मानना है कि यह नेटबुक ग्राहकों को काफी पसंद आएगी और इससे कंपनी का बाज़ार बढ़ाने में मदद मिलेगी.

एचपी की पोर्टेबल नोटबुक

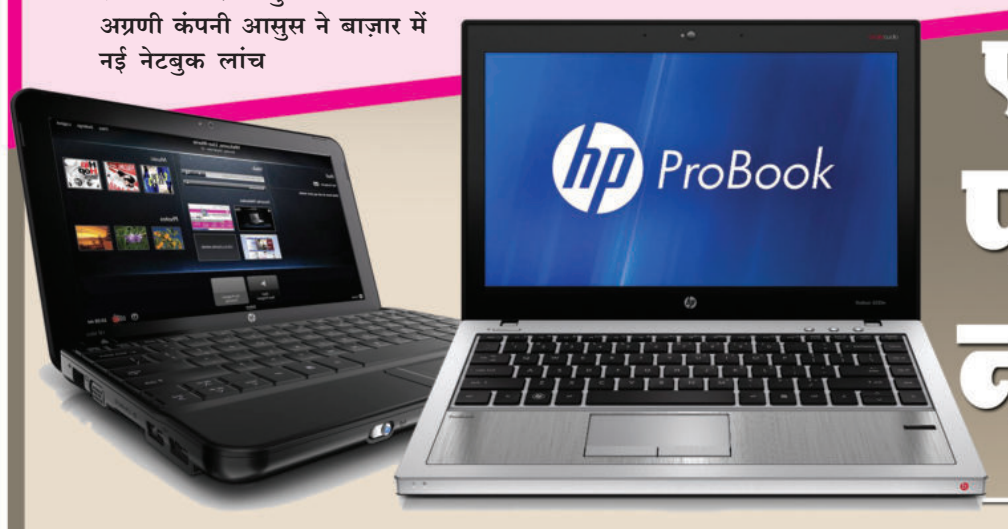

भारतीय बाज़ार दुनिया भर की कंपनियों की पसंद बनता जा रहा है, इसलिए सभी कंपनियां यहां अपने उत्पाद लांच करती रहती हैं. इसी क्रम में अब दुनिया की जानी-मानी कंपनी हालेट पेकर्ड ने भारतीय बाज़ार में अल्ट्रा पोर्टेबल नोटबुक लांच की है. कंपनी का कहना है कि यह नोटबुक स्टाइल, गुणवत्ता और काम के हिसाब से बेजोड़ है, जो उपभोक्ताओं को पसंद आएगी. इसमें 12.5 इंच की उच्च गुणवत्तायुक्त डिस्प्ले है, जिससे अच्छी पिक्चर्स देखने को मिलेंगी. इसमें प्रसिद्ध डिज़ाइन फोर्ज का इस्तेमाल किया गया है. कंपनी का मानना है कि यह नोटबुक अच्छा लाभ कमाएगी.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

नए रूप में ऑडी क्यू-5

पिछले तक़रीबन दो सालों के दौरान देश में कार कंपनियों की बिक्री न्यूनतम स्तर पर आ पहुंची है. ऐसे में उनकी पेशानी पर बल पड़ना लाज़िमी है, लेकिन कंपनियां सतर्क हो गई हैं. वे अपने स्तर पर ग्राहकों को लुभाने का हरसंभव प्रयास कर रही हैं. इसी क्रम में लग्जरी कार कंपनी ऑडी इंडिया ने अपनी एसयूवी क्यू-5 का नया वर्जन लांच किया है. इसकी क़ीमत घटाकर 35.13 लाख रुपये कर दी गई है. क्यू-5 के नए वर्जन में 2.0 लीटर इंजन लगा है. यह कार इस साल अक्टूबर से सड़कों पर आ जाएगी. ऑडी इंडिया के हेड माइकल पर्श्क ने कहा, ऑडी क्यू-5 टीडीआई क्यू लग्जरी एसयूवी सेगमेंट में लीडरशिप पोजीशन को मज़बूत करने के लिए अच्छी तरह तैयार है. ऑडी क्यू-5 पहले से ही भारत में काफी लोकप्रिय है. इसकी आकर्षक क़ीमत अब इसे और बड़े ग्राहक आधार तक पहुंचाएगी. क्यू-5 के मौजूदा वर्जन की क़ीमत 39.06 लाख और 45.12 लाख रुपये है. पर्श्क के मुताबिक़, भारत जिस मौक़े को पेश कर रहा है, उसे देखते हुए हमें भरोसा है कि हमारी रीटेल बिक्री 2011 के अंत तक 5,000 कारों पर पहुंच जाएगी.

ट्रांससेंड का यूएसबी टी-3 एस

इसमें विशेष सीओबी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह आपके द्वारा डाले गए डाटा को ज़्यादा सुरक्षित रखता है.

मल्टी मीडिया उत्पादों की प्रमुख कंपनी ट्रांससेंड ने बाज़ार में नया यूएसबी टी-3 एस उतारा है. कंपनी का कहना है कि यह हल्का है और ज़्यादा विश्वसनीय है. इसे विशेष तौर से धूल से सुरक्षित भी बनाया गया है. इसमें विशेष सीओबी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह आपके द्वारा डाले गए डाटा को ज़्यादा सुरक्षित रखता है. टी-3 एस नामक इस ड्राइव को 4 जीबी, 8 जीबी और 16 जीबी की श्रेणी में बाज़ार में उतारा गया है. इसकी लेखन स्पीड 5 एमबीपीएस है, जबकि पढ़ने की 18 एमबीपीएस.

माइरा का सिक्योरिटी मॉनिटर

माइरा ने स्टाइलिश डीवीआर 19 इंच का मॉनिटर लांच किया है. इसमें डिजिटल वीडियो लगाया गया है. एमडीआई-के 9008 नामक इस मॉनिटर को सिक्योरिटी के लिए बनाया गया है. कंपनी का कहना है कि इसमें कई कैमरे लगाए गए हैं, जो हैं तो अलग-अलग, लेकिन एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं. इन्हें अलग-अलग भी इस्तेमाल किया जा सकता है. इसमें फुटेज को बेहतरीन तरीक़े से रिकॉर्ड किया जाता है. इस मॉनिटर में कई ऐसे फंक्शन हैं, जो सुरक्षा के लिहाज़ से बहुत महत्वपूर्ण हैं. इसमें अलार्म, आउटपुट और इनपुट ऑप्शंस के साथ ही मोबाइल सपोर्ट सॉफ्टवेयर भी लगाया गया है.

विज्ञापन हेतु संपर्क करें : email : advt@chauthiduniya.com

बाइचिंग ने 10 से अधिक वर्षों तक भारत की कप्तानी की और लगभग 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 107 मैचों में 42 गोल किए.

बाइचिंग भूटिया

हम तुम्हें भुला नहीं सकते

ए एन शिबली

वर्ष 2007 की बात है. नई दिल्ली के अंबेडकर नगर स्टेडियम में नेहरू कप फुटबॉल टूर्नामेंट खेला जा रहा था. मीडिया बॉक्स में मेरे समीप भारत में फुटबॉल के इन्साइक्लोपीडिया कहलाने वाले नूवी कपाड़िया बैठे थे. चूंकि भारत में फुटबॉल की जानकारी उनसे अधिक किसी को नहीं है और वह दुनिया भर में फुटबॉल के बड़े-बड़े टूर्नामेंटों की कमेंट्री कर चुके हैं. इसलिए मैंने उनसे पूछा, क्या भारत भी कभी विश्वकप फुटबॉल में खेल सकता है? उन्होंने कहा, भाई, यह आने वाले 50 वर्षों में तो संभव नहीं है. भारत अगर बाइचिंग जैसे दो-चार खिलाड़ी पैदा कर दे तो यही उसके लिए बड़ी बात हो जाएगी. कपाड़िया ने कहा कि भारत में जिस तरह फुटबॉल खेली जाती है और इस पर कम ध्यान दिया जाता है, ऐसे में यह संभव ही नहीं है कि भारत विश्वकप में खेले. उन्होंने जो बात कही, उससे भारतीय फुटबॉल में बाइचिंग भूटिया की हैसियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. भारत के अब तक के सबसे मशहूर खिलाड़ी बाइचिंग भूटिया ने पिछले दिनों फुटबॉल से संन्यास लेने का निर्णय कर लिया. भारत में क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों के दो-चार खिलाड़ी ही ऐसे हैं, जिन्हें आम तौर पर भारतीय खेलप्रेमी पहचानते हैं. उनमें से बाइचिंग भूटिया भी एक हैं. वैसे तो भारत में हर कोई क्रिकेट का दीवाना है, लेकिन ऐसे में भी भूटिया जैसे खिलाड़ी को लोग पहचानते हैं तो यह उनका कमाल ही है. अगर आप अचानक किसी से पूछें कि फुटबॉल के किसी एक खिलाड़ी का नाम बताओ तो निश्चित तौर पर वह आपको सबसे पहला नाम भूटिया का ही बताएगा. क्रिकेट में इस सवाल के जवाब में सचिन के अलावा दूसरे खिलाड़ियों के भी नाम आ सकते हैं, लेकिन फुटबॉल में भूटिया के अलावा और किसी का नाम नहीं आ सकता. यह भूटिया के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन का ही कमाल है कि उन्हें लगभग 16 सालों तक भारत की सेवा करने का मौक़ामिला. सिक्किम के एक मामूली गांव में 15 दिसंबर, 1976 को पैदा होने वाले भूटिया ने फुटबॉल में बहुत नाम कमाया. उन्हें फुटबॉल खेलने का शौक़ अपने बड़े भाई को देखकर हुआ, जो क्षेत्रीय स्तर पर फुटबॉल खेलते थे. भूटिया को फुटबॉल के अलावा बैडमिंटन, बॉस्केटबॉल और एथलेटिक्स में भी रुचि थी, लेकिन उन्होंने अपना करियर फुटबॉल में ही बनाया.

भूटिया के माता-पिता नहीं चाहते थे कि उनका बेटा खेलों में रुचि ले, लेकिन भूटिया के चाचा कर्मा भूटिया ने उनका प्रवेश सेंट ज़ेवेरिस स्कूल में करा दिया, जहां केवल 9 वर्ष की आयु में ही भूटिया को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से स्कॉलरशिप मिली. भूटिया पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर सुर्ख़ियों में तब आए, जब उन्होंने 1992 में सुब्रतो कप के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन किया और टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित हुए. सुब्रतो कप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद उन्हें भारत में फुटबॉल के गढ़ कोलकाता में खेलने का अवसर मिला. 1993 में स्कूल छोड़कर भूटिया ने ईस्ट बंगाल क्लब ज्वाइन कर लिया. दो साल बाद वह जेसीटी मिल्स भगवाड़ा में शामिल हो गए और 1996-97 में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन की बदौलत इस क्लब ने इंडिया नेशनल फुटबॉल लीग पर क़ब्ज़ा किया. भूटिया लीग में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने. यहां बेहतरीन खेल पेश करने के बाद उन्हें नेहरू कप में खेलने का मौक़ा मिला और इस तरह उनके इंटरनेशनल करियर की शुरुआत हुई. उज़बेकिस्तान के खिलाफ़ मैच में गोल करके भूटिया सिर्फ़ 19 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल गोल करने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने.

1997 में सैफ चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने मालद्वीप को 5-1 से शिकस्त देकर ख़िताब हासिल किया. इसमें एक गोल भूटिया का भी था. दो साल बाद भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश को शिकस्त देकर ख़िताब का बचाव किया. फाइनल में भारत की ओर से दो गोल हुए, जिनमें एक गोल भूटिया का था. 2002 में भारत ने वियतनाम को हराकर एलजी कप जीता. फाइनल में भारत की ओर से तीन गोल हुए, जिनमें दो गोल भूटिया ने किए. 2009 का नेहरू कप भूटिया के लिए विशेष साबित हुआ, क्योंकि इसी टूर्नामेंट के दौरान उन्होंने भारत की ओर से 100वां मैच खेला और ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय बने. 1996 में उन्हें साल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवॉर्ड मिला. 1997 में फेडरेशन कप में ईस्ट बंगाल की ओर से खेलते हुए उन्होंने मोहन बगान के ख़िलाफ़ तीन गोल किए और वह इस प्रकार के टूर्नामेंट में हैट्रिक करने वाले पहले खिलाड़ी बने. 1999 से 2002 तक उन्हें इंग्लिश डिवीज़न-2 की टीम बर्री के ख़िलाफ़ खेलने का मौक़ा मिला. ऐसा करने वाले वह भारत के पहले खिलाड़ी बने. फुटबॉल की जब भी बात होती है तो सबसे पहले भूटिया का नाम आता है. उनकी अहमियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत के पूर्व कोच बॉब हाटन ने एक बार कहा था कि भूटिया फुटबॉल के सचिन तेंदुलकर हैं. फुटबॉल में बेहतरीन प्रदर्शन करके भूटिया अपना नाम रोशन करते ही रहे, साथ ही वह दूसरे कारणों से भी सुर्ख़ियों में आए. पहली बार 2008 में, जब उन्होंने तिब्बती लोगों पर कथित अत्याचारों के ख़िलाफ़ बीजिंग ओलंपिक की मशाल लेने से इंकार कर दिया था. दूसरी बार भूटिया सुर्ख़ियों में तब आए, जब उन्होंने टेलीविज़न के डांस प्रोग्राम झलक दिखला जा में कोरियोग्राफर सोनिया जाफ़र के साथ हिस्सा लिया. कमाल तो तब हो गया, जब भूटिया विजयी घोषित हुए और ईनाम के रूप में उन्हें 40 लाख रुपये मिले. ईनाम की आधी राशि उन्होंने दान कर दी और आधी राशि अपने और अपनी साथी के बीच बांट ली.

बाइचिंग ने 10 से अधिक वर्षों तक भारत की कप्तानी की और लगभग 16 साल के अंतरराष्ट्रीय करियर में उन्होंने 107 मैचों में 42 गोल किए. वह भारत के एकमात्र और दुनिया के उन गिने-चुने अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्होंने अपने देश के लिए 100 या उससे अधिक मैच खेले. भूटिया के नेतृत्व में भारत ने तीन बार साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप, दो बार 2007 और 2009 में नेहरू कप और 2008 में एएफसी चैलेंज कप जीता. भूटिया को 1998 में अर्जुन अवॉर्ड और 2008 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया. भूटिया को हम मैदान पर नहीं देख पाएंगे, लेकिन फुटबॉल जगत में उनका अमूल्य योगदान लोगों को हमेशा उनकी याद दिलाता रहेगा.

feedback@chauthiduniya.com

1997 में सैफ चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने मालद्धीप को 5-1 से शिकस्त देकर ख़िताब हासिल किया. इसमें एक गोल भूटिया का भी था. दो साल बाद भारत ने एक बार फिर बांग्लादेश को शिकस्त देकर ख़िताब का बचाव किया. फाइनल में भारत की ओर से दो गोल हुए, जिनमें एक गोल भूटिया का था. 2002 में भारत ने वियतनाम को हराकर एलजी कप जीता.

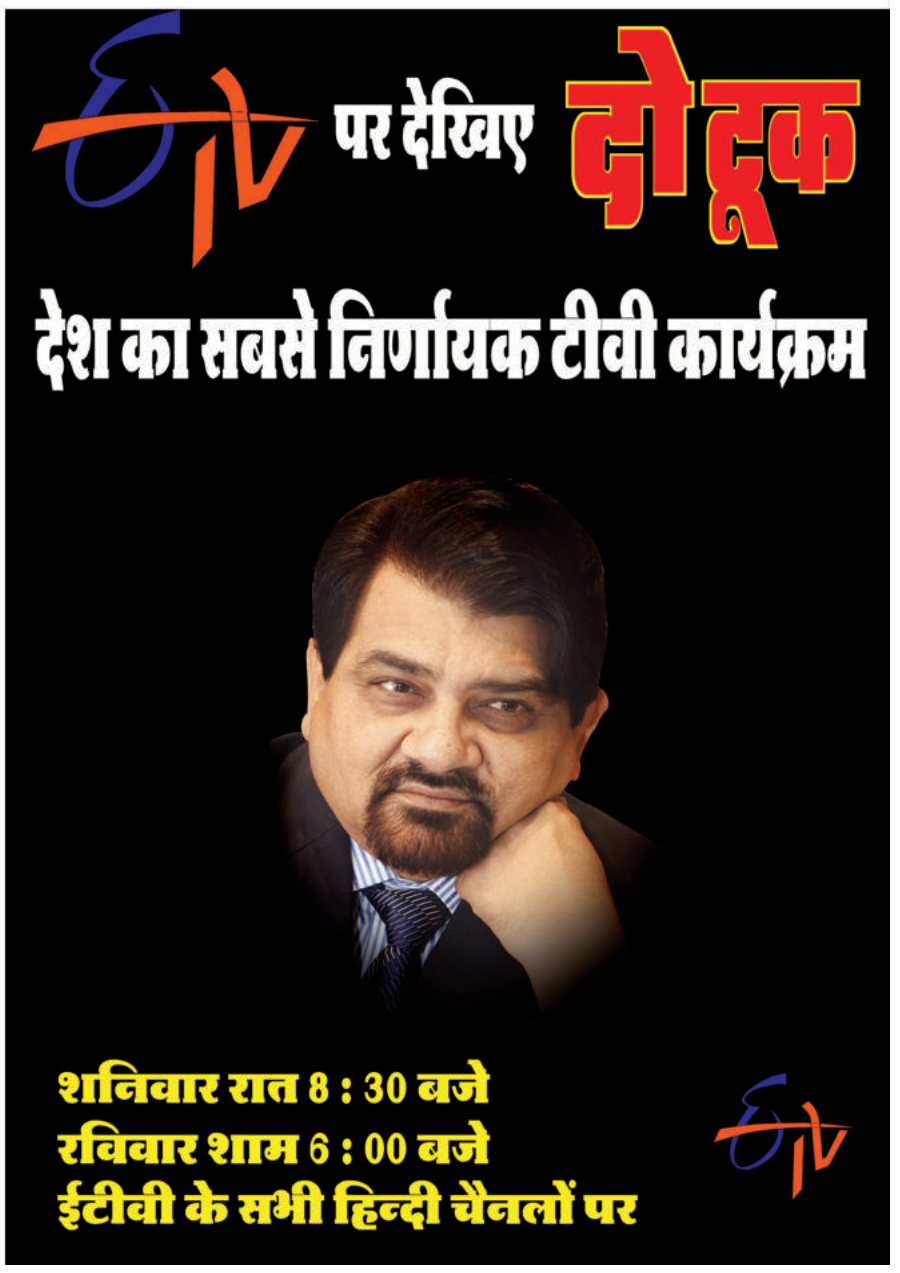

Postal Regn. No. DL/ND-11/6139/2009-11, RNI No. DELHIN/2009/30467

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 सितंबर–18 सितंबर 2011

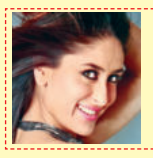

8 करोड़ रुपये की डिमांड करके करीना ने बॉलीवुड में नया रिकॉर्ड बनाया है. अभी तक किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को यह मुक़ाम हासिल नहीं हो पाया है.

करीना की दबंगई

बॉलीवुड के सितारों का पारिश्रमिक आसमान छू रहा है. पहले शाहरुख ख़ान, ऐश्वर्या, सलमान ख़ान एवं आमिर खान आदि का नाम सुनने में आता था, लेकिन अब एक नया नाम और जुड़ गया है करीना कपूर का. आजकल उन्होंने डॉयरेक्टरों के साथ दबंगई दिखानी शुरू कर दी है. उन्होंने सल्लू की राह पर चलते हुए मधुर भंडारकर से उनकी फिल्म हीरोइन में प्रॉफिट शेयर की डिमांड की है और मधुर ने इसके लिए हामी भर दी है. 8 करोड़ रुपये की डिमांड करके करीना ने बॉलीवुड में नया रिकॉर्ड बनाया है. अभी तक किसी बॉलीवुड अभिनेत्री को यह मुक़ाम हासिल नहीं हो पाया है. यह मांग लाज़िमी भी थी, क्योंकि करीना बॉलीवुड की सबसे व्यस्त अभिनेत्रियों में से एक हैं. अभी हाल में उनकी फिल्म बॉडी गार्ड रिलीज हुई है. दीवाली पर किंग खान के अपोजिट उनकी एक और फिल्म रावन रिलीज होगी. इसके अलावा वह सैफ अली ख़ान की फिल्म एजेंट विनोद, एकता कपूर की फिल्म वंस अपॉन ए टाइम मुंबई-2 और आमिर ख़ान के अपोजिट रीमा कागती की फिल्म भी कर रही हैं. बावजूद इसके बेबो ने मधुर के लिए समय निकाला तो इसके बदले में मोटी फीस तो उन्हें लेनी ही थी.

जिसेले का जादू

बॉलीवुड ने कई विदेशी बालाओं को सहारा दिया है. अब बॉलीवुड में करियर की ऊंचाइयों पर पहुंचने की तैयारी मे हैं ब्राजीलियन मॉडल जिसेले मोंटेरियो, जिनकी ख़ूबसूरती सबकी नज़र में आ चुकी है, दीपिका पादुकोण और सैफ अली ख़ान स्टारर फिल्म लव आजकल के छोटे से किरदार हरलीन कौर से. अब यह हसीन बाला प्रोमोडोम फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूसर संदीप कपूर की आने वाली फिल्म प्रणाम वालेकुम में लीड रोल में नज़र आने वाली हैं. जिसेले से पहले इस फिल्म में एक पाकिस्तानी अभिनेत्री को लेने की बात कही जा रही थी, पर अभी हाल में हुए मुंबई बम धमाके के बाद उन्होंने अपना इरादा बदल दिया. इस बारे में प्रोड्यूसर संदीप ने मीडिया में साफ कर दिया है, हालांकि यूनिट के सदस्यों ने यह नहीं बताया कि फिल्म में जिसेले मोंटेरियो किस तरह की भूमिका निभा रही हैं, पर यह तय हो गया कि पाकिस्तानी अभिनेत्री से डील तोड़नी पड़ी. यह फिल्म पाकिस्तान से जुड़ी है, लेकिन इसमें हिंदू-मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है, बल्कि यह एक सिचुएशनल कॉमेडी फिल्म है और इसके डायरेक्टर हैं मशहूर हास्य अभिनेता संजय मिश्रा. पहली बार डायरेक्टर बने संजय ने इस फिल्म के लिए कई फिल्मों के ऑफर ठुकरा दिए. जिसेले मोंटेरियो के अलावा इस फिल्म में विजयराज, मनु ऋषि, शिल्पा शुक्ला, मनोज पावा, संजय मिश्रा एवं असरानी आदि हैं और गेस्ट अपीयरेंस देंगे इरफान ख़ान एवं रजत कपूर. फिल्म प्रणाम वालेकुम के को-प्रोड्यूसर हैं भूषण शर्मा एवं अमित चौहान तथा म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सचिन गुप्ते.

अच्छे दोस्त हैं हृतिक

गणेश हेगड़े और हृतिक डांस में काफी माहिर हैं, यह बात तो सभी जानते हैं, लेकिन यह जानना दिलचस्प है कि हृतिक रोशन गणेश हेगड़े के आने वाले एलबम में डांस करते हुए नज़र आएंगे. गणेश का एलबम जी रिलीज हुआ था 2005 में, अब इस साल वह लेट्स पार्टी नामक एलबम लांच करने जा रहे हैं. गणेश को अपने म्यूज़िक एलबम दीवाना में सबसे पहले इंडियन पॉप एक्ट को प्रोड्यूस करने, संकलन, निर्देशन और ख़ुद उसमें कलाकार के तौर पर काम करने के लिए जाना जाता है. गणेश का मानना है कि पॉप इंडस्ट्री जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है और उसे दोबारा जीवित करने की ज़रूरत है. संगीत के प्रति उनका प्रेम काफी छोटी उम्र में ही नज़र आने लगा था. लगभग पांच सालों के बाद एक नए आइडिया के साथ एक बार फिर केवल ख़ुद के दम पर एलबम लाना आसान नहीं था, लेकिन इसे आसान बनाया उनके दोस्त हृतिक रोशन ने. गणेश ने अपने एलबम के सारे गाने ख़ुद ही लिखे हैं और दो गानों को कोरियोग्राफ भी किया है. गणेश का कहना है कि हृतिक काफी प्रोफेशनल हैं, जब तक वह सही ढंग से परफॉर्मेंस नहीं देते हैं, तब तक रीटेक लेते रहते हैं. जब उन्हें लगता है कि अब परफेक्ट शॉट हुआ, तभी वह उसे फाइनल करते हैं. गणेश के इस म्यूज़िक एलबम में हृतिक के अलावा कैटरीना, बिपाशा और प्रियंका चोपड़ा भी डांस करती हुई नज़र आएंगी. हृतिक अपनी फिल्मों और रियलिटी शो के सिलसिले में काफी व्यस्त रहते हैं. सिर्फ गणेश की दोस्ती की ख़ातिर वह इस एलबम में डांस करने के लिए राज़ी हुए. गणेश उनका शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, यह मेरे लिए गर्व की बात है कि हृतिक ने इस एलबम में काम किया.

फिल्म प्रीव्यू

मौसम

एक एक्टर के रूप में पंकज कपूर कितने बेहतरीन हैं, यह बताने की ज़रूरत नहीं है. जाने भी दो यारों, एक डॉक्टर की मौत, एक रुका हुआ फ़ैसला और धर्म जैसी कई फिल्में इस बात की गवाह हैं. टीवी धारावाहिक करमचंद और ऑफिस-ऑफिस के ज़रिए उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की. मौसम के ज़रिए उन्होंने निर्देशन के क्षेत्र में प्रवेश किया है और उम्मीद की जा रही है कि अभिनेता की तरह वह निर्देशक के रूप में भी दर्शकों को प्रभावित करेंगे. इस फिल्म को बनाने में उन्होंने लंबा समय लिया और खास मौसम का इंतज़ार किया. शाहिद और सोनम में केमिस्ट्री पर्दे पर अच्छी लगे, इसके लिए शूटिंग शुरू होने से पहले उन्होंने दोनों को एक-दूसरे को पत्र लिखने के लिए कहा, ताकि वे अच्छी तरह से एक-दूसरे को जान सकें. फिल्म मौसम बनी है चार सीजन, चार रंगों, उम्र के चारों दौरों और चार ऐतिहासिक घटनाओं को जोड़कर. यह पूरी तरह से रोमांटिक फिल्म है, जिसमें प्रेम की भावना को तीव्रता के साथ पेश किया गया है. पहला सीजन शुरू होता है पंजाब के छोटे से गांव में रहने वाले वाले पंजाबी लड़के हैरी और कश्मीरी लड़की आयत के एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होने से. दोनों अवयस्क हैं. सीजन दो में दोनों के बीच प्यार होता है. जब वे साथ नहीं होते तो उन्हें प्यार की गहराई का एहसास होता है. सीजन तीन और चार में उनका प्रेम चरम पर पहुंचता है, लेकिन इसके पहले दोनों को कई क़ुर्बानियां देनी पड़ती हैं और कई सच्चाइयों से रूबरू होना पड़ता है. हैरी और आयत के प्रेम की पृष्ठभूमि में ज़िंदगी के कई रंग दिखाई पड़ते हैं. इरोज इंटरनेशनल मीडिया लिमिटेड एवं विस्तार रेलीगर फिल्म फंड और सिनर्जी के बैनर तले बनी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है शीतल विनोद तलवार और सुनील ए लुल्ला ने. संगीत दिया है प्रीतम ने. शाहिद एवं सोनम कपूर के अलावा इस फिल्म में आपको अनुपम खेर, अदिति शर्मा एवं सुप्रिया पाठक समेत कई और कलाकार भी दिखाई देंगे.

नए किरदार में ग्रेसी

बॉलीवुड के लेटेस्ट ट्रेंड को देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे ज़्यादातर फिल्में हीरो प्रधान बनती हैं और हीरोइनों को केवल शो पीस के तौर पर रखा जाता है. जबकि पहले हीरोइन के नाम पर फिल्में चला करती थीं, लेकिन निर्माता सुनील कुमार और निर्देशक ललन कुमार ने अल्का पिक्चर्स के बैनर तले हिंदी फीचर फिल्म घोघोरानी-ए मैजिक फ्रेंड बनाने की शुरुआत कर दी है. इस फिल्म में होंगी लगान फेम एक्ट्रेस ग्रेसी सिंह. ग्रेसी इसमें लीड रोल निभा रही हैं और यह महिला प्रधान फिल्म होगी. इसमें हीरो केवल कुछ दृश्यों के लिए ही होंगे या फिर कुछ गानों के लिए. फिल्म की कहानी लिखी है ख़ुद निर्देशक ललन कुमार ने. फिल्म के निर्माता एक बिजनेसमैन हैं और उनका फिल्म बनाने का अनुभव नया है, लेकिन फिर भी उन्होंने अलग तरह के विषय पर फिल्म बनाने का निर्णय लिया और बॉलीवुड की हिट थीम लव स्टोरी को ट्राई नहीं किया. फिल्म घोघोरानी-ए मैजिक फ्रेंड के पांच गाने श्रुति स्टूडियो में रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिन्हें गाया है मशहूर गायक सुदेश भोंसले ने. गीत ललन कुमार और विजय वर्मा ने लिखे हैं, संगीत दिया है किशोर रावत ने और कैमरे पर काम किया है बी एन साहनी ने. फिल्म में ग्रेसी सिंह के अलावा सिकंदर, सोनिका गिल, बाल कलाकार रश्मि पारेख एवं इक़बाल सिंह गज्जान आदि हैं.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

दिल्ली, 12 सितंबर-18 सितंबर 2011

www.chauthiduniya.com

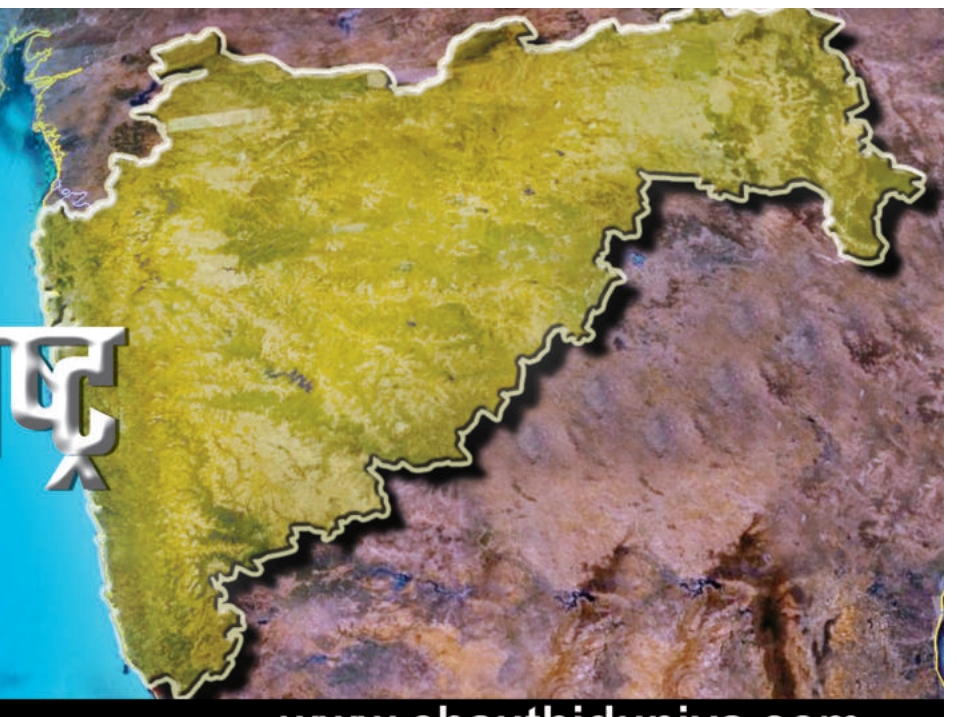

किसानों पर बिजली की मार

प्रवीण महाजन

महाराष्ट्र की स्थापना के बाद से ही विदर्भ क्षेत्र राज्य का एक पिछड़ा हुआ हिस्सा है. दरअसल, यहां के नेताओं की राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी की वजह से यह इलाक़ा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के मुक़ाबले काफी पीछे है. विदर्भ के हालात ही कुछ ऐसे हैं कि यहां हर रोज किसान आत्महत्या करने को विवश हैं.

यहां की खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है. जब बारिश अच्छी होती है, तो फ़सलें और पैदावार अच्छी होती है, लेकिन जब बरसात नहीं होती, तो हालात इस कदर बिगड़ जाते हैं कि किसानों को ख़ुदकुशी के अलावा कोई विकल्प नज़र नहीं आता. विदर्भ के किसानों के समक्ष सिंचाई की समुचित व्यवस्था न होना एक बड़ी समस्या है. बावजूद इसके महाराष्ट्र में किसी सरकार ने विदर्भ के किसानों की इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया, नतीज़तन उनकी हालत बद से बदतर होती जा रही है. मौजूदा समय में विदर्भ के किसानों को सिंचाई के लिए पानी की व्यवस्था कराना बहुत ही ज़रूरी है. विदर्भ में कुछ जल प्रकल्प हैं, इनमें से कुछ छोटे हैं और कुछ बड़े, लेकिन किसानों को कृषि कार्य हेतु जितना पानी चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है. गोसीख़ुर्द, बावनथड़ी, अपर वर्धा, निम्न वर्धा, पैनगंगा, पेंच प्रकल्प और बेंबला जैसे बड़े बांध विदर्भ में ज़रूर हैं, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है. दरअसल, इस समस्या की मूल वजह है विदर्भ क्षेत्र में बनने वाली 65 नई बिजली परियोजना. इसके अलावा विदर्भ में कोराड़ी, खापरखेड़ा, चंद्रपुर, पारस में पहले से ही बड़े थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं और इनकी वजह से बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैल रहा है. दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन बांधों में जो पानी पीने के लिए और सिंचाई करने के लिए संग्रहित हैं, उसी पानी को मनमाने ढंग से इन बिजली परियोजनाओं को दिया जा रहा है. पानी का इस तरह ग़लत इस्तेमाल विदर्भ के किसानों के लिए चिंता का सबब बन गया है. महाराष्ट्र सरकार विदर्भ की ज़मीनी हक़ीक़त जानते हुए भी हर वर्ष ऐसी परियोजनाओं को आंख मूंदकर मंजूरी दे रही है. यह जानते-समझते हुए कि ये सभी प्रोजेक्ट न सिर्फ़ कोयले पर आधारित हैं, बल्कि इन्हें चलाने के लिए 2034.45 एमएम3 पानी की ज़रूरत पड़ेगी. ग़ौरतलब है कि इन थर्मल पावर परियोजनाओं को पानी देने के लिए पांच श्रेणियों में बांटा गया है.

पहली ए श्रेणी में 4 चालू प्रोजेक्ट हैं, जिसकी उत्पादन क्षमता 5448 मेगावॉट है. इस परियोजना को विद्युत उत्पादन के लिए 368 एमएम3 पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि पानी की इतनी ही मात्रा से 3 लाख 40 हज़ार 860 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकती है.

दूसरी बी श्रेणी में 17 परियोजनाओं को मंजूरी मिली है. इसके तहत 1333 मेगावॉट विद्युत का उत्पादन किया जाएगा. इन 17 परियोजनाओं को 469.04 एमएम3 पानी दिया जाएगा, जबकि इस पानी से 4 लाख 34 हज़ार 448 एकड़ कृषि भूमि की सिंचाई की जा सकती है.

तीसरी सी श्रेणी में 10 प्रोजेक्ट हैं. इसके तहत भी 4010 मेगावॉट बिजली का उत्पादन किया जाएगा. इन परियोजनाओं को संचालित करने के लिए 157.10 एमएम3 पानी की आवश्यकता होगी. जितना पानी इसमें ख़र्च होगा, उतने ही पानी से 1 लाख 45 हज़ार 513 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकती है.

चौथी डी श्रेणी में 10 प्रोजेक्टों के लिए सिंचाई परियोजनाओं से पानी की मांग की गई है. इसमें 6436.50 मेगावॉट बिजली उत्पादन की क्षमता होगी. इन प्रकल्पों से बिजली उत्पादन के लिए 240.78 एमएम3 पानी की ज़रूरत पड़ेगी. इन प्रस्तावों को अगर मंजूरी मिल जाती है, तो किसानों के हक़ का पानी छिनना तय है, क्योंकि इस पानी से 2 लाख 23 हजार 22 एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकती है.

पांचवीं ई श्रेणी में 28 प्रोजेक्ट के लिए पानी की मांग की गई है, इन परियोजनाओं से 23605 मेगावॉट बिजली पैदा होगी. इस पावर प्रोजेक्ट को 799.53 एमएम 3 पानी की ज़रूरत पड़ेगी, यदि इन प्रस्तावों को मान लिया जाता है, तो किसानों की बर्बादी तय है, क्योंकि इतने ही पानी से 7 लाख 40 हज़ार 564 एकड़ कृषिभूमि पर सिंचाई की जा सकती है. इन बिजली परियोजनाओं को जितना पानी देना पड़ रहा है और आने वाले दिनों में और देना पड़ेगा, उससे किसानों को दोहरी मार झेलनी पड़ेगी. अगर देखा जाए तो कृषि प्रधान विदर्भ इलाक़े में जिस रफ्तार से विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी जा रही है, इसके पीछे कहीं न कहीं बड़ी-बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का मकसद छुपा हुआ है. वास्तव में विदर्भ में इतनी अधिक संख्या में पावर प्रोजेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन चंद्रपुर, वणी भाग में बड़े पैमाने पर कोयला उपलब्ध होने का कारण बताकर यहां पॉवर प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, यदि समय रहते इस पर लगाम नहीं लगाया गया तो, विदर्भ की कृषि योग्य भूमि का बंजर होना और हज़ारों किसानों का तबाह होना तय है. बिजली परियोजनाओं की वजह से विदर्भ के कई इलाक़ों में पानी का गंभीर संकट भी पैदा हो गया है. किसानों की समस्याएं यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि विदर्भ में जितने भी नए पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उसके निर्माण और ट्रांसमिशन के लिए हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी. ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए किसानों की उपजाऊ ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन कोई भी किसान अपनी मर्ज़ी से ज़मीन देना नहीं चाहेगा, ऐसे में सरकार जबरन ज़मीन अधिग्रहीत करेगी, इसके नतीज़े में हिंसक झड़पें होंगी और कई लोग हताहत होंगे. आने वाले दिनों में इसके काफी बुरे प्रभाव देखने को मिलेंगे. किसान न सिर्फ़ अपनी परंपरागत कृषि कार्य से अलग होंगे, बल्कि उनकी आय का साधन भी छिन जाएगा. मौजूदा समय में राज्य सरकार की भूमि अधिग्रहण नीति पर ग़ौर करें तो, वे पूरी तरह से किसान विरोधी हैं, क्योंकि किसानों से ली जाने वाली ज़मीन के एवज़ में उन्हें काफी कम मुआवज़ा दिया जाता है. इतना ही नहीं, जिन किसानों के खेतों से बिजली की ट्रांसमिशन लाइन गुजरती हैं, वे इसके नीचे की ज़मीन पर फ़सल नहीं ले सकता है. इसके अलावा जहां कोई परियोजनाएं तैयार की जाती हैं, वहां से नई रेल लाइन और सड़क बनाने के लिये भी किसानों की ज़मीन ली जाती है.

बिजली परियोजनाएं प्रदूषण बढ़ाने में भी सहायक हैं. जिसका विपरीत असर खेती पर होता है. इसके अलावा इन पावर प्रोजेक्ट से निकलने वाला धुंआ और राख भी लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है. चंद्रपुर ज़िले में स्थित थर्मल पावर स्टेशन से 2340 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है. अगर पर्यावरण के लिहाज़ से देखें तो यह शहर महाराष्ट्र राज्य के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार है, जबकि देश के प्रदूषित शहरों में चंद्रपुर का दूसरा स्थान है. इतनी भयावह स्थिति के बावजूद भी चंद्रपुर ज़िले में 15,478 मेगावाट उत्पादन क्षमता वाली एक और नई बिजली परियोजना लाने की तैयारी है. कमोबेश ऐसी ही हालत नागपुर ज़िले की भी है. राज्य के अन्य हिस्से जैसे, पश्चिमी महाराष्ट्र, कोंकण, खानदेश की तुलना में विदर्भ में सिंचाई का अनुशेष बहुत ज़्यादा है. इसी वजह से विदर्भ में किसानों की आत्महत्या दर भी ज़्यादा है. वर्ष 2009 में इस बाबत एक रिपोर्ट तैयार की गई थी. इस रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य के अन्य क्षेत्रों की तुलना में विदर्भ का सिंचाई अनुशेष 50 फ़ीसदी से भी ज़्यादा है. ऐसी स्थिति में अगर बांधों का पानी बिजली परियोजनाओं के लिए उपयोग में लाया जाता है, तो सिंचाई के लिए किसानों को पर्याप्त पानी नहीं मिलेगा. ऐसी सूरत में विदर्भ के किसानों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा. विदर्भ में अधिक से अधिक विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का यह कतई मतलब नहीं निकालना चाहिए कि, इससे लोगों को रोज़गार के अधिक अवसर मिलेंगे. बिजली निर्माण का सीधा मतलब है अन्य उद्योगों के लिए रॉ मटेरियल तैयार करना और रोज़गार के अप्रत्यक्ष अवसर पैदा करना. राज्य सरकार विदर्भ की ज़मीन पर सिर्फ़ पावर प्रोजेक्ट खड़ी कर रही है, जबकि राज्य के शेष हिस्से में कई तरह के कल-कारखाने स्थापित कर रही है. महाराष्ट्र के अन्य इलाक़े दिनों-दिन प्रगति कर रहे हैं, जबकि विदर्भ के हिस्से में आता है प्रदूषण, राख, बंजर होती ज़मीन, बीमारियां और किसानों में निराशा.

ग़ौरतलब है कि चंद्रपुर-नागपुर स्थित बिजली परियोजनाओं की नीरी पर्यावरण संशोधन संस्था ने वर्ष 2006 में चल रहे बिजली प्रकल्पों का एक कॉस्ट ऍनलिसिस किया था. इस अध्ययन में प्रकल्पों का पर्यावरण पर क्या असर होता है, इसके अलावा मानव एवं अन्य जीवों पर, सामाजिक-आर्थिक घटकों पर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में गहन विश्लेषण किया गया था.

उल्लेखनीय है कि महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद ने एक क़ानून पारित किया था, ताकि सरकार को महाराष्ट्र वॉटर रिसोर्सेस रेग्युलेटरी अथॉरिटी एक्ट 2005 में संशोधन करने का रास्ता साफ हो. इस क़ानून के तहत थर्मल पावर प्रोजेक्टों के साथ जिन उद्योगों को पानी वितरण का कोटा तय किया गया था, उसके बारे में समीक्षा करने की बात निर्धारित की गई थी. ज्ञात हो कि महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने पिछले 18 मई 2011 को एक प्रस्ताव पारित कर जल नीति में फेरबदल किया था, जिसके तहत पेयजल को पहली प्राथमिकता, सिंचाई के पानी को दूसरा और उद्योगों के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले पानी को तीसरी वरीयता दी गई थी. सरकार की नीयत पर ग़ौर करें तो, शासन ने थर्मल पावर परियोजनाओं के लिए पानी देने का रास्ता साफ़ कर दिया. इसका सीधा मतलब है कि प्रदेश के किसानों को सिंचाई के लिए अब पानी कम मात्रा में उपलब्ध होगा. सरकार की इस किसान विरोधी नीति को देखकर यही कहा जा सकता है कि किसानों के प्रति उनकी मंशा साफ़ नहीं है. ऐसे में यह कहना लाज़िमी है कि किसानों की यह दुर्दशा उस प्रदेश में हो रही है, जहां के दिग्गज नेता शरद पवार केंद्र सरकार में कृषि मंत्री हैं.

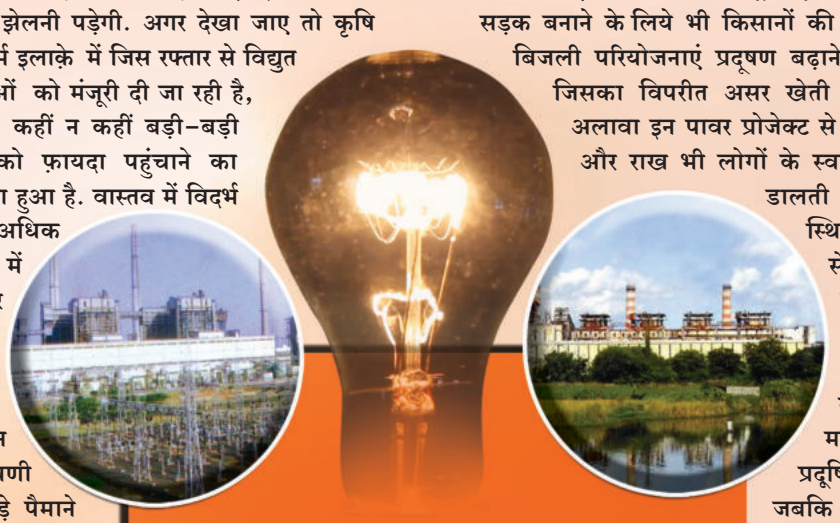

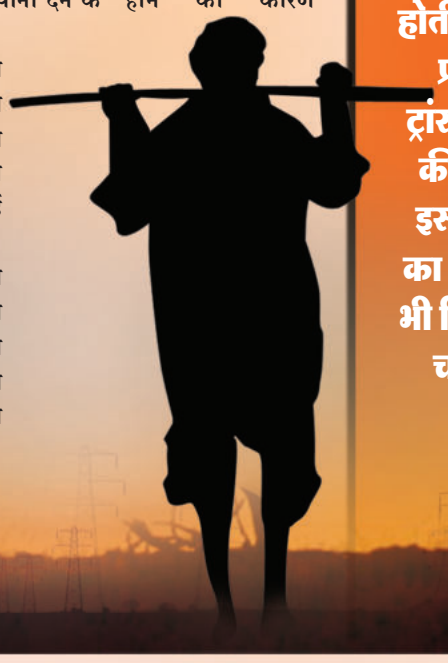

किसानों की समस्याएं यहीं पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि विदर्भ में जितने भी नए पावर प्रोजेक्ट आ रहे हैं, उनके निर्माण और ट्रांसमिशन के लिए हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी. ज़ाहिर सी बात है कि इसके लिए किसानों की उपजाऊ ज़मीनों का अधिग्रहण किया जाएगा, लेकिन कोई भी किसान अपनी मर्ज़ी से ज़मीन देना नहीं चाहेगा, ऐसे में सरकार जबरन ज़मीन अधिग्रहीत करेगी, इसके नतीज़े में हिंसक झड़पें होंगी.

feedback@chauthiduniya.com

हैदराबाद में स्पेशल काउंसलिंग इंजीनियर पद पर नियुक्त हुए. उन्होंने उसी साल मुसी नदी में आई बाढ़ और उससे प्रभावित हैदराबाद वासियों को राहत पहुंचाने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन योजना बनाई.

वर्ष 1881 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की. बी.ए करने के उपरांत उन्हें मैसूर रियासत की ओर से आर्थिक सहायता मिली और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना स्थित साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया.

अभियंताओं से अपेक्षा

सभी अभियंताओं को भी अभियांत्रिकी ज्ञान का उपयोग कर उसे आम जनता की समस्याओं का समाधान करने और उसके जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए. श्री विश्वेश्वरैया ने पूना साइंस कॉलेज से और पूना इंजीनियरिंग कॉलेज से उपाधि हासिल की. बॉम्बे प्रेसीडेंसी में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने सेम्स बर्कली पुरस्कार ग्रहण किया.

शिरीष चक्रदेव

अभियंता दिवस विशेष पर डॉ. एम. विश्वेश्वरैया को अभिवादन करते हैं. अपने जीवन के सौ साल (1861 से 1962) के कालखंड में आपने अभियांत्रिकी ज्ञान का उपयोग कर उसका लाभ आम जनता तक पहुंचाया. आम जनता का जीवन स्तर सुधारने के लिए वह सदा तत्पर रहते थे. इसी प्रकार सभी अभियंताओं को भी अभियांत्रिकी ज्ञान का उपयोग कर उसे आम जनता की समस्याओं का समाधान करने और उसके जीवनस्तर को सुधारने की दिशा में प्रयत्न करना चाहिए. श्री विश्वेश्वरैया ने पूना साइंस कॉलेज से और पूना इंजीनियरिंग कॉलेज से उपाधि हासिल की. बॉम्बे प्रेसीडेंसी में प्रथम स्थान प्राप्त कर उन्होंने सेम्स बर्कली पुरस्कार ग्रहण किया. उस समय प्रथम स्थान आने वाले अभियांत्रिकी के विद्यार्थियों को सहायक अभियंता के पद पर रखा जाता था. उन्हें वर्ष 1884 में बॉम्बे शासन के पीडब्ल्यूडी विभाग में सहायक अभियंता के पद पर रखा गया. वर्ष 1908 में आपने अधीक्षक अभियंता के पद से सेवानिवृति ले ली, क्योंकि उस जमाने में मुख्य अभियंता के पद पर उनका प्रमोशन किया जाना संभव नहीं था. उस समय वह पुणे के सिंचाई विभाग में कार्यकारी अभियंता के पद पर कार्यरत थे, तब उन्होंने नई तकनीक का उपयोग कर ऑटोमेटिक गेट का डिज़ाइन तैयार किया और खड़कवासला तालाब में उस गेट को लगाया गया. इस ऑटोमेटिक गेट से तालाब के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई और बाढ़ में बहने वाले पानी को संग्रहित किया. एक ऐसा ही ऑटोमेटिक गेट ग्वालेर के तिगरा डैम और मैसूर के कृष्णराजसागर बांध में लगाया गया. श्री विश्वेश्वरैया ने इस तरह के गेट का पेटेंट भी कराया था, लेकिन बदले में उन्होंने सरकार से किसी तरह की रॉयल्टी नहीं ली.

उसके बाद अप्रैल 1909 में श्री विश्वेश्वरैया ने हैदराबाद में स्पेशल काउंसलिंग इंजीनियर पद पर नियुक्त हुए. उन्होंने उसी साल मुसी नदी में आई बाढ़ और उससे प्रभावित हैदराबाद वासियों को राहत पहुंचाने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन योजना बनाई. इसी तरह शहर के गंदे पानी को स्वच्छ करने की एक आधुनिक योजना बनाई. नवंबर 1909 में उन्हें मैसूर रियासत की ओर से मुख्य अभियंता बनाया गया. इसी तरह नवंबर 1912 में वह मैसूर राज्य के दीवान बने और दिसंबर 1918 को दीवान के पद से सेवानिवृत हुए. उसके बाद उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर कंसल्टिंग इंजीनियर का कार्य शुरू किया. वर्ष 1922 में हैदराबाद सरकार ने उन्हें ड्रेनेज स्कीम के लिए सलाहकार बनाया. इस ज़िम्मेदारी का उन्होंने बख़ूबी पालन किया. इसके लिए एक कारगर योजना बनाकर नदी पर सुरक्षा बांध बनाया. अपनी एक रिपोर्ट में उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाक़ों में घरों के निर्माण पर रोक लगाने और लोगों का अन्यत्र पुनर्वास कराने की महत्वपूर्ण सलाह देते हुए कहा कि बाढ़ की समस्या से निजात इसी तरह मिल सकता है. बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए उन्होंने मूसी नदी की दो शाखाओं पर बांध बनाने की योजना बनाई. इस तरह बांधो में पानी एकत्रित कर हैदराबाद शहर को बाढ़ से निजात दिलाई. जब वे मैसूर राज्य के दीवान थे, उस समय बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी उन्होंने कई तरह की योजनाएं बनाई थी. उनके दूरदर्शी सोच का ही नतीज़ा था कि शिवसमुद्रन में जलविद्युत परियोजना का निर्माण हुआ. विद्युत और सिंचाई के लिए उन्होंने कावेरी नदी पर बांध बनाने की योजना बनाई, जिसके तहत कृष्णराजसागर डैम का निर्माण हुआ. ग़ौरतलब है कि इसी बांध के नीचे मैसूर के प्रसिद्ध वृंदावन गार्डन को भी विकसित किया गया है. श्री विश्वेश्वरैया को उनके बेहतर अभियांत्रिकी और प्रशासकीय कार्य के लिए भारत सरकार ने 7 सितंबर 1955 को देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के हाथों सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया. वर्ष 1961 में उनके 100 वें जन्मदिन पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वयं बंगलौर आकर उनका आदर-सत्कार किया. पंडित नेहरू ने इस अवसर पर उनके बारे में कहा था– मैं समस्त देशवासियों की तरफ़ से भारत के इस महान सुपुत्र का सम्मान करने के लिए यहां आया हूं. हालांकि, स्वतंत्र भारत में भी अभियंताओं ने देश के विकास में काफ़ी अहम योगदान दिया है. आज देश ने दूरसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है. इसी का परिणाम है कि भारत की आम जनता भी मोबाइल सुविधा का लाभ उठा रही है. उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में भारत की विश्व में अच्छी साख है. नारायण मूर्ति समेत कई अभियंताओं ने बेहतरीन लक्ष्य हासिल करते हुए देश के विकास में सहयोग किया है. देश में औद्योगिक विकास के लिए ऊर्जा ज़रूरी है, लिहाज़ा आण्विक ऊर्जा के क्षेत्र में सरकारी कंपनियों के साथ ही निजी कंपनियां भी ऊर्जा के नए श्रोत विकसित कर रहे हैं. देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है साथ ही अभियांत्रिकी के ज्ञान का उपयोग करके उनसे पैदा होने वाले जोख़िम को कम किया जा सकता है. क्योंकि हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि भविष्य में भारत के परमाणु ऊर्जा संयंत्र रूस और जापान की तरह हादसों की शिकार न बनें. बेशक, देश ने विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्रों में काफी प्रगति की है, लेकिन आज भी कई ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसे पूरा किया जाना बेहद ज़रूरी है. आज़ादी के बाद देशभर में सिंचाई की कई परियोजनाएं बनी हैं, बावजूद इसके महज़ 20 फ़ीसदी कृषि क्षेत्र ही सिंचित है. किसानों की हालत में सुधार लाने के लिए यह ज़रूरी है कि लंबित सिंचाई परियोजनाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए.

जलआपूर्ति की कई योजनाएं तालाबों पर निर्भर है. एक अनुमान के मुताबिक़ 80 फ़ीसदी गांव में अभी भी पीने के लिए स्वच्छ पानी का आभाव है. सरकार को गांवों में जलापूर्ति योजना को पूरी ज़िम्मेदारी के साथ पालन करना चाहिए, क्योंकि सभी को पता है कि लोगों में होने वाली अधिकांश बीमारियां दूषित पानी पीने की वजह से ही होती है. ऐसे में देश के सभी अभियंताओं को जनहित के इस कार्य में विशेष योगदान देना चाहिए. अभियंताओं को चाहिए कि वे अपने काम कम समय और कम ख़र्च में पूरा कर आमजनों को इसका लाभ दिलाएं. अभियंता दिवस के मौक़े पर भारत के सभी अभियंताओं से इसकी अपेक्षा है.

feedback@chauthiduniya.com

इंजीनियर्स डे की हार्दिक शुभेच्छा
डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया की जयंती पर शत-शत नमन

Vidya Engineering Nagpur
P.K. CONSTURCTION
System & Devices Pvt. Ltd. Chandrapur
Shrinivasa Construction Pvt. Ltd. Nagpur
Ashwini Constructions Nagpur
Nitin Waghmare Govt. Contractor Nagpur
Well Wisher
इंजीनियर आर.एम.पुरे
एम. कुमार कंस्ट्रक्शन
एस.बी. चन्ने आलापल्ली
इंजीनियर वाय.एस.कुथे
विशाल कंस्ट्रक्शन, नागपुर
पी.के.फेब्रीकेशन वर्कशॉप, नागपुर
N. MORRIS Nagpur
Anand Constructions Nagpur
SWAYAMBHU Construction Nagpur
इंजीनियर जी.आर.मुंडले
श्रीसाई बालाजी कंस्ट्रक्शन नागपुर
आर. के. पुरी नागपुर
इंजीनियर आर.एस.वरंभे
इंजीनियर एम.के.पिंपळे
शरद गोबाडे कंत्राटदार, ताडगांव
Pragati Constructions Nagpur
P.T. Kolhe Govt. Contractor Nagpur
Shrikant Kapse Govt.Contractors Nagpur
इंजीनियर डि.एस.लाहोटी
इंजीनियर ए.एम.गुलधे
एम.जी. बावणकुळे
इंजीनियर एस.एम.देवाळकर
इंजीनियर एच.एस.इंगोले
सोनाली कंस्ट्रक्शन
S.S. Constructions Nagpur
Chakradeo Constructions Co. Nagpur
S.K.Mehata & Company Govt. Contractor Nagpur
इंजीनियर एम.के.सोमकुंवर
इंजीनियर पी.एन.कठाले
प्रवीण ठाकरे
इंजीनियर एस.आर.गोशेटवार
इंजीनियर टी.एम.निखाडे
प्रशांत अवचटे, कंत्राटदार, ताडगांव

इंजीनियर्स डे

डॉ. एम. विश्वेश्वरैया

अभियांत्रिकी के पितामह

इंजीनियर्स डे या अभियंता दिवस समर्पित है देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले अभियंताओं के नाम पर. इस दिन हम सभी याद करते हैं डॉ. मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को, जिन्हें भारत में अभियांत्रिकी का पितामह भी कहा जाता है. गौरतलब है कि उन्हें सर एम.वी. के नाम से भी संबोधित किया जाता है. डॉ. विश्वेश्वरैया न केवल एक प्रख्यात अभियंता थे, बल्कि महान दूरदर्शी राजनेता और प्रशासक भी थे. वे अपनी मातृभाषा के साथ ही संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर भी समान अधिकार रखते थे. उनका जन्म 15 सितंबर 1860 मैसूर रियासत के कोलार ज़िले (वर्तमान में कर्नाटक) के मुद्देहल्ली गांव में हुआ था. उनके पिता श्रीनिवास शास्त्री संस्कृत के प्रकांड विद्वान और आयुर्वेदिक औषधियों के प्रमुख व्यवसायी भी थे. उनकी मां वेंकाचम्मा बहुत ही धार्मिक प्रवृति की विदुषी महिला थीं. श्री विश्वेश्वरैया ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा चिक्काबल्लापुर में पूरी की. उसके बाद उच्च शिक्षा के लिए वे बंगलौर आ गए. वर्ष 1881 में उन्होंने स्नातक की परीक्षा पास की. बी.ए करने के उपरांत उन्हें मैसूर रियासत की ओर से आर्थिक सहायता मिली और वे इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए पूना स्थित साइंस कॉलेज में प्रवेश लिया. वर्ष 1883 में उन्होंने एलसीई और एफसीई परीक्षा (आज की इंजीनियरिंग की परीक्षा के समकक्ष) में प्रथम स्थान हासिल किया.

इंजीनियरिंग की परीक्षा उतीर्ण करते ही तत्कालीन बंबई सरकार ने डॉ. विश्वेश्वरैया को नौकरी की पेशकश की. तत्पश्चात उन्हें नासिक में सहायक अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया. उनकी अभियांत्रिकी क्षमता का पहला परिचय तब हुआ, जब उन्हें दशहरी धुलिया से 35 मील दूर एक गांव में पांजरा सिफोन के निर्माण का कार्य सौंपा गया. इसमें उन्होंने एक इंजीनियर के रूप में विशेष अनुभव हासिल किया, जो उनके आगे की ज़िंदगी में काफ़ी काम आया. उन्होंने शहर में जलापूर्ति की एक नई और बेहतरीन योजना बनाई, जिसे आधुनिक सिंचाई प्रणाली में ब्लॉक सिस्टम कहा जाता है. इसके अलावा उन्होंने पानी के अनावश्यक बहाव को रोकने के लिए लोहे के ऑटोमेटिक दरवाजों का ईजाद किया. अपने इस अविष्कार का इस्तेमाल उन्होंने खड़कवासला बांध में किया. वे मैसूर के कृष्णराजसागर बांध के वास्तुकार भी थे. मौजूदा समय में यह बांध कर्नाटक के महत्वपूर्ण बांधों में से एक है.

सर एम. विश्वेश्वरैया ने बहुत ही सादा-सरल जीवन व्यतीत किया. वे विशुद्ध शाकाहारी थे और अपना कार्य पूरी लगन, ईमानदारी से करते थे. उनकी कर्तव्यपरायणता से प्रभावित होकर मैसूर रियासत के महाराजा ने उन्हें वर्ष 1912 में दीवान बनने के लिए आमंत्रित किया. इस गौरवमयी पद को स्वीकारने से पहले उन्होंने अपने सभी रिश्तेदारों को रात्रिभोज के लिए आमंत्रित किया. सभी रिश्तेदारों से उन्होंने साफतौर पर कहा कि यह पद वे अपने ऊपर किए गए उपकार के रूप में ग्रहण करेंगे. इस ज़िम्मेदारी को संभालने के बाद अपने पारिवारिक सदस्यों के व्यक्तिगत कार्य से दूर रहेंगे. उन्होंने मैसूर के दीवान के रूप में शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही औद्योगिक विकास पर भी विशेष जोर दिया. मैसूर के दीवान के रूप में उन्होंने चप्पल फैक्ट्री, साबुन फैक्ट्री, धातु फैक्ट्री और क्रोम ट्रेनिंग फैक्ट्री की शुरूआत की. इसके अलावा उन्होंने राज्य में कई कल-कारखानों की स्थापना में भी अहम भूमिका निभाई. उन्हीं के अथक प्रयास से भद्रावती में आयरन और स्टील फैक्ट्री का निर्माण हुआ. वर्ष 1918 में उन्होंने मैसूर रियासत के दीवान पद से अपनी इच्छा से सेवानिवृति ली.

मैसूर के दीवान पद से मुक्त होने के बाद वे फिर से अपने काम में सक्रिय हो गए. उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग का कार्य शुरू किया. इस तरह उन्होंने अपनी अभियांत्रिकी क्षमता का लोहा विश्व स्तर पर भी मनवाया. देश के विकास में किए गए उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए वर्ष 1955 में उन्हें सर्वोच्च सम्मान भारतरत्न से सम्मानित किया गया. उनके सम्मान में विश्वस्तरीय तकनीकी संस्थान की स्थापना की गई, जिसका नामकरण भी उन्हीं के नाम पर किया गया. वर्तमान समय में डॉ. एम.वी. विश्वेश्वरैया तकनीकी संस्थान देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जहां उनके विचार मूर्त रूप लेते हैं आज के होनहार और मेहनती अभियंताओं के रूप में. उनके जीवन के सौ वर्ष पूरे होने पर भारत सरकार ने उनके नाम पर एक डाक टिकट भी जारी किया था. 101 वर्ष की आयु में भारत के इस सपूत का देहावसान 14 अप्रैल 1962 को हो गया.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

सम्मान व पुरस्कार

- 1904: 50 साल की अखंडित अवधि के लिए सिविल इंजीनियर्स के लंदन इंस्टीट्यूशन की मानद सदस्यता से सम्मानित
- 1906: कैसर हिंद सम्मान
- 1911: दिल्ली दरबार में केसीआईई (भारतीय साम्राज्य के कम्पेनियन)
- 1921: डी.एस.सी- कलकत्ता विश्वविद्यालय
- 1931: एलएलडी- बंबई विश्वविद्यालय
- 1937: डी. लिट.- बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
- 1943: इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के एक मानद सदस्य (भारत) के रूप में निर्वाचित
- 1944: डी.एस.सी- इलाहाबाद विश्वविद्यालय
- 1948: डाक्टरेट-एलएलडी, मैसूर विश्वविद्यालय
- 1953: डी. लिट- आंध्र विश्वविद्यालय
- 1953: टाउन योजनाकारों संस्थान, भारत के मानद फेलोशिप से सम्मानित
- 1955: भारत के सर्वोच्च सम्मान भारतरत्न से सम्मानित
- 1958: बंगाल की रॉयल एशियाटिक सोसायटी परिषद द्वारा दुर्गा प्रसाद खेतान मेमोरियल गोल्ड मेडल से सम्मानित
- 1959: भारतीय विज्ञान संस्थान, बंगलौर फेलोशिप

यह सभी सम्मान राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय स्तर के हैं, इसके अलावा सर एम.वी. को अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया था.

एक समारोह के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सर एम.वी. से बात करते हुए.

बाल अवस्था में सर एम.वी.

युवावस्था में सर एम.वी.

सर एम.वी. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलौर का दौरा करते हुए.

वर्ष 1946 में कनाडा के टोरंटो शहर में सर एम.वी. एआईएमओ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए.

1950 में बंगलौर स्थित हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्ट्री का निरीक्षण करते हुए सर एम.वी.

सर एम.वी. की अभियांत्रिकी की अद्भुत क्षमता का प्रतीक मैसूर के पास बना कृष्णराजसागर बांध.

1955 में राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद से भारतरत्न सम्मान ग्रहण करते हुए सर एम.वी.

1947 में एएमआईओ के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते सर एम.वी.

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के प्रेसीडेंट सर एम.वी उद्योगपति जे.आर.डी. टाटा और वैज्ञानिक एच.जे भाभा के साथ.

कलकत्ता में हिन्दुस्तान मोटर निर्मित इंजन का निरीक्षण करते हुए सर एम.वी. साथ में बी.एम. बिरला

दिल्ली में सर एम.वी. भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और सी. राजगोपालाचारी के साथ.

वह घर जहां सर एम.वी. का जन्म हुआ.

सर एम.वी. को 92वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं देते हुए उनके गुरू जयचंदराजा वाडियार.

1935 में यूएसए के डेट ट्राइट क्लब में सर एम.वी. मिस्टर फ्रैंक एफ. बेल के साथ.

सर एम.वी. की मां श्रीमती वेंकचाम्मा.

Postal Regn. No. RNP/NP/CITY/383/2011-13, RNI No. DELHIN/2009/30467

जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत केंद्र. सरकार की ओर से जो स्टार बस नगर निगम को मिली थीं, उनकी भी हालत साल दो साल में ही ख़राब हो चुकी हैं.

घर बचा लो नितिन जी

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

राजेश नामदेव

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर मुझे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नियुक्त नहीं किया हैं और न ही पार्टी के काम में संघ की कोई दखलअंदाज़ी होती है. ऐसा नितिन गडकरी बार–बार दोहराते रहते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि आरएसएस ने राजधानी दिल्ली स्थित चौकड़ी को बाजू में रखकर नितिन गडकरी का नेतृत्व भाजपा पर थोपा है. इसीलिए गडकरी पहले दिन से ही अपनी क्षमता साबित करने के लिए जूझते दिखाई देते हैं. भाजपाध्यक्ष बने गडकरी को क़रीब पौने दो साल हो रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी पर उनकी पूरी तरह पकड़ दिखाई नहीं देती. जिन्हें गडकरी का नेतृत्व पसंद नहीं था, ऐसे तमाम नेता उनसे दूरी बना रहे हैं. इतना ज़रूर है कि ऐसे भाजपा नेता गडकरी के साथ होने का दिखावा भी कर रहे हैं. भाजपा प्रमुख होने के नाते गडकरी पार्टी की कमान मज़बूती से कसना चाहते हैं, लेकिन सभी को पता है कि पार्टी में सभी अहम फ़ैसले लालकृष्ण आडवाणी ही करते हैं. इस हक़ीकत को नकारा नहीं जा सकता. आरएसएस द्वारा नितिन गडकरी को भाजपाध्यक्ष बनाए जाने से दिल्ली में भी कई दिग्गज भाजपाई नाराज़ है तो दूसरी तरफ़ महाराष्ट्र में पार्टी के वरिष्ठ ओबीसी नेता गोपीनाथ मुंडे भी गडकरी से खार खाए हुए हैं. ऐसे में पार्टी को मज़बूत करने में गडकरी को कितनी कामयाबी मिलेगी इसे लेकर भाजपा में संशय की स्थिति बनी हुई है. जिन नेताओं को नितिन गडकरी का नेतृत्व रास नहीं आ रहा है, ऐसे नेता उनकी राह में कांटे बिछाने की कोशिशों में लगे हुए हैं. बतौर भाजपाध्यक्ष नितिन गडकरी 19 दिसंबर को अपने दो साल पूरे करेंगे. गडकरी की अगुवाई में असम, बिहार, पं.बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए. इन चुनावों में सिर्फ़ एक राज्य बिहार में भाजपा को जबरदस्त कामयाबी मिली. बाक़ी चार प्रदेशों में भाजपा का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है. बिहार में मिली सफलता का मुख्य कारण यह था कि वहां की जनता विकास चाहती थी और लालू यादव के विकल्प के रूप में नीतीश से अच्छा और कोई विकल्प उसके सामने नहीं था. मतलब वहां मिली सफलता जनता दल (यू)–भाजपा गठबंधन की संयुक्त रूप से है. वर्तमान में उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव परिणाम पर ही गडकरी का भविष्य निश्चित है कि वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे कि नहीं. उत्तर प्रदेश में भी वहां की जनता मायावती का विकल्प खोज रही है. ऐसे में समाजवादी पार्टी के सामने भाजपा कितनी टिकेगी यह अहम सवाल बना हुआ है. ऐसे में गडकरी का पूरा ध्यान उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव पर ही लगा हुआ है. यही वजह है कि भाजपा नेताओं के विरोध के बावजूद भी संजय जोशी और उमा भारती की पार्टी में दोबारा वापसी की गई है और इन दोनों नेताओं को यूपी का दायित्व सौंपा गया है. बहरहाल भाजपा को यहां कामयाबी मिल भी जाती है तो उसका सारा श्रेय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता को ही जाएगा, क्योंकि वहां की जनता आज भी वाजपेयी को ही सर्वोपरि मानती है. इसे भांपते हुए गडकरी वाजपेयी की जन लोकप्रियता भुनाने की कोशिशों में जुटे हैं. ऐसे में सवाल उठता है कि मिशन यूपी में मशगूल गडकरी के गृहनगर में क्या होगा, जहां अगले वर्ष के प्रारंभ में महानगर पालिका और ज़िला परिषद के चुनाव होने हैं. अगले साल यूपी में चुनाव के बाद भी उनकी मुश्किलें कम नहीं होगी, क्योंकि उनके गृहनगर में ही भाजपा गुटबाज़ी का शिकार हो गई है. ऐसे में चुनाव से पहले अगर पार्टी के अंदर खींचतान ख़त्म नहीं हुई तो भाजपा का बेड़ागर्क होना तय है. पिछले चुनाव में यहां भारतीय जनता पार्टी को कामयाबी मिली थी, लेकिन इस बार चुनाव में भाजपा और नितिन गडकरी के सामने एक चुनौती खड़ी होने वाली है. वैसे पिछली बार की तुलना में यहां सियासी समीकरणों में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है. मसलन, नागपुर महानगर पालिका और नागपुर ज़िला परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत न हो, इसकी पूरी तैयारी ख़ुद पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं ने ही कर रखी है. इन चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी की हार होती हैं तो वह गडकरी की हार मानी जाएगी. ख़ासकर उन लोगों को इसी के बहाने एक मौक़ा मिल सकता है, जिन्हें गडकरी का नेतृत्व मान्य नहीं है. महाराष्ट्र में नाराज़ चल रहे पार्टी के कद्दावर ओबीसी नेता गोपीनाथ मुंडे से लेकर सुषमा स्वराज जैसे असंतुष्ट नेता गडकरी को केंद्र की राजनीति से बाहर करने की कवायद में जुटे हुए हैं. इस हक़ीक़त को खारिज नहीं जा सकता है. ऐसे में महानगर पालिका और ज़िला परिषद का चुनाव जीतना गडकरी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. पांच साल पहले नागपुर महानगर पालिका के चुनाव में जीत हासिल कर भाजपा ने कमान संभाली थी, तब भाजपाध्यक्ष नितिन गडकरी ने जनता से कई वायदे किए थे. उन्होंने नागपुर की जनता को 24 घंटे शुद्ध जल उपलब्ध कराने, नागपुर को कचरा मुक्त शहर बनाने, नक्षत्र गार्डन, ऑटोगैस किट और सभी रास्तों पर स्ट्रीट लाइट लगाने की बात कही थी. इतना ही नहीं नितिन गडकरी ने नागपुर को लंदन बनाने का सब्ज़बाग भी दिखाया था. हालांकि, कई लोग यह भी मानते हैं कि गडकरी का विजन बेहतर है, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई योजनाओं को पूरा करने में उनकी पार्टी के पदाधिकारी, निगम के पार्षद, महापौर और समितियों के अध्यक्ष पूरी तरह नाकाम रहे हैं. नागपुर की सड़कें इस कदर जर्जर हो चुकी हैं कि कई जगहों पर गड्ढों में से सड़क खोजनी पड़ती है. इसके अलावा सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइटों में आधे से ज़्यादा ख़राब हैं. नगर निगम की ओर से चलाई जा रही बसों की हालत भी खस्ता है. इन बसों को चलाने का ज़िम्मा वंश निमय लिमिटेड को सौंपा गया है.जेएनएनयूआरएम के अंतर्गत केंद्र सरकार की ओर से जो स्टार बस नगर निगम को मिली थीं, उनकी भी हालत साल–दो सालों में ही ख़राब हो चुकी हैं. कंपनी की मनमानी से नागरिकों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं.

नितिन गडकरी के भाजपा अध्यक्ष बनते ही महाराष्ट्र भाजपा में असंतोष भी बढ़ गया. राज्य विधान परिषद में विपक्ष के नेता पांडुरंग फुंडकर और गोपीनाथ मुंडे गडकरी नेतृत्व के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी जता चुके हैं. इतना ही नहीं गडकरी ने जिन बसपा के नेताओं को भाजपा में लाया था उनमें से कई लोग बीजेपी को अलविदा कहना शुरू कर दिया है. सूत्रों की मानें तो मुंडे गुट बसपा नेताओं को पार्टी से अलग कर बीजेपी को खोखला बनाने की कवायद में जुटा है. अगर समय रहते इसे रोका नहीं गया तो यह गडकरी और महाराष्ट्र भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है.

feedback@chauthiduniya.com

जिन नेताओं को नितिन गडकरी का नेतृत्व रास नहीं आ रहा है, ऐसे नेता उनकी राह में कांटे बिछाने की कोशिशों में लगे हुए हैं. बतौर भाजपाध्यक्ष नितिन गडकरी 19 दिसंबर को अपने दो साल पूरे करेंगे.

चुनावी बजट

नागपुर महानगर पालिका में भाजपा की ओर से पेश 2011-12 का बजट उनके कार्यकाल का अंतिम बजट था. भाजपा ने 1187 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया. वैसे मनपा की आय 50 से 55 करोड़ रुपये के बीच है. उम्मीद की जा रही है कि इससे हर वर्ष 600 से 650 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा. इसमें 50 करोड़ रुपये जेएनएनयू आरएम योजना के तहत केंद्र सरकार से मिलेंगे, जबकि इसी योजना के लिए 50 करोड़ रुपये का क़र्ज़ अलग से मिलेगा. इस तरह क़रीब 750 करोड़ रुपये मिलते हैं तो शेष 437 करोड़ रुपये का इंतज़ाम कैसे होगा? हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कहीं न कहीं इस बजट के पीछे चुनावी मक़सद छुपा हो.

ग़रीबों का पैसा मनोरंजन के लिए

नागपुर में स्ट्रीटलाइट, सड़क , पानी शहर को गंदगी मुक्त और ड्रेनेज की साफ-सफाई जैसी मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने के बजाय महानगर पालिका ने नागपुर महोत्सव, नागपुर गौरव सहित 9 सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए वर्ष 2007 से लेकर 31 मई 2011 तक क़रीब 3 करोड़ 15 लाख रुपये रेवड़ी की तरह बांटे. इतना ही नहीं मनपा के पास इससे जुड़े अन्य कई ख़र्चों का भी कोई हिसाब-किताब नहीं है. मनपा में इन दिनों लापरवाही और मनमानी का दौर चल रहा है. शाही ख़र्च पर लगाम लगाने की बजाय सत्तापक्ष राजस्व बढ़ाने की बात कह रही है. ऐसे में सवाल यह है कि आय बढ़ाने के लिए कहीं मनपा आम जनता पर करों का अतिरिक्त बोझ तो नहीं लाद देगी. मनपा प्रशासन ने अप्रैल 2008 में संपत्ति कर और अप्रैल 2009 में पानी कर में वृद्धि की थी. इसके अलावा जकात कर, विज्ञापन कर, लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की थी.

अन्ना, यह कैसी विडंबना !

भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ जनांदोलन खड़ा करने के लिए अन्ना को सलाम, किरन बेदी को सलाम, अरविंद केजरीवाल को सलाम. सलाम उन सभी को, जिन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया. अन्ना के आंदोलन में गलाफाड़–फाड़ कर नारे लगाए, वंदेमातरम का उद्घोष किया, तिरंगा लहराया सरकार को हिलाया– जगाया, उसकी नींद हराम कर दी. बढ़ते जनाक्रोश से सरकार घबराई, सांसदों के घर–घर जाकर उनकी भी मदहोशी में खलल डाला. उनकी खुमारी को तोड़ा. बढ़ते जनदबाव के कारण सरकार चहुंओर से हिलने लगी, उसे अहसास हुआ कि अन्ना के अनशन के आगे तो सारी राजनीतिक, कूटनीतिक होशियारी धरी की धरी रह गई. पता नहीं अन्ना क्या खाकर अनशन पर बैठे थे कि उनका आत्मबल टूट ही नहीं रहा था. दरअसल यह पूरा हठयोग पुराने जमाने के योगी जैसा था, जिसके तप से इन्द्र का सिंहासन डोल उठता था. आंदोलन की शुरुआत में सरकार का सारा जोर अन्ना के आंदोलन को विफल करने पर था. इसलिए मनमोहनी सरकार अपने प्यादों को उसी तरह आगे कर अन्ना के अनशन को तोड़ने का प्रयास कर रही थी. जैसे इन्द्र ऋषियों–योगियों की समाधि तोड़ने के लिए कभी रंभा, कभी मेनका जैसी अप्सराओं को भेजता था, पर अन्ना के हठयोग के आगे सरकार की तमाम चालें विफल हो गईं.

सरकार ने आम आदमी की भावना को समझने का कभी प्रयास ही नहीं किया. उसके दुख–दर्द को सुनने की कभी कोशिश नहीं की. उसकी समस्याओं का समुचित समाधान करने पर विचार नहीं किया. एयरकंडीशनर कमरे में बैठने, एसी कारों में चलने वाले मंत्रियों–नौकरशाहों को नहीं पता कि आम आदमी को उनके प्रशासनिक मकड़जाल में फंस कर किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह से रक्तपिपासु हो गया है और आम आदमी को निचोड़ डालना चाहता है. दरअसल, प्रशासन को आंदोलन कुचलने, ग़रीबों पर लाठी भंजवाने, गोलियां बरसाने की आदत पड़ चुकी है. अन्ना ने इस बात को परखा और भ्रष्ट–हत्यारे तंत्र के ख़िलाफ़ अनशन की घोषणा की और लोगों से आंदोलन में शामिल होने का आह्वान किया. देश की लाखों जनता अन्ना की इस अपील पर सड़कों पर उतर आई. इस जनाक्रोश के लिए पूरी तरह सरकार ही ज़िम्मेदार थी, क्योंकि अगर सरकार ने लोगों की समस्याओं पर ध्यान दिया होता तो इस आंदोलन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. सत्ता के मद में चूर हुकूमत ने सपने में भी नहीं सोचा था कि अन्ना का आंदोलन इतना व्यापक होगा. उसे लगा कि जिस तरह रामदेव को रामलीला मैदान से खदेड़ दिया था, उसी तरह अन्ना को भी खदेड़ देंगे, लेकिन जब सत्ता की तमाम चालें उलटी पड़ गईं, तो लगा मामला बिगड़ जाएगा. तक अन्ना के लिए महाराष्ट्र सूबे के पूर्व मुखिया विलासराव देशमुख को सरकार ने अपना शांतिदूत बनाकर अन्ना के पास भेजा. बात धीरे–धीरे बनने लगी. अन्ना की बात मान कर सरकार ने अन्ना के जनलोकपाल बिल का मसौदा पेश किया. सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने इस मसले पर ख़ूब भड़ास निकाली. संसद भवन में कई राजनेताओं ने उन्हें चेतावनी दी, तो कईयों ने उन्हें सलाम ठोंका. किसी ने उनको महान बनाया तो कई नेताओं ने उनके मसौदे में मीन–मेख निकाला. उसके बाद आख़िरकार अन्ना ने अनशन ख़त्म करने की घोषणा कर दी. यहां तक सब ठीक था, लेकिन आगे जो वाकया हुआ वह कुछ अटपटा था. मन में सवाल उठ रहा था कि अन्ना ने ऐसा क्यों किया? अन्ना यह क्या हो रहा था? आपने यह आंदोलन भ्रष्टाचार के ख़िलाफ़ छेड़ा था. भ्रष्टाचारियों की मनमानी रोकने के लिए आपने मुहिम चलाई थी, लेकिन इस अनशन को आपने एक भ्रष्ट मंत्री के मान–मनोव्वल के बाद तोड़ा. विलासराव देशमुख आदर्श सोसायटी घोटाले में घिरे हैं. मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करने पर सुप्रीम कोर्ट ने उन पर 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था. ऐसे में उन्हें भी सलाम.

चौथी दुनिया ब्यूरो
feedback@chauthiduniya.com

चौथी दुनिया

बिहार झारखंड

दिल्ली, 12 सितंबर–18 सितंबर 2011

www.chauthiduniya.com

CYBOTECH CAMPUS

ADMISSIONS OPEN

2nd Floor, Varma Centre, Boring Road Crossing, Patna-1 E-mail: info.courses@cybotechcampus.com • www.cybotechcampus.com

BCA BBA BSc-IT MCA MBA MSc-IT BA MA B.Com. M.Com.

An ISO 9001:2008 Certified Institution SQC ISO 9001:2008

Transport Facility

SMS CYBOTECH <space> YOUR NAME to 56677

FOR ADMISSION CALL 0612 2541398 0612 2541498 0 9708581801

- QUALITY EDUCATION
- RECOGNISED DEGREES & DIPLOMAS
- AFFORDABLE COST

'CYBOTECH CAMPUS' is a registered trademark of ACRIPL • We have no branch outside Patna

पासवान ने खोला पत्ता

रामविलास पासवान ने सीएम बनने की इच्छा जताकर अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. देर से ही सही, लेकिन पहली बार बिहार के लिए उन्होंने सही पत्ते खोले हैं. यह इसलिए भी कि नीतीश कुमार के बढ़ते क़द को क़ाबू में रखने के लिए उन्हीं के क़द का विकल्प सामने होना ज़रूरी था.

फोटो–*प्रभात पाण्डेय*

सरोज सिंह

आख़िरकार बात ज़ुबां पर आ ही गई. लोजपा प्रमुख रामविलास पासवान पटना के कुछ दलित बस्तियों में गए थे. वहां के हालात देख वह इतने दुखी हुए कि उन्होंने कहा कि अगर बिहार की जनता मुझे मुख्यमंत्री बनाती है तो मैं इन बस्तियों में पक्का मकान बनवा दूंगा. पासवान की ज़ुबां से ये अल्फाज़ क्या निकले, राजनीतिक गलियारों में सनसनी फैल गई. लोजपा के कार्यकर्ता तो उछल पड़े जबकि दूसरे दलों के नेताओं ने गुणा–भाग लगाना शुरू कर दिया. भाजपा व जदयू के नेताओं ने तीर चलाने शुरू कर दिए. मुख्यमंत्री पद के लिए अपने आप को सबसे उपयुक्त मानने वाले नेताओं में भी खुसुर–फुसुर शुरू हो गई. लेकिन इन सबके बीच राजनीतिक विश्लेषकों ने एक सुर में कहा कि रामविलास पासवान ने सीएम बनने की इच्छा जताकर अपना सबसे बड़ा दांव खेल दिया है. देर से ही सही लेकिन पहली बार बिहार के लिए उन्होंने सही पत्ते खोले हैं.

ऐसा इसलिए भी ज़रूरी था कि नीतीश कुमार के बढ़ते क़द को क़ाबू में रखने के लिए उन्हीं के क़द का विकल्प सामने होना ज़रूरी था.

आइए इस कहानी के कुछ पुराने पन्ने पलटते हैं. बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में भी यह अटकलें लगाई जा रही थीं कि रामविलास ख़ुद को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करेंगे. दिग्विजय सिंह के निधन के बाद नीतीश विरोध का जनमानस पासवान को बेहतर विकल्प के तौर पर देख रहा था. लेकिन राज्यसभा भेजने के अहसान तले दबे रामविलास उस समय एक बड़ी राजनीतिक चूक कर गए. लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार मान लिया और अपने भाई पशुपति पारस को उप मुख्यमंत्री के तौर पर पेश कर दिया. जनता के बीच इस ग़लत राजनीतिक फ़ैसले की इतनी कड़ी प्रतिक्रिया हुई कि राजद लोजपा गठबंधन का सूपड़ा ही साफ़ हो गया और एनडीए ने भारी जीत दर्ज की. वजह साफ़ थी, उस समय जनता के सामने विकल्पहीनता की स्थिति थी. लालू प्रसाद को जनता सीएम के तौर पर नहीं चाहती थी, उसे पासवान में बिहार के वास्तविक विकास की चाबी दिख रही थी. पर एक ग़लत फ़ैसले ने सब कुछ चौपट कर दिया. लेकिन लोजपा कार्यालय में जो इफ्तार पार्टी हुई, उसे देखकर लगा कि पासवान अपनी ग़लतियों से सीख रहे हैं और काफ़ी क़ायदे से अपना होमवर्क कर रहे हैं. इस पार्टी में विपक्ष की राजनीति करने वाले तमाम चेहरे नज़र आए. पासवान के घर पर जुटी यह जमात ही फ़िलहाल नीतीश का विकल्प देने की ताक़त रखती है. लेकिन इस ताक़त को सही क्रम में पिरोने की कलाकारी पासवान को करनी है. लालू प्रसाद, उपेंद्र कुशवाहा, सदानंद सिंह, प्रभुनाथ सिंह, अखिलेश सिंह, ददन यादव के अलावा ढेर सारे ऐसे चेहरे पार्टी में एक दूसरे से कुछ कहना चाह रहे थे, पर इफ्तार की मर्यादा से बंधे होने के कारण दिल की बात ज़ुबां पर न आ सकी. लेकिन इन सारे नेताओं का एक साथ जुटना ही यह बताता है कि नीतीश का विकल्प देने की बैचेनी बढ़ गई है और एक व्यवहारिक समीकरण बनाने का काम जल्द से जल्द शुरू होने का सबको इंतजार है. ऐसा समीकरण, जिसमें सभी नेताओं का सम्मान बरक़रार रहे और जो जनता की भावनाओं के क़रीब हो. पासवान के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि वह सभी जाति, वर्ग व समुदाय के लोगों में लोकप्रिय हैं. इनकी छवि एक काम करने वाले नेता की रही है. केंद्र में इनको जब भी मंत्री बनने का मौक़ा मिला, इन्होंने बिहार के लिए बहुत कुछ किया. दलितों के वह मसीहा तो हैं ही, पिछड़े व उच्च जातियों के लोग भी इन्हें हाथों हाथ लेते हैं. बिहार के चारों कोनों में इनकी लोकप्रियता एक तरह है. फारबिसगंज गोलीकांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए इन्होंने जो ज़ोरदार पहल की, उससे अल्पसंख्यकों के बीच इनकी इमेज एक बार फिर पहले की तरह चमकी है. लोजपा के प्रधान महासचिव राघवेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि रामविलास पासवान तो प्रदेश की जनता की स्वाभाविक पसंद हैं. वह जिस दिन मैदान में कूदेंगे सामने वाले धाराशायी हो जाएंगे. काफी समय से कार्यकर्ताओं व प्रदेश की जनता का दबाव उनपर था. इसलिए अगर पासवान बिहार में रहकर प्रदेश की जनता की सेवा का मन बनाते हैं तो यह शुभ संकेत है. जानकार बताते हैं कि पासवान ने अनायास ही मुख्यमंत्री बनने की बात नहीं कह डाली है. कांग्रेस चाहती है कि बिहार में नीतीश का मुक़ाबला करने के लिए पासवान को ही आगे किया जाए. लालू प्रसाद का क्या हश्र हुआ, वह कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव में देख चुकी है. मौटे तौर पर तय हुआ है कि राजद का भी साथ लिया जाएगा, पर नेता के तौर पर पासवान को ही आगे किया जाएगा ताकि जनता में भरोसा जगाया जा सके. राजद अगर इसके लिए तैयार नहीं होता है तो उसको अलविदा भी कहा जा सकता है. ऐसे में राजद के विक्षुब्ध नेताओं को तवज्जो देकर जोड़ने की रणनीति भी बनाई जा रही है. किसान महापंचायत में दिग्विजय सिंह से जुड़े लोगों को भी साथ लेने का प्रयास चल रहा है. कोशिश यह हो रही है कि वामदलों को भी इस अभियान में जोड़ा जाए. पासवान के वामनेताओं से रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हैं. रणनीति के तहत अभी सभी दल व नेता अपने–अपने पार्टी बैनर के तले अपने कार्यक्रम चलाते रहेंगे. लेकिन आंतरिक तौर पर उनके बीच तालमेल बना रहेगा. जनता से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा तथा नीतीश सरकार की कमियों को हर मंच पर उजागर किया जाएगा. पासवान चाहते हैं कि लालू की तरह नीतीश को हटाने का श्रेय भी उनको ही मिले. इसलिए उन्होंने ना–नुकुर करते करते पार्टी कार्यकर्ताओं व जनभावनाओं का ख्याल रखते हुए ख़ुद को नीतीश के मुक़ाबले पेश करने का फ़ैसला किया. उनके इस फ़ैसले से पहली बार मुक़ाबले का मैदान तैयार हुआ है. देखना है, इस मैदान में आगे निकलने के लिए कौन कौन से दांव पेंच आज़माए जाते हैं.

feedback@chauthiduniya.com

दिल यहां जिस्म वहां

नौशाद आलम

लोजपा के ठाकुरगंज के विधायक नौशाद आलम अजीब उलझन में हैं. पिछले दिनों पार्टी से नाराज़ हुए तो विधानसभा अध्यक्ष को लिखकर दे दिया कि जदयू में शामिल होना है. पार्टी आलाकमान तक यह बात गई तो पटना से लेकर दिल्ली तक मनाने का दौर शुरू हो गया. मेहनत रंग लाई और नौशाद आलम ने ऐलान किया कि उनकी नाराजगी दूर हो गई है और अब वह जदयू में नहीं जाएंगे, लोजपा में ही रहेंगे. इसके मुतल्लिक एक पत्र उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष को लिखा. लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी. स्पीकर साहब ने व्यवस्था दी कि नौशाद आलम व प्रमोद कुमार सिंह ने जदयू में शामिल करने की जो अर्जी दी थी, उसे स्वीकार कर लिया गया है. इस तरह अब वे जदयू विधायक दल के सदस्य माने जाएंगे. स्पीकर की इस व्यवस्था के बाद तो नौशाद आलम को काटो तो ख़ून नहीं. वह करें तो क्या करें. स्पीकर से गुहार लगाई कि वह अपने फ़ैसले पर फिर से सोंचे. इसी बीच हाईकोर्ट में भी एक रिट याचिका दायर की गई है. उनके वकील राजकुमार ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष ने क़ानून को नज़रअंदाज़ कर जदयू में शामिल होने का फ़ैसला सुना दिया है. नौशाद आलम का कहना है कि हमें न्याय की उम्मीद है. लगता है कि स्पीकर साहब अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेंगे. रामविलास जी का साथ नहीं छोड़ूंगा. लोजपा में हूं और रहूंगा लेकिन स्पीकर साहब के फ़ैसले के बाद दिल तो लोजपा में रह गया पर जिस्म जदयू में चला गया है.

भूदान एवं बंदोबस्ती की भूमि को वापस हथियाने के लिए यहां के स्थानीय लोगों के साथ आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है.

ललित नारायण मिश्र की मृत्यु के पश्चात वित्तीय संकट का बहाना बनाकर इस योजना के साथ टालमटोल किया जाता है.

भूदान की भूमि पर भूमाफ़ियाओं का क़ब्ज़ा

नीरज कुमार सिंह

जैसे ही किशनगंज ज़िले को बिहार का पहला चाय उत्पादक ज़िला बनने का गौरव प्राप्त हुआ और बिहार भारत के चाय उत्पादक राज्यों की श्रेणी में शामिल हो गया, यहां के छोटे से बड़े किसान फ़सलों की खेती से बिमुख होकर चाय की खेती में लग गए. चाय के लिए उपयुक्त वातावरण को देखते हुए स्थानीय के साथ दूसरे प्रांतों के बड़े-बड़े घरानों के लोगों ने अनेकों तिकड़म लगाकर भूमि ख़रीदना प्रारंभ किया. इससे यहां की भूदान एवं बंदोबस्ती की भूमि भी उन बड़े लोगों के हाथों में चली गई और यहां के ग़रीब राजवंशी (पोलिया) एवं आदिवासी समुदाय के लोग भूमिहीन हो गए और दाने-दाने को तरसने लगे. आज इसी भूदान एवं बंदोबस्ती की भूमि को वापस हथियाने के लिए यहां के स्थानीय लोगों के साथ आदिवासियों ने मोर्चा खोल दिया है. मालूम हो कि टी बोर्ड के नियम के अनुसार चाय की खेती के लिए सरकार से एनओसी प्राप्त होना आवश्यक है. भूमि भूदान एवं बंदोबस्ती की नहीं होनी चाहिए. लेकिन स्थानीय अज्ञानता के कारण स्थानीय तो क्या पड़ोसी बंगाल एवं आसाम तक के लोग भूदान बंदोबस्ती एवं बिहार सरकार की भूमि को हथियाकर चाय की खेती कर रहे हैं और चाय पत्ती तोड़कर अपने राज्य ले जा रहे हैं. उधर, बिहार सरकार की स्थानीय चाय कृषकों के प्रति स्पष्ट नीति न रहने एवं टी प्रोसेसिंग यूनिट के अभाव में स्थानीय किसान पिछड़ रहे हैं और अपनी चाय पत्तियों को कौड़ियों के दामों में बेचने को विवश हैं. इससे इनकी आर्थिक स्थिति चरमरा रही है. एक अनुमान के अनुसार किशनगंज की लगभग 900 एकड़ भूदान एवं बंदोबस्ती की भूमि पर अवैध लोगों का क़ब्ज़ा है. भूदान की भूमि के संबंध में किशनगंज भूदान यज्ञ कमेटी के कार्यालय मंत्री बजीर खपा ने एक सूची चौथी दुनिया को सौंपी. जिसका विवरण इस प्रकार है-आलोक घोष, कुकुड़बाघी, ठाकुरगंज, नेताय मजुमदार कुकुड़बाघी, ठाकुरगंज, रविशंकर भट्ट, कुकुड़बाघी, ठाकुरगंज, बंशी जायसवाल, कुकुड़बाघी, ठाकुरगंज, युगल अग्रवाल, कुकुड़बाघी, ठाकुरगंज, राजकरण दतरी, सारोगोरा एवं कालीदास, पोठिया, राजु दतरी, सारोगोरा एवं कालीदास पोठिया, अंजली देवी, सारोगोरा, पोठिया, निमाई अराजी किस्मत, हपत्त्यािगच्छ (बंगाल), बिनोद महेश्वरी कालीदास चोपड़ा (बंगाल), सज्जन चौधरी गोहाटी आसाम. इस संबंध में जिलाधिकारी किशनगंज संदीप कुमार पुड्डलकुटी का कहना है कि अंचलाधिकारी को इस प्रकार की भूमि के सर्वे का कार्य सौंपा गया है. इसके बाद आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी. जबकि स्थानीय बुद्धिजीवियों एवं चाय कृषकों को कहना है कि सरकार टी प्रोसेसिंग यूनिट लगाए व कच्चुखोआ में बंद पड़ी यूनिट को चालू कराए तो किसानों की माली हालत भी सुधर जाएगी और बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व भी प्राप्त होगा.

ज़िलाधिकारी संदीप कुमार पुड्डलकुटी का कहना है कि अंचलाधिकारी को इस प्रकार की भूमि के सर्वे का कार्य सौंपा गया है, उसके बाद आवश्यक क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.

feedback@chauthiduniya.com

मोक्ष स्थली गया में आस्था का मेला

सुनील सौरभ

आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में व्यक्ति विशेष से लेकर सारा जमाना बदल गया है. बिहार का गया तो अब महानगर हो गया है. पहनावे से लेकर खानपान एवं रहन सहन सबकुछ बदलते दौर में बदल गया है, लेकिन सैकड़ों वर्षों से चली आ रही गयाजी में पितरों की मोक्ष प्राप्ति के लिए पिंडदान करने की परंपरा आज तक नहीं बदली है. कलयुग में धर्म कर्म के प्रति लोगों में रुचि कम होने और संस्कृति के नष्ट होने की बात कही जाती रही है, किन्तु त्रेता युग से गया में पितरों के लिए किया जाने वाला श्राद्ध और पिंडदान आज भी उसी रूप में हो रहा है, जिस रूप में त्रेतायुग में होता था. गया सनातन धर्मावलंबियों के लिए विश्व में मोक्षस्थली के रूप में विख्यात है. पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध के लिए काशी, प्रयाग और गया का उल्लेख विभिन्न धर्मग्रंथों में हैं. इसमें गया को शीर्ष माना गया है क्योंकि गया में ही सनातन धर्मावलंबी स्वयं का श्राद्ध कर सकते हैं. गौ हत्या से निवारण के लिए यहीं श्राद्ध करने का विधान है. वैसे तो साल भर यहां पिंडदान होता रहता है. तीर्थयात्री आते रहते हैं. प्रतिवर्ष पितृपक्ष के 15 दिनों के दौरान 5 से 8 लाख लोग पिंडदान और श्राद्ध करने यहां आते हैं. लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक केंद्र या राज्य सरकार ने इस मेले को राजकीय या राष्ट्रीय मेला घोषित करने का प्रयास नहीं किया है. यहां तक कि इस मेले से विख्यात गयाजी को धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित करने का प्रयास कभी नहीं किया गया. पितृपक्ष में देश-दुनिया के हिंदू धर्मावलंबी अपने पितरों को पिंडदान कर उनके प्रति आस्था जताकर आशीर्वाद प्राप्त करने गया जी आते हैं. आधुनिकता की अंधी दौड़ में अपनी परंपरा-संस्कृति को भूलने और बड़े बुजुर्गों को सम्मान से बेदखल करने के चलन वाले इस युग में भी प्रतिवर्ष गया में लगने वाला पितृपक्ष मेला हर किसी के लिए अद्भुत है.

ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में सारे पितर यहां आते हैं और अपने संततियों से पिंडदान की अपेक्षा रखते हैं. इस समय पितरों के रूप में जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय रहता है. इस दौरान देश ही नहीं विदेशों से भी हिन्दू पिंडदान करने गया आते हैं.

अपने पितरों से अप्रत्यक्ष रूप से संवाद-साक्षात्कार करने की अनोखी परंपरा है पिंडदान. कहा जाता है कि जो हिंदू धर्मावलंबी अपने पितरों के प्रति आस्था नहीं जताते हैं, उन्हें पितरों के श्राप का कोप भाजन बनना पड़ता है, लेकिन जो लोग अपने पितरों के प्रति सम्मान रखते हैं, गयाजी में पिंडदान करते हैं, उन्हें उन्नति, सुख समृद्धि और शांति की प्राप्ति होती है. इसी बात को ध्यान में रख कर पूरी दुनिया के सनातन धर्मावलंबी अपने पितरों को श्रद्धा समर्पित करने गया के पितृपक्ष मेले में लाखों की संख्या में आते हैं. इस वर्ष पितृपक्ष मेला 11 सितम्बर से लग रहा है. प्रत्येक वर्ष आश्विन महीने के कृष्णपक्ष, जिसे पितृपक्ष के रूप में जाना जाता है, का विशेष धार्मिक महत्व है. ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में सारे पितर यहां आते हैं और अपने संततियों से पिंडदान की अपेक्षा रखते हैं. इस समय पितरों के लिए पिंडदान के रूप में जो कुछ दिया जाता है वह सब अक्षय रहता है. इस दौरान देश ही नहीं विदेशों से भी हिन्दू पिंडदान करने गया आते हैं. ख़ासकर नेपाल, श्रीलंका, मारीशस, फीजी, गुयना, तिब्बत, म्यांमार, भूटान आदि देशों के हिंदू श्रद्धालुओं की भीड़ अधिक होती है. गया में पिंडदान कब से प्रारंभ हुआ, इसका कोई प्रामाणिक सबूत नहीं मिलता है किन्तु यहां के गया पाल पंडों का मानना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रम्हाजी ने यहां पिंडदान किया था और तभी से पिंडदान की परंपरा अभी तक निरंतर जारी है. प्राचीन काल में पिंडदान पूरे एक साल तक चलता था.

उस दौरान तीर्थयात्री 360 वेदियों पर खोया, जौ तथा गेहूं के आटे व बालू से बने पिंडों को दान किया करते थे. किन्तु अब सिर्फ विष्णुपद, अक्षयवट, फल्गु नदी, पुनपुन नदी, रामशिला, सीताकुंड, रामकुंड, ब्रम्हकुंड, बोधगया, धर्मारण्य, मंगलागौरी, काकबली, ब्रम्हयोनी, प्रेतशिला, गया सिर, वैतरणी सहित मात्र 45 वेदियां ही शेष बची हैं, जहां पिंडदान किया जाता है. पिंडदान का प्रारंभ पटना ज़िला स्थित पुनपुन घाट से होता है. पहले यहां पंडा जाकर पूजा कराते थे परंतु अब गया में ही यह रस्म पूरी की जाती है. पहले पिंडदान करने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही था परंतु 1985 से मिथिला के पंडितों ने स्त्रियों को भी पिंडदान करने का अधिकार दे दिया. अब स्त्रियां भी पिंडदान करती हैं. गया ज़िला प्रशासन की ओर से पितृपक्ष मेले को लेकर तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था के लिए होटलों, धर्मशालाओं, निजी आवासों को 300 से अधिक लाइसेंस जारी किए गए हैं. इसके अलावा स्कूलों में भी तीर्थयात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की गयी है. पितृपक्ष में आने वाले तीर्थयात्रियों को राशन-किरासिन के लिए भी जगह-जगह पर जनवितरण की दुकानें खोली गई हैं. बिजली-पानी की व्यवस्था के साथ स्ट्रीट लाइट को भी ठीक किया गया है. मेला क्षेत्र में नाले व गंदगी की सफ़ाई अभी तक पूरी नहीं हुई है. आस्था से सराबोर और परंपराओं से बंधे होने के कारण यहां आने वाले अधिकांश तीर्थयात्री सारी परेशानियों को झेलकर भी अपने पितरों की मोक्ष की कामना करते हैं, लेकिन यह बात भी कहने से नहीं चूकते हैं कि गया जी को हरिद्वार, पुष्कर तथा बोधगया की तर्ज पर विकसित करने की ज़रूरत है.

feedback@chauthiduniya.com

टॉयफाइड में विशेष परहेज की ज़रूरत : डॉ. शर्मा

डॉ. शर्मा

बरसात का मौसम बीमारियों का मौसम माना जाता है. हर उम्र के व्यक्ति मौसमी बीमारियों के इलाज के लिए चिकित्सकों के यहां नज़र आते हैं. ऐसी ही बीमारियों पर गया के प्रसिद्ध फिजिशियन डॉ. एस.पी. शर्मा से की गई बातचीत के ख़ास अंश प्रस्तुत है:-

बरसात के मौसम मे कौन-कौन सी बीमारी अधिक होती है, इसके क्या कारण हैं?

वैसे तो हर मौसम में सभी तरह की बीमारियों की शिकायत लेकर मरीज आते रहते हैं, लेकिन यह भी सच है कि बरसात के मौसम में कुछ बीमारी अधिक होती हैं. जैसे-टॉयफाइड, पारा टॉयफाइड, लू, मलेरिया, गैस्ट्रोटाईट, जॉन्डिस आदि. इन बीमारियों के होने का मुख्य कारण दूषित खान-पान, दूषित पेयजल का सेवन है. टॉयफाइड के मरीज़ के रसोई घर में खाने की चीजों को बिना हाथ साफ किए छूने से भी खाने के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक टॉयफाइड के कीटाणु चले जाते हैं.

इसके बचाव के क्या उपाय हैं?

लोगों को खान-पान में सतर्कता बरतनी चाहिए. लेकिन टॉयफाइड के मरीजों को विशेष परहेज की ज़रूरत है. गर्म खाना ही खाना चाहिए. खाने से पहले हाथ अच्छी तरह धो लें. टंकी, जलापूर्ति के नल के पानी को नहीं पिएं. फिल्टर का पानी या फिर पानी को गर्म कर लें. ठंडा होने पर साफ कपड़े से पानी को छान लें, तब पानी का सेवन करें. टॉयफाइड के मरीजों को दवा का विशेष डोज देना चाहिए. इसके साथ में एकोवा कैप्सूल/सीरप लें. डॉक्टरों की सलाह लेकर लिवोकॉन दवा का भी सेवन कर सकते हैं.

टॉयफाइड के अलावा साल भर किस तरह के मरीज़ आते हैं?

यक्ष्मा (टीबी) के मरीज़ अधिक आते हैं. इसका मुख्य कारण है, मगध प्रमण्डल में खेतीहर मजदूर तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले लोगों की संख्या अधिक है. आर्थिक विपन्नता के कारण ऐसे परिवारों के सदस्यों को सही भोजन नहीं मिल पाता है. टीबी के मरीज इस रोग को गंभीरता से नहीं लेते हैं. दवा भी छोड़-छोड़ कर खाते हैं. जिसके कारण यह रोग बहुत गंभीर हो जाता है. जिसे एमडीआर कहते हैं. जो एड्स से भी खतरनाक होता है. टीबी ठीक नहीं हो रही हो तो ऐसे मरीजों को एचआईवी का टेस्ट कराना चाहिए. टीबी के मरीजों को दवा का सेवन नियमित करना चाहिए. जिससे कि बीमारी को काबू में रखा जा सके.

सुनील सौरभ
feedback@chauthiduniya.com

चरित्रवान शिक्षक ही राष्ट्र को आदर्श युवा दे सकते हैं

शिक्षक दिवस पर विशेष

डॉ. अनिल सुलभ

स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि व्यक्ति के अंदर के दीप को प्रज्जवलित कर देना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है. मतलब यह कि व्यक्ति के ज्ञानचक्षु खुल जाएं और इसमें जीवन जीने की शाश्वत कला विकसित हो. वह जीवन के मूल्यों को समझ ले तथा कोई भी निर्णय लेने में वह स्वविवेक का प्रयोग कर सके. विवेकानंद जैसे महापुरूष वेदों में उल्लेखित तत्व-ज्ञान का आश्रय लेकर यह बात सदैव दोहराते रहे कि शिक्षा अर्थात विद्या से विनय की प्राप्ति होती है. यह मनुष्य को सदाचरण और सद्व्यवहार के लिए प्रेरित करती है. स्वस्थ, सुखी और शांतिपूर्ण जीवन के साथ उन्नति और यश प्राप्ति के यही आधार-तत्व हैं.

किन्तु आज क्या इस प्रकार की शिक्षा हम दे पा रहे हैं? क्या आज जिस महापुरुष (भारत के द्वितीय किन्तु अद्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली डा.राधा कृष्णन) की जयंती के पुण्य अवसर पर पूरा राष्ट्र शिक्षक-दिवस मनाता है, क्या अब ऐसे शिक्षक हैं जो विद्यार्थियों में ज्ञान की ज्योति फैलाने में सक्षम हों? क्या हम ज्ञान और चरित्र निर्माण की कोई भी पाठशाला बना पाए हैं? तो फिर हम किस प्रकार के भ्रष्टाचार मुक्त चरित्रवान युवकों का भारत बनाने का स्वप्न देख रहे हैं? क्या हम डॉ. राधा कृष्णन के बताए मार्ग पर एक कदम भी बढ़ा सकें ? तो यह उनकी आत्मा को संताप देना नहीं है? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं, जिनका उत्तर देने में राष्ट्र को और विलंब नहीं करना चाहिए. विगत वर्षों में हमने बहुत कुछ खो दिया. अब भी यदि नहीं चेते तो संभवत: देश को प्रगति की पटरी पर लाना अत्यंत दुष्कर हो जाएगा. व्यक्ति और देश की आर्थिक उन्नति हो. जीने के लिए भौतिक संसाधन, वैज्ञानिक प्रगति, तकनीकी उन्नति और प्रबंधन शिक्षा भी आवश्यक है. किन्तु धन-उगाही ही जीवन का मुख्य ध्येय बन जाए तो क्या मूल्यवान, गुणवत्तापूर्ण जीवन संभव है? संभवत: दुनिया का कोई भी व्यक्ति इसका उत्तर हां में नहीं देना चाहेगा. दुर्भाग्य से आज भारत के नौजवान इसी अंधी दौड़ में झोक दिए गए हैं. युवा कर्मियों पर व्यवसायिक संस्थाओं की ओर से बड़े-बड़े लोभ देकर लाभ के बड़े-बड़े लक्ष्य थोपे जाते हैं. इन मायावी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमारे युवा किसी भी हद तक जाकर अपनी नैसर्गिक ऊर्जा को नष्ट करते हुए बड़ी-बड़ी ठगी का हिस्सा तक बनते जा रहे हैं. उनकी जवानी न स्वयं उनके लिए, न समाज के लिए और न राष्ट्र के ही काम आ रही है. हम लालच लोभ देकर पूरी की पूरी पीढ़ी को भ्रष्ट बनाते जा रहे हैं. जिस प्रकार से भी संभव हो, धन-प्राप्त करने के उद्देश्य में हमारी शक्तियां नष्ट हो रही हैं.

मेरी दृष्टि में धन पाने के लिये हम बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं. चरित्र खोकर धन पाना, पश्चिम की संस्कृति हो सकती है, हमारी नहीं. पश्चिमी देशों का संपूर्ण समाज आज इसकी कीमत भी चुका रहा है. हर प्रकार की विलासता की चीजों की उपलब्धता के बीच भी वहां के लोग अशांति और मृत्यु-तुल्य मानसिक अवसाद में जी रहे हैं. हम अपने युवकों को यह समझा पाने में सर्वथा असमर्थ हो चुके हैं कि चरित्र की रक्षा करते हुए भी आर्थिक उन्नति कर सकते हैं. सम्मान पूर्वक खुशहाल जीवन जी सकते हैं. बहुत पुरानी बात भी नहीं हैं. मध्यकाल में जब संपूर्ण भारत मगध-साम्राज्य के झंडे के नीचे एक था और इसकी राजधानी पाटिलिपुत्र (आज के बिहार की राजधानी पटना) में थी, उस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था. यह भी कहा जाता था कि इस देश में दूध की नदियां बहती हैं. इस काल में पाटिलिपुत्र को दुनिया का सबसे सुंदर और समृद्ध नगर माना गया था. लगभग 14 वर्षों तक यह नगर राजधानी की हैसियत रखता था, जिसमें से लगभग 9 सौ वर्ष ऐसे थे, जब इसके नेतृत्व में वह अखंडित भारत था, जिसका विस्तार आज के भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ 75 प्रतिशत अफ़ग़ानिस्तान तक था. जो छोटे-छोटे देश स्वतंत्र अस्तित्व रखते हैं, जैसे नेपाल, भूटान, मलेशिया, थाइलैंड आदि, ये सब तब भारत की सीमा के भीतर थे. ग्रीक के राजदूत मेगस्थनीज ने तथा चीनी यात्री ह्वेन सांग और फाहियान ने भी इस नगर को दुनिया का श्रेष्ठतम नगर कहा था. उनकी मानें तो पाटिलिपुत्र में चारों तरफ खुशहाली थी. सभी घर समृद्ध थे और नगर के घरों में ताले नहीं लगाये जाते थे. अविश्वसनीय लगने वाली उपरोक्त सूचना एक ख़बर भर नहीं है. इससे सिद्ध होता है कि नगर में लोकप्रिय शासन व्यवस्था थी. चारों तरफ खुशहाली थी. कोई भी इतना ग़रीब नहीं था, जिसे खाने को न मिलता हो. कहने की आवश्यकता नहीं कि इस काल में मानव-संसाधन और इसके निर्माण के उपायों पर अधिक कार्य किए जाते थे. योग्य मनुष्यों का निर्माण प्रथम प्राथमिकता में हुआ करता था. क्योंकि योग्य व्यक्तियों से ही चतुर्दिक उन्नति संभव है. इस सारस्वत वैदिक अवधारणा पर तत्कालीन प्रबुद्ध समाज आचरण करता था. शासन-तंत्र भी प्रबुद्ध और गुणीजनों की इच्छा और सुझाव का सम्मान और अनुपालन करता था. आज हम पश्चिमी संस्कृति की भोंड़ी नकल के क्रम में अपना चरित्र भूलकर ज्ञान का अर्थ धन कमाने का औजार समझने लगे हैं.

शिक्षा नीति में बराबर हुए प्रयोगों ने भी इस दिशा में नकारात्मक स्थिति उत्पन्न की है. यदि हम शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन चाहते हैं तो हमें अपनी प्राथमिक-शिक्षा को मज़बूत और प्रभावकारी बनाना होगा. आज हमें कक्षाओं में भाषण देने वाले व्याख्याताओं और प्राध्यापकों की नहीं, गुणी और चरित्रवान शिक्षकों की आवश्यकता है. बच्चों का कोमल मन आदर्श की जिज्ञासा में रहता है. वह अपने गुरुजनों का अनुसरण करना चाहता है. हम पहले जैसे शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं. जब हम योग्य शिक्षक नहीं दे पा रहे हैं तो योग्य छात्र की अपेक्षा भी नहीं कर सकते. आज प्राय: यह सुनने को मिलता है कि आज के लड़के अनुशासनहीन हो रहे हैं. अपराध-कर्म में लिप्त हो रहे हैं. मैं यह मानता हूं कि विद्यार्थी बुरे नहीं होते. हम स्वयं बुरे हो गए हैं. हम कक्षाओं में समय पर नहीं जाते. छात्रों को ठीक से नहीं पढ़ाते. अपनी कमाई के लिये छात्र-छात्राओं को ट्यूशन के लिये प्रेरित और कभी-कभी बाध्य करते हैं. राग-द्वेष की भावना से उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करते हैं. नकल करने की छूट देकर छात्र-छात्राओं को चरित्रहीन और भ्रष्ट बनाते हैं और सोचते हैं कि विद्यार्थी अनुशासन में भी रहे और शिक्षकों की चरण-वंदना भी करता रहे. वहीं छात्र उपेक्षा और असंतोष का शिकार होकर जब रोष व्यक्त करता है तो हम कहते हैं कि आज के लड़के बुरे हो गए हैं. सरकारें भी इस दिशा में कारगर कदम उठाने के स्थान पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का कार्य कर रही हैं. बिहार के मुख्यमंत्री ने इस दिशा में चार क़दम और आगे बढ़कर, बिहार की प्राथमिक शिक्षा को लगभग ध्वस्त ही कर दिया है. प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति में जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसने बिहार की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था की चूलें हिला दी हैं. हज़ारों की संख्या में अयोग्य व्यक्तियों की शिक्षक के रूप में नियुक्तियां हुई हैं. ऐसे अशिक्षित और भ्रष्टाचार के माध्यम से आए कथित शिक्षक किस प्रकार के मानव-संसाधन तैयार करेंगे, इसकी कल्पना मात्र से डर लगता है.

चारों तरफ शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसको लेकर स्वाभाविक रूप से चिंतनशील समाज में चिन्ता व्याप्त है. इस दिशा में सरकार और प्रबुद्ध समाज को गंभीरता से विचार करना होगा. शिक्षक-समुदाय को अपने आदर्श शिक्षक सर्वपल्ली डॉ. राधा कृष्णन के बताए मार्ग पर चल कर आदर्श शिक्षक बनने का संकल्प लेना चाहिए. तभी हम विवेक संपन्न युवाओं का संस्कारवान मानव संसाधन विकसित कर सकेंगे. और तभी भ्रष्टाचार मुक्त प्रगतिशील भारत का स्वप्न पूरा होगा. इस वरेण्य महापुरुष और आदर्श शिक्षक के प्रति भी यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी.

feedback@chauthiduniya.com

सकरी-हसनपुर रेल लाइन अधर में लटकी है

विकास कुमार

राज्य की लंबित रेल परियोजनाओं में से एक सकरी-हसनपुर रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा न होने से उत्तर बिहार एवं मिथिलांचल के लोगों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है. 74 किमी. लम्बी इस रेल लाइन के निर्माण कार्य उद्घाटन दो-दो रेल मंत्रियों ने किया था, लेकिन अब यह हवा-हवाई साबित होकर रह गया है. उत्तर बिहार में सबसे पहले 1874 ई. में तत्कालीन शासन ने बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य चलाने हेतु चमथा-दरभंगा तक लाइन बिछाकर गाड़ियों का परिचालन चालू करवाया था.

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 1 मई 1969 ई. को समस्तीपुर में रेलमंडल की स्थापना हुई. बता दें कि उत्तर बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने करने, कोसी एवं करेह की प्रलयंकारी बाढ़ से बचाव तथा आम लोगों को आवागमन की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र ने 74 किमी लंबी इस रेल लाइन निर्माण कार्य का उद्घाटन 22 फरवरी 1974 को किया था. इस प्रस्तावित रेल लाइन के निर्माण कार्य हेतु गोरखपुर से इंजीनियर लगाए गए थे. अभियंताओं ने हसनपुर-कुशेश्वरस्थान और सकरी में शिविर लगाकर रेल लाइन निर्माण की सारी प्रक्रियाएं पूरी की थीं. इस कार्य में केंद्र सरकार के तकरीबन 12 लाख रुपये ख़र्च हुए व सकरी-हसनपुर रेल लाइन के निर्माण हेतु पांच करोड़ 95 लाख रुपये स्वीकृत भी किए गए, लेकिन ललित नारायण मिश्र की मृत्यु के पश्चात वित्तीय संकट का बहाना बनाकर इस योजना के साथ टालमटोल किया जाता रहा. प्रस्तावित रेल योजना को पूरा करने के सिलसिले में सकरी और हसनपुर के बीच आठ रेलवे स्टेशनों के निर्माण के लिए स्थल का चयन भी किया गया था. चयन किए गए स्टेशनों के नाम हैं- कौराही, कुशेश्वर स्थान, हरिनगर, जीबछघाट, बिरौल, नेड़री, बेनीपुर और जगदीशपुर. इतना कार्य होने के बाद भी केंद्र में जो भी नई सरकार बनी, वह साधन का अभाव बताकर इस योजना को रद्दी की टोकरी में डालती रही. इसके पश्चात मिथिलांचल के सपूत होने का गौरव प्राप्त करने वाले पूर्व रेल मंत्री रामविलास पासवान ने अपने मंत्रित्व काल में वर्ष 1996 में इस रेल लाइन निर्माण का दोबारा शिलान्यास हसनपुर उच्च विद्यालय, हसनपुर के प्रांगण में किया था. क्षेत्र के लोगों में आशा की एक नई किरण जागी कि लंबित रेल परियोजना का निर्माण कार्य अब शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा. पूर्व रेल मंत्री पासवान ने इस रेल निर्माण कार्य योजना का कार्य प्रारंभ किये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की भी स्वीकृति दी थी. 15 साल व्यतीत होने के बावजूद भी सकरी से हसनपुर रोड रेल परियोजना के तहत बिरौल से हसनपुर तक रेल पटरी नहीं बिछ सकी है. राजनीति की धुरी माने जाने वाले रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव एवं नीतीश कुमार रेल मंत्री पद को सुशोभित कर चुके हैं. इनके अलावा भी रेल मंत्री के रूप में बिहार के ही केदार पांडे एवं राम सुभग सिंह रह चुके हैं फिर भी मिथिलांचल की अति महत्वपूर्ण योजना अधर में लटकी हुई है.

ललित नारायण मिश्र

रामविलास पासवान

रोसड़ा संसदीय क्षेत्र के तत्कालीन सांसद रामभगत पासवान ने वर्ष 1985 के सत्र में रेलवे संशोधन विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए कहा था कि सकरी-हसनपुर नई रेल लाइन के सर्वेक्षण कार्य पर सरकार द्वारा लाखों रुपये ख़र्च किए गए, लेकिन उत्तर बिहार की करोड़ों जनता की मांग को नकारते हुए वर्षों से इसे लंबित रखा गया है. उन्होंने उस समय सरकार को प्रतिमाह 22 लाख रुपये प्रतिमाह नुकसान होने की चर्चा की थी. इसी तरह पूर्व सांसद व मंत्री दशई चौधरी ने भी पूर्व रेल मंत्री जार्ज फर्नांडिस को स्मार-पत्र देकर इस परियोजना को पुन:जीवित करने की मांग की थी. पूर्व सांसद एवं दलित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र पासवान ने भी इस ओर केंद्र सरकार एवं रेलमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उल्लेखित किया था कि इसके निर्माण से लोगों को कम पैसे और कम समय में पूर्णिया, सहरसा, मधेपुरा, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर ज़िलों के साथ राज्य के अनेक स्थानों का संबंध स्थापित हो सकेगा, लेकिन यह योजना कब पूरी होगी, कोई नहीं जानता.

feedback@chauthiduniya.com

सर्व शिक्षा अभियान का हाल बेहाल

देवघर

देवघर ज़िले में राज्य शिक्षा परियोजना अपने उद्देश्यों के विपरीत और मनमाने तरीके से चल रही है. यहां सर्व शिक्षा अभियान के नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं. पिछले दो तीन वर्षों में राज्य सरकार की ओर से करोड़ों रुपये की पठन-पाठन सामग्री, कम्प्यूटर, टेलीविजन, रेडियो सहित कई आवश्यक सुविधा विद्यालयों को दी गईं, परन्तु पदाधिकारियों व परियोजना कर्मियों के ग़ैर ज़िम्मेदराना कार्यों से आज अधिकांश विद्यार्थियों को पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है. ज़िले के विद्यालयों में बच्चों को मिलने वाले मध्याह्न भोजन में लापरवाही आम बात हो गई है. विद्यालय भवन निर्माण में प्राक्कलन व सरकारी नियमों का घोर उल्लंघन किया जा रहा है. विद्यालय भवन निर्माण के स्थल चयन से लेकर निर्माण कार्य कराने तक ग्रामीणों की पूरी सहमति नहीं रहने के कारण पदाधिकारियों व ग्रामीणों के बीच टकराव भी हो रहा है. भवन निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग करने का मामला भी उजागर होता रहता है. ज़िले के दर्जनों विद्यालय ऐसी जगहों पर बनाए गए हैं, जहां से आबादी काफ़ी दूरी पर है. इससे बच्चों की उपस्थिति सिर्फ़ नामांकन पंजी तक ही रह गई है. सरकार ने विद्यालयों को प्राकृतिक आपदा जैसे वज्रपात से बचाव के लिए तड़ित चालक लगाने हेतु लाखों रुपये ख़र्च किए लेकिन आज शायद ही ज़िले के एक चौथाई विद्यालयों में तड़ित चालक लगा हो. विद्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार तड़ित चालक लगाने में घटिया सामग्री व निम्न स्तरीय नियम अपनाए गए, जिसमें ज़िले के विभागीय पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है. विभाग को रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ़ काग़ज़ों पर आंकड़े मिलाए जाते रहे हैं. मध्यान्ह भोजन हेतु खाद्यान्न की मात्रा हो या अन्य सुविधा प्राप्ति के लिए नामांकन पंजी में विद्यार्थियों के फ़र्ज़ी नाम भरे जाने के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं. हाल के दिनों में पालाजोरी प्रखंड अंतर्गत एक विद्यालय परिसर में विद्यार्थियों को दी जाने वाली किताबों को जलाने का मामला काफ़ी चर्चित रहा. वैसे ज़िले के अधिकांश विद्यालयों के बच्चों को पूरी किताबें शायद ही मिली हों. सरकार की ओर से बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक विद्यालयों में कम्प्यूटर आपूर्ति की गई थी परन्तु आज शायद ही बच्चों को कम्प्यूटर पढ़ाई की सुविधा मिली है. उधर, ज़िला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र कुमार अपनी तारीफ ख़ुद ही करते नहीं थकते. ज़िले के सर्व शिक्षा अभियान की सर्वाधिक दुर्गति वर्तमान ज़िला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र कुमार के ही कार्यकाल में हुई है. विभागीय सूत्रों के अनुसार, शिक्षकों के पदोन्नति, स्थानान्तरण आदि मामलों में जिला शिक्षा अधीक्षक शिवेंद्र कुमार का विवादास्पद निर्णय चर्चा में रहा है. ज़िले के कई शिक्षकों की ओर से जातिवादी भेदभाव करने का आरोप भी लगता रहा है. ऐसी हालत में ज़िले के नौनिहालों का भविष्य ईश्वर के हाथ में ही है, कारण कि ज़िले के उच्चाधिकारी सहित विभाग के राज्यस्तरीय पदाधिकारी भी आंख पर पट्टी बांध किसी एक और महाभारत होने के इंतजार में हैं. यह भी कहा जा सकता है कि किसी ज़माने में विद्या अर्जन का पवित्र मंदिर कहा जाने वाला विद्यालय आज सिर्फ़ काग़ज़ी विवरण पूरा करने के साथ साथ ठेकेदारी का केंद्र बन चुका है. जिसमें गांव के कुछ दबंगों एवं शिक्षकों के गठजोड़ से सरकार के पैसे को जमकर लूटने की योजनाएं बनती रहती हैं और फ़र्ज़ी बिल के ज़रिए आवंटित राशि डकारी जा रही है.

रणजीत झा
feedback@chauthiduniya.com

विद्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, तड़ित चालक लगाने में घटिया सामग्री व निम्नस्तरीय नियम अपनाए गए. इसमें ज़िले के विभागीय पदाधिकारियों की भूमिका संदिग्ध रही है. विभाग को रिपोर्ट करने के लिए सिर्फ़ काग़ज़ों पर आंकड़े मिलाए जाते रहे हैं. मध्यान्ह भोजन हेतु खाद्यान्न की मात्रा और अन्य सुविधा प्राप्ति के लिए नामांकन पंजी में विद्यार्थियों के फ़र्ज़ी नाम भरे जाने के कई मामले प्रकाश में आ चुके हैं.